आरोप पत्र

कांग्रेस राज के पांच बछर
छत्तीसगढ़ हो गे तितर-बितर

कटघरे में कांग्रेस

छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ
आरोप पत्र

भावपूर्ण
श्रद्धांजली

बाधाएँ आती हैं आएँ।
घिरे प्रलय की घोर घटाएं,
पावों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसे यदि ज्वालाएँ,
निज हाथों में हँसते-हँसते,
आग लगाकर जलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता

भारत रत्न

श्रद्धेय स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी

को समस्त छत्तीसगढ़वासियों की ओर से

शत्-शत् नमन...

आह्वान

छत्तीसगढ़ को महतारी कह,
कुछ पंजों ने इसको लूटा है,
प्रभु राम के ननिहाल में बैठा,
ये मारीच भी झूठा है..
हीरा कोयला लोहा सब,
हमारी महतारी का गहना है,
पंजों ने सब कुछ बेच दिया,
जो छत्तीसगढ़ महतारी ने पहना है..
जहां शबरी ने बेर खिलाए,
वहाँ ये पंजे कमीशन खा रहे,
छत्तीसगढ़ महतारी के खजाने को,
ये दिल्ली दरबार में लुटा रहे...
आज युवा खड़े हैं सड़कों पर,
ना रोटी है ना रोजगार है,
गाय मर रही भूखी प्यासी,
गोठान में सिर्फ़ भ्रष्टाचार है..
पंजों की नापाक पकड़ से,
बहन-बेटियाँ भी कहाँ बच पायी,

सड़कें बिक गई कमीशन में,
अपराध की बलि चढ़ गया भाई...
भत्ता खा गये खनिज खा गये,
छत्तीसगढ़ की हर चीज खा गये,
फिर भी इनका पेट नहीं भरता है,
छत्तीसगढ़िया मर भी जाए,
पंजों को फर्क नहीं पड़ता है..
उठो जागो निश्चय करो,
हे वीर नारायण की संतानों,
अपने भीतर गुण्डाधुर के,
रक्त की शक्ति को पहचानों...
हे गुरु घासीदास के वीर पुत्रों,
हमें सुन्दरलाल शर्मा का
सपना सजाना है,
छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में,
कमल का फूल चढ़ाना है,
अब छत्तीसगढ़ को बचाना है,
इसीलिए भाजपा सरकार बनाना है..

श्री आशुतोष सुरेंद्र दुबे

संदेश

जनहित में प्रिय नागरिकों के लिए,

मैं अरुण साव भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

छत्तीसगढ़ हमारे राष्ट्र के नैसर्गिक संसाधनों से समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ बड़े पहाड़ों से लेकर प्राकृतिक सम्पदा से भरी हुई कोयले और एल्युमीनियम की खदानें हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर हमेशा से भारतवर्ष का एक अग्रणी प्रदेश बनने की क्षमता रही है। आदरणीय अटल जी ने इसके सामर्थ्य को पहचानते हुए इसका एक आत्मनिर्भर राज्य के रूप में निर्माण किया। लेकिन पिछले पांच वर्षों में पहले कांग्रेस सरकार बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में तो आई, पर सत्ता के मद में जनता को ही भूल गई। एक ऐसा प्रदेश जो शांति की प्रतिमूर्ति समझा जाता था उसे कांग्रेस सरकार ने हिंसा, अशिक्षा, बेरोजगारी, माताओं बहनों की असुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लाचारी के अंधे कुएं में धकेल दिया, जिससे छत्तीसगढ़ के विकास और उसकी प्रकाश ज्योति पर अंधेरा छा गया है। भ्रष्टाचार और घोटालों की आग में छत्तीसगढ़ की प्रगति की जड़ें खोखली हो गई हैं। ₹ 2,000 करोड़ का शराब घोटाला, ₹ 1,300 करोड़ का गौठान घोटाला, ₹ 5,000 करोड़ का राशन घोटाला जैसे कई घोटालों ने छत्तीसगढ़ के विकास के पहियों को जाम कर दिया है।

इस आरोप पत्र के माध्यम से हम कांग्रेस सरकार का लेखा-जोखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आदरणीय नागरिकों, आप सभी से अपील है कि आप भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ आवाज उठाएं और सच्चाई की ओर बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ को विकास की ऊंचाइयों तक पहुँचाने में योगदान करें। आपके सहयोग से हम छत्तीसगढ़ को फिर से समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं।

धन्यवाद,

अरुण साव
प्रदेश अध्यक्ष
भाजपा छत्तीसगढ़

संदेश

हमारा छत्तीसगढ़, वो राज्य जिसके लिए दशकों तक राज्य के स्वप्नद्दष्टा रहे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी और डॉक्टर खूबचंद बघेल जी पृथक राज्य की मांग को लेकर संघर्ष करते रहे और कांग्रेस की सरकारें हर बार उन्हें निराश करके वापिस लौटाती रहीं।
फिर सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के क्षेत्रवासियों की भावनाओं को समझा और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की घोषणा संसद में की और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर 15 साल तक विश्वास दिखाया। यह 15 साल छत्तीसगढ़ के लिए विकास का स्वर्णिम कालखंड था जिसमें एक नए बने राज्य में अनेकों चुनौतियों के बीच, जब छत्तीसगढ़ की छवि बीमारू राज्य और एक पलायन करने वाले राज्य की बनी हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिन-रात समर्पित कर छत्तीसगढ़ के लिए सुदृढ़ विकास और अंत्योदय पर आधारित सर्वांगीण हितैषी नीतियां निर्मित की। 1 रुपये किलो चावल की योजना से लेकर सड़कों का जाल बिछाने और शिक्षा के प्रसार से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं बढाने तक भाजपा की सरकार ने डेढ़ दशक छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की है।

फिर 2018 में कांग्रेस ने झूठे वादों, फरेब और प्रलोभन से रचित एक घोषणा पत्र तैयार किया और गीता और गंगाजल की कसम खाकर छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनता को ठग कर उनसे वोट हासिल किए। आज इस दुर्घटना को 5 साल पूरे होने आए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता उस छल को भूली नहीं है, किस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं को शराबबंदी के नाम पर, युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को पेंशन के नाम पर, किसानों को बोनस के नाम पर, आदिवासियों को लुभावने वादों के नाम पर और पूरे प्रदेश को यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम और विकास जैसे झूठे दावों के नाम पर धोखा दिया है। आज 5 साल बाद कांग्रेस की यह स्थिति है कि ना तो यह अपना पुराना घोषणा पत्र जनता को दिखा सकती हैं और ना ही नया घोषणा पत्र बनाने के लिए जनता के बीच जा सकती हैं।

पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़वासियों के लिए भले ही कुछ नहीं किया लेकिन प्रदेश के भ्रष्टाचारियों और कमीशनखोरों के लिए सुनहरे दरवाजे जरूर खोल दिए हैं।
15 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ की पहचान एक विकास आधारित राज्य के रूप में बनाई थी लेकिन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने विकसित हो रहे छत्तीसगढ़ की छवि ED और CD वाले प्रदेश की निर्मित कर दी है।

पिछले 5 सालों में कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीडीएस घोटाला, गौठान घोटाला, यहां तक की महादेव एप के जुआँ-सट्टा में भी सरकार की भागीदारी और भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ चुका है। कांग्रेस की सरकार ने यह बड़े-बड़े भ्रष्टाचार करके सिर्फ छत्तीसगढ़वासियों के साथ छल ही नहीं किया है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की छवि को कलंकित करने का भी काम किया है। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति यह हो चुकी है कि 5 साल में छत्तीसगढ़ के लिए “भ्रष्टाचार का अड्डा” “नशे का कॉरिडोर” और “अपराधियों के लिए संरक्षित स्थान” जैसे शब्द उपयोग किये जाते हैं।

कांग्रेस की यह सरकार छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर लूटने में इस तरह व्यस्त है कि उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है। प्रदेश की जनता से किए गए वादे कांग्रेस पूरी तरह भूल चुकी है और आज गांव-गरीब-किसान, युवा और महिलाएं समेत सभी वर्ग इस सरकार से प्रताड़ित हैं। किसान बेबस है और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा की स्थिति इस हद तक खराब हो चुकी है कि स्कूलों में ना तो शिक्षक है और ना बिल्डिंग। 5 सालों में छत्तीसगढ़ में अगर कुछ बनाया गया है तो सिर्फ एक चेहरे को चमकाने के लिए प्रचार के बैनर और पोस्टर बने हैं।

साथियों, अब समय आ चुका है कि इस झूठी और भ्रष्ट कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर बाहर किया जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास आधारित एक ऐसा छत्तीसगढ़ निर्मित किया जाये जिसकी परिकल्पना हमारे आदर्श पुरुषों ने की थी क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस के हाथ में ताकत रहेगी तब तक यह भ्रष्टाचारियों को समर्थन देती रहेगी। अब छत्तीसगढ़ की जनता को यह निर्णय करना है कि उन्होंने प्रदेश में 15 साल का जो विकास का कालखंड देखा है, वह सरकार चाहिए या फिर भ्रष्टाचार, घोटालों और अपराधियों को संरक्षण देने वाली 5 साल की यह लुटेरी सरकार चाहिए?

धन्यवाद,

डॉ रमन सिंह
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा
पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

संदेश

लोकनायक और यशस्वी नेता अटलजी ने दलगत भावना से ऊपर उठ कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण बड़े मन से किया था। राज्य निर्माण के पीछे सोच यही थी कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान हो, सबके चेहरे पर मुस्कान हो। इसी भावना से पिछली सरकार ने काम भी किया और विकास के अनेक नए कीर्तिमान गढ़े। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि अटल जी के उस सपने पर कुठाराघात करने का काम प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है।

बड़े-बड़े वादों के कारण 2018 में प्रदेश के निर्माण के बाद पहली बार चुन कर आयी कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ जैसा छल किया है, लोकतंत्र में धोखाधड़ी की जैसी मिसाल कायम की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, वैसा उदाहरण स्वतंत्र भारत के इतिहास में दूसरा कोई खोजने पर भी नहीं मिलेगा। अपने जन घोषणा पत्र की मर्यादा को तार-तार करते हुए कांग्रेस ने लोकतंत्र पर अविश्वास का संकट पैदा कर दिया है।

साफ नीयत से किसी राजनीतिक दल द्वारा किए वादों में से एकाध का किसी मजबूरीवश पालन नहीं हो पाना अलग बात है, किंतु यह सोच कर ही बड़े-बड़े वादे करना कि उन्हें पूरा नहीं करना है, ऐसा अमर्यादित आचरण है जिसकी कोई भी सजा कम होगी। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपनी अधिकतर घोषणाओं को जानबूझ कर पूरा तो नहीं ही किया, अनेक मामलों में तो वादे का ठीक उलट किया।

गंगाजल हाथ में लेकर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया लेकिन शराब कि शासकीय होम डिलीवरी की, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला किया, किसानों के हित की बड़ी-बड़ी बात कर उसे मिट्टी-गिट्टी को वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर खरीदने को विवश किया, गौठान के नाम पर ही हजारों करोड़ का घोटाला किया, केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे चावल में भी ₹ 5,000 करोड़ से ऊपर का गबन किया, छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने के उलट तमाम राज्यसभा सीटें दस जनपथ को समर्पित कर दी। कांग्रेस के ऐसे सैकड़ों कृत्य एक सांस में गिनाए जा सकते हैं जिसे करके भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मिंदा किया है।

तमाम प्रचारों के उलट शासन की शर्मनाक विफलताओं का मीनार खड़ा किया हुआ है इस सरकार ने। शराब घोटाला, सीमेंट-कोल-आयरन पैलेट्स आदि में अरबों का घोटाला, चावल घोटाला, गौठान घोटाला, पीएससी नियुक्ति घोटाला समेत ऐसा कोई भी विभाग, कोई भी योजना नहीं बची है जिसे दस जनपथ के भूख की भेंट न चढ़ा दिया गया हो। लगातार प्रदेश को लूटने में ही सारा ध्यान लगा देने का दुष्परिणाम आज प्रदेश भुगत रहा है। विधानसभा में दिए जवाब के अनुसार ही प्रदेश में 39 हजार से अधिक छत्तीसगढ़िया बच्चे चिकित्सा के अभाव में दिवंगत हो गए। एक हजार किसान और दस हजार से अधिक युवा समेत 36 हजार छत्तीसगढ़ियों ने गहन निराशा में आत्महात्या कर ली। 90 हजार से अधिक बेटियां कहां गायब हो गयी इसका कांग्रेस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

एक सशक्त विपक्ष के रूप में हमने लगातार तमाम लोकतांत्रिक मंचों पर कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों के विरुद्ध आवाज उठाते हुए अपने दायित्वों का पालन किया है। अब जबकि पुनः जनादेश का समय आ गया है, तब यह आरोप पत्र प्रस्तुत कर हम जनता जनार्दन से कांग्रेस के अपराधों की कड़ी से कड़ी सजा देने का निवेदन करते हैं।

धन्यवाद,

नारायण चंदेल
नेता प्रतिपक्ष
छत्तीसगढ़ विधानसभा

आमुख

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर सदियों से उपेक्षा झेल रहे छत्तीसगढ़ को पहचान और सम्मान दिया। छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2003 से 2018 तक भाजपा के नेतृत्व में विकास के नये सोपान तय किए पर आज की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के समृद्ध इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत को कलंकित कर भ्रष्टाचार और माफियाओं का अड्डा बना दिया है।

छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2003 से 2018 तक भाजपा के नेतृत्व में विकास के नये सोपान तय किए पर आज की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के समृद्ध इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत को कलंकित कर भ्रष्टाचार और माफियाओं का अड्डा बना दिया है।

माता कौशल्या की जन्मभूमि और भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश में राम वन गमन पथ बनाने, गौमाता की गोबर खरीदी, गौ मूत्र खरीदी, नरवा गरुवा घुरवा-बारी के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। गौमाता के गोबर खरीदी के नाम पर अरबों रुपयों का भ्रष्टाचार किया है। भौरा, गिल्ली-डंडा, पिट्ठूल, गेड़ी, बॉटी, खो-खो, कबड्डी आदि हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है और पूरे देश में अलग-अलग नाम से खेले जाते हैं। "बोरे-बासी" का आदिकाल से हिंदुस्तान, खास तौर पर छत्तीसगढ़ में जन-सामान्य के भोजन में विशेष स्थान रहा है "पुत्री स्नान" छत्तीसगढ़ सहित देश की हर पवित्र नदी में पौराणिक काल से आयोजित होता आ रहा है। भाजपा सरकार ने राजिम से इस परंपरा को सम्मान दिया।

प्रदेश के बहुरूपिया (मुख्यमंत्री) छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराने के नाम पर "राजीव गांधी मितान क्लब" का गठन कर करोड़ों रुपयों की खैरात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाँट रहे हैं। हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ की महान संस्कृति और परंपरा से कांग्रेस का कोई नाता नहीं रहा है और मात्र इसके बाजारीकरण को छत्तीसगढ़ियावाद का जामा पहनाकर ढोंग रचा जा रहा है।

ज्ञात इतिहास के हर दौर में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरगुजा, कांकेर और रायगढ़ के सिंघनपुर, कबरा पहाड़ के लगभग 30,000 वर्ष पूर्व के पाषाणयुगीन भित्ति चित्र, महाभारत और रामायण काल से लेकर वर्तमान में सिरपुर जहां भगवान बुद्ध आये (अवदान शतक के अनुसार), ताला, मल्हार का स्थापत्य, बारसूर भगवान गणेश की विश्व में विशालतम प्रतिमा, दंतेवाड़ा की 15 दिनों की फागुन मड़ई, बस्तर के घोटुल की स्वच्छंद, स्वतंत्र और अनुशासित जीवन शैली, जशपुर का सरहुल (सरना प्रकृति की पूजा), नाचा तथा करमा, गौर नृत्य से सुशोभित है और यह वास्तविक छत्तीसगढ़ की महान संस्कृति है।

आज हम सबको मिलकर छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार, माफिया, नशा और अपराध से मुक्त करा कर एक विकसित राज्य बनाना है, यही छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी।

महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि और भारतीय दर्शन में उनका योगदान, राजा चक्रधर का नृत्य संगीत, खैरागढ़ में एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय, हबीब तनवीर का लोकनाट्य, सूरजबाई खांडे, झाराम देवांगन, देवदास बंजारे, दाऊ मन्दराजी, रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासिंह, जयदेव बघेल जैसी इन महान विभूतियों के योगदान से राउत नाचा जैसे लोकनृत्य और भरथरी, पंडवानी, बांसगीत, सुवानृत्य जैसे लोकगायन एवं लोककला जैसे डोकरा शिल्प, बेल मेटल, बांस शिल्प आदि समृद्ध हुआ। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला और सबसे विशालकाय गणेश प्रतिमा छत्तीसगढ़ में है।

ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास (श्यामास्वप्न हिन्दी - का पहला उपन्यास), बाबू रेवाराम, कोदूराम दलित, सत्यदेव दुबे, डॉ. शंकर शेष, बंशीधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे (हिन्दी साहित्य में छायावाद के जनक), पंडित बलदेव प्रसाद मिश्रा, हीरालाल काव्योपाध्याय, डॉ॰ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी (सरस्वती के दो बार संपादक), मुक्तिबोध, लाला जगदलपुरी, हरि ठाकुर जैसे महानुभावों ने छत्तीसगढ़ की महान साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्ना पंडित सुन्दरताल शर्मा ने इस गौरवशाली राज्य की नींव रखी है।

पिछले पाँच वर्षों में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की महान सांस्कृतिक, साहित्यिक और लोक कला को सिर्फ नष्ट करने का काम किया और उनका संरक्षण करने के बजाय राजनीतिकरण करते हुए धर्म और संस्कृति के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाली देश की पहली सरकार बन कर पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिया।

विगत 9 वर्षों में भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास के नये आयाम तय कर विश्व पटल में अपना विशेष स्थान बना रहा है। सदियों से क्षीण हो चुकी प्राचीन काल की प्रभुता और प्रतिष्ठा को फिर से अर्जित करते हुए आज समूचे विश्व के सामने भारत एक आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि जब देश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है तब हमारा राज्य छत्तीसगढ़ बद से बदतर होता जा रहा है। बढ़ते भ्रष्टाचार, अपचार और अपराध की वजह से प्रदेश का सर शर्म से झुका जा रहा है।

आज हम सबको मिलकर छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार, माफिया, नशा और अपराध से मुक्त करा कर एक विकसित राज्य बनाना है, यही छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भागीरथ प्रयास किये उसमें यहां की सरकार का उचित सहयोग न मिल पाने की वजह से विकास में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। विकास की गति से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार तालमेल नहीं बैठा पा रही है। अगर केंद्र के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार होगी तो आमूलचूल परिवर्तन होगा।

आइये माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब अपने आप को छत्तीसगढ़ के नव निर्माण के लिए समर्पित करें।

भारत माता की जय... छत्तीसगढ़ महतारी की जय....

कटघरे में कांग्रेस

आरोप पत्र

भूपेश बघेल एक नजर में

लबरा के डबरा

• राजनैतिक उत्पत्ति	-	(नकली) बी फार्म से
• कर्ज़दार हूं	-	राहुल का
• दरबारी हूं	-	प्रियंका का
• प्रशंसक हूं	-	रेहान का
• यार हूं	-	खड़गे का
• वादों में	-	शेखचिल्ली हूँ
• बरगलाने में	-	लबरा हूँ
• प्रशासन में	-	सौम्य हूँ
• मंत्रियों में	-	मिश्री भैय्या हूँ
• दोस्तों में	-	ढेबर हूँ
• विधायकों में	-	देवइन्द्र हूँ
• स्वर में	-	संगीत हूँ
• व्यापारियों में	-	रामगोपाल हूँ
• खेलों में	-	नंगी दौड़ हूँ
• कर्ज़ लेने में	-	माल्या हूँ
• प्रदेश को लूटने में	-	सहारा श्री हूँ
• कार्यकर्ता में	-	विजय हूँ
• आदमियों में	-	शकुनि हूँ
• नेताओं में	-	दुर्योधन हूँ
• रिश्तों में	-	कंस हूँ
• भोजन में	-	पैसा हूँ
• द्रव में	-	शराब हूँ

कहिस बहुत- करिस कुछू नही

लबरा भूपेश के लबारी

• रिटायर्ड लोगों को संविदा नियुक्ति नहीं देना	-	दे रहे है
• स्टार्ट-अप नीति एयर एंबुलेंस	-	नहीं किया
• मुफ्त गैस सिलेंडर	-	नहीं चली
• मंडी टैक्स	-	नहीं हटाया। डबल कर दिया
• छात्रों को साइकिल	-	नहीं दिया
• किसानों को 2 साल का बोनस	-	नहीं दिया
• संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण	-	नहीं
• आउटसोर्सिंग बंद	-	नहीं
• कक्षा 12वीं तक मुफ्त शिक्षा	-	नहीं
• लाइट मेट्रो	-	नहीं
• फिल्म सिटी	-	नहीं
• ऐरोसिटी	-	नहीं
• वर्ल्ड लेवल स्कूल (विश्व स्तरीय स्कूल)	-	नहीं
• होलसेल कॉरीडोर	-	नहीं
• वर्धा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सेवा ग्राम	-	नहीं
• शहीद स्मारक	-	नहीं
• अमर जवान ज्योति	-	नहीं
• श्री राम जी थ्री-डी व्यू	-	नहीं
• जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क	-	नहीं
• रीपा- रुरल इंडस्ट्रीयल पार्क	-	नहीं
• विवेकानंद स्मारक	-	नहीं
• खैरागढ़ विश्वविद्यालय का रायपुर में ऑफ कैम्पस	-	नहीं
• हर ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग यूनिट	-	नहीं
• खारून रिवर फ्रंट	-	नहीं

मैं गंगाजल के कसम
खावत हवं कि कभू
शराबबंदी करे बर
गंगाजल के कसम
नई खाए हंव !
वाह रे
झुठलबरा !

जनघोषणा पत्र पर धोखा

ठग भूपेश, लबरी कांग्रेस

लगातार तीन चुनाव हार चुके छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव (2018) से पहले हताश हो कर जनता को भटकाने के लिए कई झूठे वादे किये थे। वैसे तो कांग्रेस ने कुल 316 वादे किये थे, लेकिन उनके नेता प्रमुख 36 वादों पर भी किये गए काम का ब्यौरा नहीं दे पाते हैं। उपमुख्यमंत्री कहते हैं 12 पूरे हुए, प्रवक्ता कहते हैं 34 हुए, किसी को नहीं पता क्या-कितना हुआ है। सत्य तो यह है की इन 36 में भी, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। अन्य 280 वादों पर तो कांग्रेस नेता आज बात करने से भी कतराते है। उन्हें खुद भी नहीं पता की क्या-क्या वादे किये थे। इन 280 अन्य वादों की सूची में प्रदेश की हर माँ को प्रतिमाह ₹ 500 देने और हर 5 सदस्य के भूमिहीन परिवार को आवास के लिए भूमि देने जैसे वादे शामिल हैं। नरवा, गरुवा, घुरवा, बारी का नारा लगाने वाले कांग्रेस के लोगों ने नाले के विकास के लिए कभी काम किया ही नहीं, कांग्रेस सरकार सिंचाई के क्षेत्र में भी फिसड्डी रही, गरुवा के अंतर्गत हुआ ₹ 1,300 करोड़ का घोटाला, गायें गौठान में हैं ही नहीं और बारी तो सरकार ने बनवाई ही नहीं। जन घोषणा पत्र आज उनके झूठे, ठग और धोखेबाज होने का सबसे बड़ा प्रमाण बना हुआ है।

कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए : योगेश

भारतीय जनता पार्टी मंडल मैनपुर द्वारा मंगलवार को प्रत्येक शक्ति केंद्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से जनसंपर्क कर कांग्रेस सरकार के ढाई वर्ष पूर्ण होने पर इसे कांग्रेस सरकार की विफलता व जन घोषणा पत्र पर किये गये वादों को झूठा बताते हुए छत्तीसगढ़ की जनता को छले जाने की बात कही।

Nai Dunia News Network
Updated Date: | Wed, 16 Jun 2021 06:51 AM (IST)
Published Date: | Wed, 16 Jun 2021 06:51 AM (IST)

छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब विपक्ष ने पूछा, घोषणा पत्र के कितने वादे हुए पूरे? बघेल बोले- हम जल्द पूरा कर लेंगे जब...

Chhattisgarh Legislative Assembly: नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और शिवरतन शर्मा ने कहा कि जवाब नहीं आ रहा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आपने सवाल पूछा है, जवाब मुझे देना है. मैं किस तरह से

छत्तीसगढ़ विधानसभा में घोषणा पत्र 2018 के वादों को पूरा किए जाने का मामला सदन में उठा और सदन में जमकर हंगामा हुआ

परेशान किसान

मिल नहीं रहा किसानों को सम्मान, विफल रहा हर प्रयास
लबरा से त्रस्त किसान खा रहा सल्फास

- यह सरकार किसानों के दम पर ही बनी और 5 साल में किसानों का दम ही निकाल दिया। प्रदेश के किसानों का कर्ज़ माफ करने, सिंचाई क्षमता दोगुना करने और धान का दो साल का बोनस देने का वादा अब तक अधूरा है। ये हाल तब है जबकि इस सरकार ने किसान के नाम पर दुनिया भर की संस्थाओं से अथक कर्ज़ लिया है। काफी सम्भावना है की इन कर्ज़ों से मिला पैसा भी कांग्रेसी खा गए हों। दीर्घकालीन कर्ज़ और निजी बैंकों के हर प्रकार के कर्ज़ एक सीमा तक ही माफ किये गए, जबकि अपने जन घोषणा पत्र में सभी तरह की कर्ज़माफी का वादा किया गया था।
- केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार धान खरीदी कर रही है, जिसका एक-एक पाई भाजपा की केन्द्र सरकार देती है। भूपेश सरकार तो पांच साल में सभी किसानो का पंजीकरण भी नहीं कर सकी। आज भी छत्तीसगढ़ के लगभग 20 लाख अपंजीकृत किसान हैं जिनको धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता।
- भूपेश सरकार ने किसानों पर प्रशासनिक अत्याचार किये हैं। खेत का रकबा गिरदावरी के नाम पर कम कर दिया, बारदाने की व्यवस्था नहीं की और न ही पैसा लौटाया, तौलाई में गड़बड़ी की और वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर प्रति एकड़ 30 बोरी मिट्टी और कंकड़ खरीदने को मजबूर किया। खेती के लिए खाद, बीज पर भी कांग्रेस सरकार ने माफ़िया राज चलाया।

परेशान किसान

मिल नहीं रहा किसानों को सम्मान, विफल रहा हर प्रयास
लबरा से त्रस्त किसान खा रहा सल्फास

- प्रदेश सरकार द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सहकारी सोसाइटी का जो सहकार्य का भाव है, उसे समाप्त कर और सोसाइटी एक्ट, 1960 का भी उल्लंघन कर अपात्रों की मनोनयन से नियुक्ति की गई है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा सोसाइटी अध्यक्षों, दुग्ध सह महासंघ, राज्य सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंक में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव न कराते हुए कांग्रेसी चमचों को ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बना दिया गया है। मंडी में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को ताक पर रख कर मनोनयन किया गया है।
- किसानों की बिजली बिल तो सरकार वसूल रही है, लेकिन वहीं पर स्टील प्लांटों के बिजली बिल को 25% माफ कर दी और वह लगभग ₹ 650 करोड़ की राशि प्रदेश के उपभोक्ताओं से वसूली जा रही है, जिसमें किसान भी शामिल है जिसे दूसरा पंप लगाने पर कोई छूट नहीं मिलती। किसान उद्योगपतियों से भी ज्यादा धनवान है, ऐसा भूपेश सरकार का मानना है।
- 28 लाख किसानों का पंजीयन होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार को सत्यापित कर नहीं भेजा गया, जिससे वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित रहें। इस सरकार की किसान विरोधी कुनीतियों के कारण पिछले 56 महीनों में 1,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है।

घोटालेबाज सरकार

कांग्रेस सरकार, भ्रष्टाचार की गारंटी

प्रदेश में ₹ 1 लाख करोड़ से भी अधिक का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस सरकार ने आम जीवन दुश्वार कर रखा है। शराब घोटाला, चावल घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, यूरिया घोटाला, वन विभाग घोटाला, गौठान घोटाला, डीएमएफ घोटाला, शिक्षक भर्ती-तबादला घोटाला जैसे और कई घोटाले कर प्रदेश और अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेला है। प्रदेश का जितना पैसा कांग्रेस ने इन घोटालों में गबन किया है उसमे 40 लाख गरीबों को पक्की छत मिल जाती, 25,00,00,000 मानक बोरा तेंदूपत्ता का भुगतान हो जाता, 6,000 से भी ज्यादा फूड पार्क बन जाते, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में डिजिटल सुविधा हो जाती। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक परिवहन, सिंचाई और स्वास्थ्य से जुडी ना जाने कितनी समस्याओं का हल हो जाता। लेकिन अपनी और कांग्रेस पार्टी की जेबें भरने के चक्कर में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के विकास को ठप कर दिया।

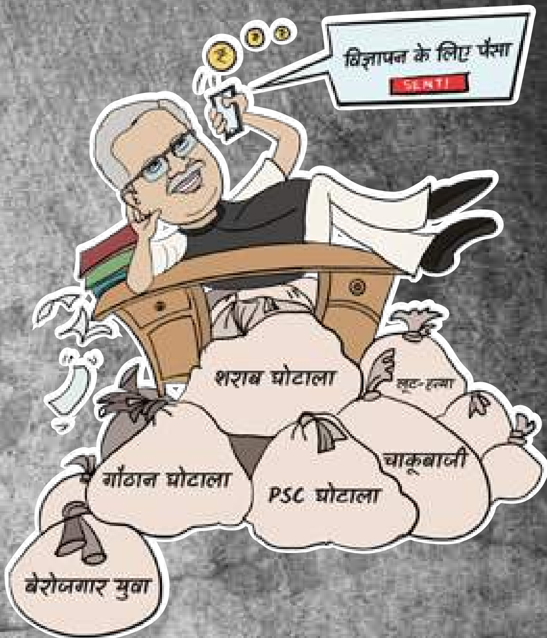

सियासत: रमन बोले- सिद्ध हो गया 250 करोड़ का चावल घोटाला, CM भूपेश खाद्य मंत्री का इस्तीफा लेंगे या बचाएंगे

अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Sat, 27 May 2023 03:35 PM IST

सार

छत्तीसगढ़ में इन दिनों चावल घोटाला, शराब घोटाला, गोठान घोटाला और यूनीपोल घोटाला आदि पर जमकर राजनीति हो रही है। मामले में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने चावल घोटाला को लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार को घेरा है।

छत्तीसगढ़ में इन दिनों चावल घोटाला, शराब घोटाला, गोठान घोटाला और यूनीपोल घोटाला आदि पर जमकर राजनीति हो रही है। मामले में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने चावल घोटाला को लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार को घेरा है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: नौकरशाहों और नेताओं ने की 2161 करोड़ की हेराफेरी, ईडी ने दाखिल किया आरोपपत्र

सार

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मंगलवार को विशेष अदालत में 13 हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। ईडी के अनुसार सभी आरोपी एक सिंडिकेट चला रहे थे। इनकी भ्रष्ट गतिविधियों से 2019-23 के बीच सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

'छत्तीसगढ़ में 1300 करोड़ का गौठान घोटाला': BJP ने कहा- बिहार के चारा घोटाले की तर्ज पर हो CBI जांच

सार

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने गौठानों के नाम पर 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के चारा घोटाले की तर्ज पर ही इस गौठान घोटाला की जांच सीबीआई से कराई जाए। साव ने दो टूक शब्दों में कहा कि गौ माता के नाम पर कांग्रेस की भ्रष्ट प्रदेश सरकार ने बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला किया है।

विस्तार

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने गौठानों के नाम पर 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के चारा घोटाले की तर्ज पर ही इस गौठान घोटाला की जांच सीबीआई से कराई जाए। साव ने दो टूक शब्दों में कहा कि गौ माता के नाम पर कांग्रेस की भ्रष्ट प्रदेश सरकार ने बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला किया है।

तेंदू पत्ता खरीदी में घोटाला

भूपेश कब तक आदिवासियों पर करोगे अत्याचार तेंदू पत्ता खरीदी में भी किया करोड़ों का भ्रष्टाचार

वनोपज की उचित मूल्य पर खरीदी की डींगें हांकने वाली कांग्रेस सरकार ने तेंदू पत्ता में भी करोड़ों का घोटाला कर आदिवासियों को लगातार 4 वर्षों से बोनस से भी वंचित रखा है। तेंदू पत्ता में दिये जाने वाले बोनस को संग्राहकों तक ना भेजकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी जेबें भर ली हैं। कांग्रेस सरकार ने तेंदू पत्ता संग्रहण की अवधि को कम करके मात्र एक-दो दिन कर आदिवासियों के साथ धोखा किया है। इससे तेंदू पत्ता संग्रहण में भारी कमी आई है। 5 साल में लगभग ₹ 1,000 करोड़ की खरीदी ही कम कर दी गई है। 5 साल में एक भी बार लक्ष्य के बराबर खरीदी नहीं की गई है। जहां 2017 में 17 लाख मानक बोरा संग्रहण हुआ था, वहीं 2021 में यह घट कर 13 लाख ही रह गया। भाजपा द्वारा संग्राहकों के कल्याण के लिए शुरू की गई बीमा, छात्रावास, चरण पादुका एवं साड़ी वितरण जैसी योजनाएं भी बंद कर दी गई हैं।

तेंदूपत्ता पर सियासत: पूर्व मंत्री बोले-14 लाख संग्राहक, संग्रहण 10.65 लाख, बाकी कहां; कांग्रेस बोली- निराधार

...ने कहा कि, जिले में मानक से 66 फीसदी ...नक बोरा की कम खरीदी हुई है। आरोप ...प्रशासन ने जानबूझ कर बीजापुर में ...कर यहां के आदिवासी संग्राहकों का 32 ...किया है।

...फोटो : संवाद

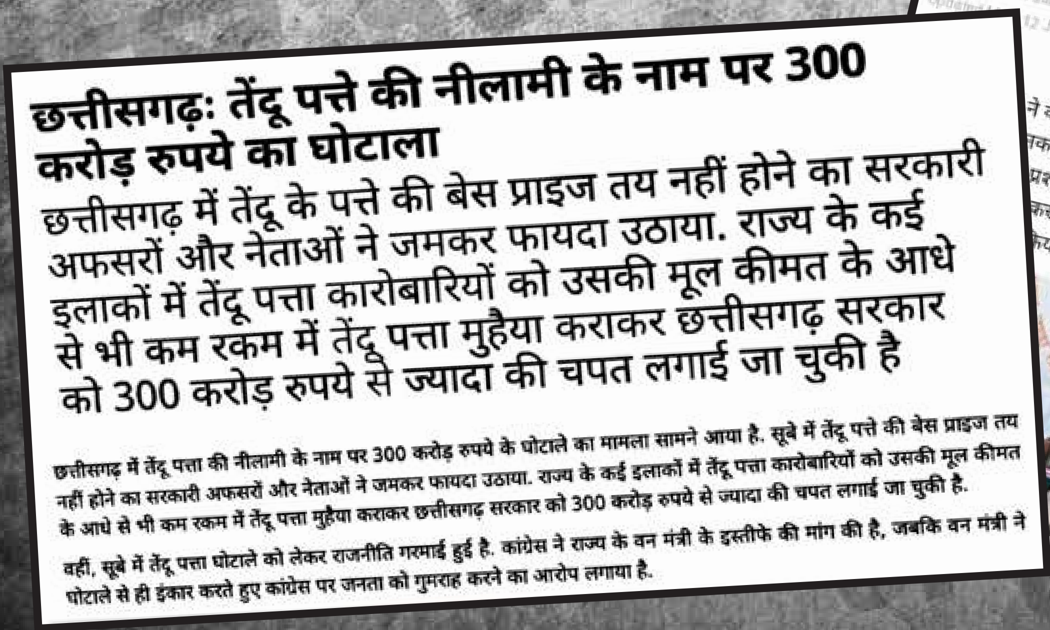

छत्तीसगढ़: तेंदू पत्ते की नीलामी के नाम पर 300 करोड़ रुपये का घोटाला

छत्तीसगढ़ में तेंदू के पत्ते की बेस प्राइज तय नहीं होने का सरकारी अफसरों और नेताओं ने जमकर फायदा उठाया. राज्य के कई इलाकों में तेंदू पत्ता कारोबारियों को उसकी मूल कीमत के आधे से भी कम रकम में तेंदू पत्ता मुहैया कराकर छत्तीसगढ़ सरकार को 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की चपत लगाई जा चुकी है

छत्तीसगढ़ में तेंदू पत्ता की नीलामी के नाम पर 300 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है. सूबे में तेंदू पत्ते की बेस प्राइज तय नहीं होने का सरकारी अफसरों और नेताओं ने जमकर फायदा उठाया. राज्य के कई इलाकों में तेंदू पत्ता कारोबारियों को उसकी मूल कीमत के आधे से भी कम रकम में तेंदू पत्ता मुहैया कराकर छत्तीसगढ़ सरकार को 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की चपत लगाई जा चुकी है.

वहीं, सूबे में तेंदू पत्ता घोटाले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. कांग्रेस ने राज्य के वन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जबकि वन मंत्री ने घोटाले से ही इंकार करते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

16 लाख से अधिक गरीबों को नहीं मिला पक्का मकान

भूपेश सरकार ने गरीबों से छीना आवास, विकास के नाम पर कर रहा विनाश

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 16 लाख से अधिक घरों को भूपेश बघेल ने बनने नहीं दिया। कांग्रेस सरकार की गरीबों का घर बनाने की कोई नियत नहीं थी, तभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहाना बनाया की इस योजना में 'प्रधानमंत्री' शब्द जुड़ा है, इसलिए वे घर नहीं बनने देंगे। कांग्रेस सरकार के उपमुख्यमंत्री श्री टी एस सिंह देव ने तब इसी रवैये से त्रस्त होकर ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। प्रदेश में अनेक स्थानों पर अपने आवास की प्रतीक्षा करते-करते गरीबों की मौत तक हो गयी। कांकेर में ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की मृत्यु जर्जर घर के गिर जाने से हो गयी। वह परिवार भी आवास की प्रतीक्षा सूची में था और कांग्रेस सरकार के राज्यांश नहीं देने के कारण उसका घर नहीं बन पाया था।

आदिवासी वृद्धा को नहीं मिला पीएम आवास

पीएम आवास योजना में बन रहे मकान को तोड़े जाने की शिकायत

24 वर्ष से काबिज का इंदिरा आवास प्रशासन ने तोड़ा, परिवार हुआ बेघर

मलबा के ऊपर ही तंबू तानकर रहने के लिए मजबूर है परिवार

तुष्टीकरण/धर्मांतरण

आदिवासियों का शोषण कर रही भूपेश सरकार विकास के नाम पर किया धर्मांतरण का व्यापार

कांग्रेस सरकार आने के बाद तेजी से धर्मांतरण बढ़ रहा है। बस्तर के सुकमा के एसपी और बस्तर के ही कमिश्नर ने पत्र लिख कर धर्मांतरण के खतरे से आगाह किया, लेकिन कांग्रेस विधायक समेत सभी नेता मिशनरियों का समर्थन कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने खुद दिल्ली में मुलाकात कर खुलेआम समर्थन का ऐलान किया। बस्तर के विधायक चन्दन कश्यप ने मिशनरियों को सहयोग देने का सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया, जबकि मिशनरियों के कारण बस्तर जल रहा है। स्थिति विस्फोटक है और कांग्रेस इसे हवा दे रही है। रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध रूप से बसने के कारण कवर्धा में दंगे, बेमेतरा में लव जेहाद को बढ़ावा, नारायणपुर में आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प, बिरनपुर में तेली समाज के युवक की हत्या के बाद तनाव, अम्बिकापुर में रोहिंग्या आदि को बसाया जाना, रायपुर में मिशनरी आतंक और तिरंगा जलाने की धमकी का साथ देना कांग्रेस के अपराध में शामिल है।

प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद, पुलिस से झड़प, ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

दफनाये गये शव को निकलवाकर ग्रामीणों ने गांव से बाहर करवा दिया

जनजाति सनातनी पक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद पहुंचा प्रशासनिक अमला

समझाइश के बाद भी धर्मांतरित परिवार मानने को नहीं हुआ तैयार

दैनिक भास्कर

धर्मांतरण का सच बता रहे आदिवासी: बस्तर, सरगुजा में जनजातियों के घरों से हटवाई देवी-देवताओं की तस्वीरें, बीमारियां दूर करने के बहाने बदली मान्यताएं

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा सियासी मुद्दा है। ये मुद्दा भ... आज की तारीख में चर्चा में अधिक है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बीते 10-15 साल से धीरे-धीरे ये मुद्दा न ...र्फ प्रदेश के जंगली इलाकों में फला-फूला बल्कि बहुत से ...रसों में छा चुका है।

शराबखोर सरकार

था शराब घोटाले से पैसे कमाने का इरादा, सत्ता के नशे में भूल गए शराबबंदी का वादा

कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी के नाम पर भी छत्तीसगढ़ की जनता को खूब छला है। शराबबंदी की जगह शराब की होम डिलीवरी सेवा देकर, उसमें भी हर शराब दुकानों पर दो काउंटर रखते हुए ₹ 2,161 करोड़ का घोटाला कर लिया। न केवल शासकीय खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया, बल्कि नकली और घटिया शराब बेच कर छत्तीसगढ़ियों के जान और माल को भी अपूर्णीय क्षति पहुंचाई, हजारों घर उजाड़े, लाखों महिलाओं का जीना दूभर किया। घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना, कलह आदि के कारण नरक बना दिया छत्तीसगढ़ के जन-जीवन को। नकली शराब की तिजारत कर दस जनपथ का एटीएम बना दिया छत्तीसगढ़ को। गांधी परिवार के लिए आज्ञाकारी कलेक्शन मास्टर मात्र होकर रह गए सीएम भूपेश।

शराब 10 फीसदी तक महंगी होगी

राजस्व बढ़ाने 'अतिरिक्त आबकारी शुल्क' में वृद्धि

राज्य की नई मत्स्यपालन नीति को भी मंजूरी

थोक में तबादले पर मंत्रीमंडलीय उप समिति का गठन

नगर के नाबालिग नशे की आगोश में

नशे की लत पूरा करने ले रहे चोरी का सहारा

दिन में आवारा पशुओं, रात्रि में शराबियों का अड्डा बन जाता है आत्मानंद स्कूल

अव्यवस्थाओं के बीच संचालित हो रहा है भाटापारा का आत्मानंद इंग्लिश स्कूल

जागरूकता

जिले के तीनों ब्लॉक में 10-10 भारत माता वाहिनी समूह

मद्य निषेध के लिए भारत माता वाहिनी से जुड़ी महिलाओं ने उठाया बीड़ा

30 समूहों से जुड़ी हैं सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं, जागरूकता रैली निकालने के साथ ही लोगों को मद्य निषेध का दिला रही शपथ

चावल के कटोरे में सेंध

गरीबों की थाली में डाला डाका, चावल का पैसा खा गया लबरा कका

₹ 1 प्रति किलो की दर से प्रति परिवार 35 किलो चावल देने वाली छत्तीसगढ़ की पीडीएस व्यवस्था देश भर में पारदर्शिता की मिसाल थी, भूपेश सरकार ने इसमें भी ₹ 600 करोड़ गबन कर पीडीएस घोटाला किया और छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी इस व्यवस्था की साख पर धब्बा लगाया। आपदा में अवसर खोजते हुए कांग्रेस सरकार ने गरीबों की भूख के साथ भी भ्रष्टाचार किया है। इस सरकार ने कोरोना आपदा काल में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भेजे जा रहे गरीबों के चावल में भी ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का घोटाला कर लिया। आदिवासी क्षेत्रों में घटिया चावल का वितरण किया गया। कैग की रिपोर्ट में भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित अनेक योजनाओं में लगातार घोटाले की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री के दोहरे आचरण का हाल यह है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ वे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए घोटालों की शिकायत दिल्ली तक करते थे, वही अधिकारी आज इनकी लूट के हिस्सेदार बने बैठे हैं। अलग तरह के इस खाद्य घोटाले की जांच केंद्र सरकार का खाद्य विभाग कर रहा है।

सरकारी चावल खरीदने दलालों का ऑफर
35 किलो चावल देने पर 600 रु. और 6 कप ले जाओ

कलेक्टर ने राइस मिलर्स की ली समीक्षा बैठक, कहा- काम में तेजी लाएं
34 हजार एमटी चावल जमा करना बाकी

पीडीएस : एक रूपए किलो में चावल लेकर दलालों को बीस रूपए में बेच रहे हैं हितग्राही

पीएससी घोटाला

भूपेश ने पूरा नहीं किया रोजगार देने का वादा
पीएससी घोटाले से सामने आया कांग्रेस का इरादा

हाल ही में सीजीपीएससी-2021 के आये परिणाम में भाई-भतीजावाद करके, करोड़ों का भ्रष्टाचार करके युवाओं के सपनों को कुचला गया है। आयोग के चेयरमैन टामन सोनवानी के बेटे समेत अनेक कांग्रेसी रिश्तेदार इसमें चयनित हुए हैं। भाजयुमो ने इस भ्रष्टाचार को लेकर सीएम आवास घेराव का एक बड़ा आन्दोलन किया है। इस परिणाम के बाद किसी भी कोचिंग संस्था ने किसी सफल उम्मीदवार के लिए श्रेय नहीं लिया। कई पदों को कांग्रेस और उसके सिपहसालारों ने आपस में बांट लिया।

नो वैकेंसी • पीएससी वही परीक्षा लेगा, जिनके आवेदन पहले जारी

पीएससी और व्यापमं से तीन महीने भर्तियां नहीं होंगी, इनके जरिए नौकरी नवंबर तक

सरकारी विभागों की लापरवाही से राज्यभर के युवा हो रहे परेशान

नवंबर से जून तक 2 हजार पदों पर भर्ती

व्यापमं के 6 माह प्रवेश परीक्षा...

पीएससी ने दो पदों के लिए अलग अलग फीस लेकर भराए आवेदन पर परीक्षा एक ली, अब दो मेरिट लिस्ट पर सवाल

अनुपम सिंह | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की एक और परीक्षा विवादों में आ गई है। पीएससी ने फरवरी 2022 में खनिज विभाग में खनिज अधिकारी और सहायक भौमिकीविद के दो अलग- अलग पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। दोनों के लिए अलग-अलग आवेदन भराए गए, फीस भी अलग-अलग ली गई, लेकिन दोनों पदों के एक परीक्षा ली गई। अब इंटरव्यू के लिए पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी गई है। वहीं, नियमों की अनदेखी करते हुए कम अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएससी ने फरवरी 2022 को खनिज विभाग में खनिज अधिकारी, सहायक भौमिकीविद के 54 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। माइनिंग ऑफिसर के 8 और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के 11 पदों पर भर्ती होनी थी। बाकी 35 पद खनिज निरीक्षक के थे। माइनिंग ऑफिसर के 8 और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के 11 पदों के लिए अभ्यर्थियों ने अलग-अलग आवेदन और फीस जमा की। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से चयन होना था। लिखित परीक्षा के लिए 300 और इंटरव्यू के लिए 30 अंक तय किए गए थे। दोनों पदों के लिए अलग-अलग आवेदन और फीस जमा करने के कारण अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि परीक्षा भी अलग- अलग ली जाएगी।

दोनों पदों के लिए एक लिखित परीक्षा | पीएससी ने दोनों पदों के लिए एक लिखित परीक्षा ली। लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है। दोनों पदों के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट में समान अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं।

संचालनालय, छत्ती
ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भव
दूरभाष : 0771-2253808
ई-मेल : ifacg.cg@nic.in,

ऑनलाइन सट्टा को सरकारी संरक्षण

ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ रहे केस पर केस फर्जीवाड़े की रेस जीत रही कांग्रेस

पूरे प्रदेश में फर्जीवाड़े का स्टार्टअप चल रहा है। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों ने काले धन को सफेद करने महादेव ऐप से ऑनलाइन सट्टा का खेल रचाया। अभी तक बड़े लोगों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि वो लोग कांग्रेस और सरकार से जुड़े लोगों के रिश्तेदार हैं। रोज प्रदेश के लोगों को ऑनलाइन ठगा जा रहा है, पर सरकार इससे बिलकुल अनभिज्ञ होने का नाटक कर रही है। पूरे प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक लाख से ज्यादा मामले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने ज्यादा पैसों की वसूली करने के लिए केवल प्यादों को पकड़ के राजा को संरक्षण दिया है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बाकायदा विज्ञापन आदि देकर छत्तीसगढ़ियों का करोड़ों ठग लूट रहे हैं। कांग्रेस ने 50 लाख परिवारों को ऑनलाइन सट्टे की लत लगाकर आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया है। वास्तव में ठगी कांग्रेस का मूल चरित्र हो गया है।

Chhattisgarh: पति-पत्नी मिलकर चलाते थे साइबर ठगी का गिरोह, सेक्सटॉर्शन के अपराध में भी शामिल

Cyber Fraud: पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी से एक को गिरफ्तार किया है, वहीं मामले का मास्टर माइंड अ पत्नी के साथ फरार है जो वारदात को अंजाम देने के लि अपनी पत्नी के बैंक खाते का इस्तेमाल करता था

By: अभितेष पांडे, अम्बिकापुर
Updated at: Fri, May 19,2023, 5:36 pm (IST)

(पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार) (Image Source : अभितेष पांडे)

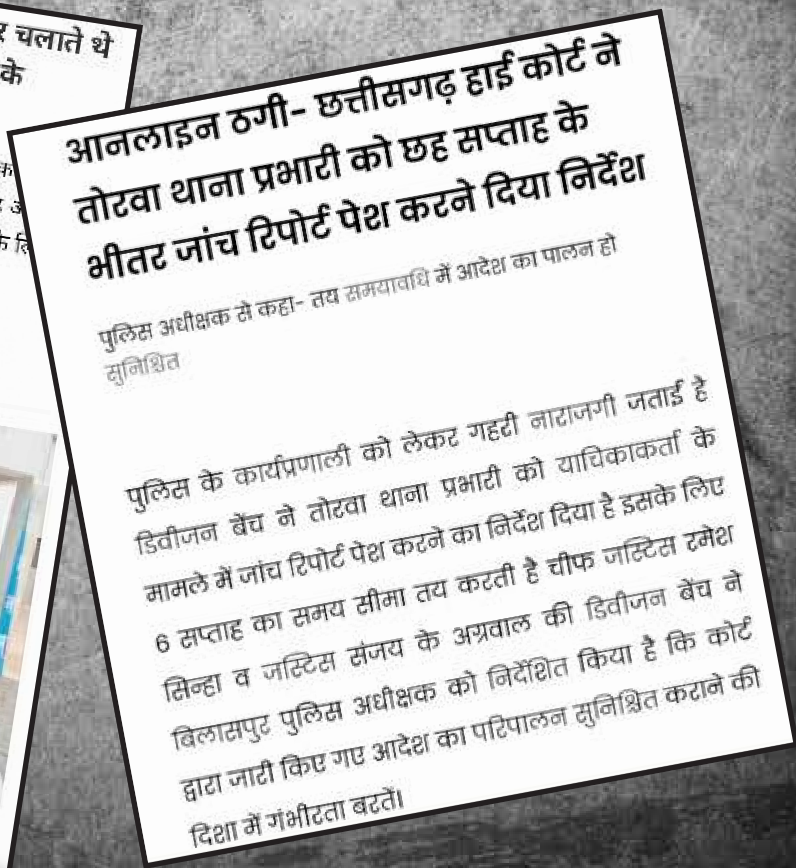

आनलाइन ठगी- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तोरवा थाना प्रभारी को छह सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने दिया निर्देश

पुलिस अधीक्षक से कहा- तय समयावधि में आदेश का पालन हो सुनिश्चित

पुलिस के कार्यप्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी जताई है डिवीजन बेंच ने तोरवा थाना प्रभारी को याचिकाकर्ता के मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है इसके लिए 6 सप्ताह का समय सीमा तय करती है चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश का परिपालन सुनिश्चित कराने की दिशा में गंभीरता बरतें।

कोयला परिवहन घोटाला

काली कमाई कर कलंकित हुई कांग्रेस
कोयला परिवहन का पैसा खा गया भूपेश

यह घोटाला भी हजारों करोड़ का है। शुरुआती तौर पर ईडी ने इसमें ₹ 540 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता लगाया है। संपत्ति अटैच किये गए हैं। इस घोटाले में मुख्यमंत्री की सबसे करीबी उप-सचिव सौम्या चौरसिया समेत अनेक अधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, दलाल आदि जेल में हैं। ऑनलाइन पास का नियम बदल कर, उसे ऑफलाइन कर देने के बाद यह घोटाला किया गया। कोयले में ₹ 25 प्रति टन की उगाही की गई। सीमेंट, आयरन पैलेट्स और रेत आदि में भी बड़े पैमाने पर धांधली की गयी है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन में धांधली के मामले में अदालत ने हाल ही में, 25 जुलाई 2023 को, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रहे विजय दर्डा और उनके बेटे देवेन्द्र दर्डा को कैद की सजा सुनाई है। कांग्रेस पार्टी के नेता सर से पैर तक कोयला भ्रष्टाचार में सालों से लिप्त हैं।

कोयले की जांच में अब तक 900 करोड़ की काली कमाई उजागर

यहां हुई कार्रवाई

रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा में कार्रवाई

कोयले के धंधे पर 4 जिलों में पड़े छापों में पकड़ी गई 300 करोड़ रु. की हेराफेरी

5 विभाग के अधिकारी छापे में शामिल थे

कोल वॉशरी, डिपो में 950 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई

■ छापे के पहले ही कई अहम दस्तावेज गायब या डिलीट

■ सौ से ज्यादा कोल डिपो, साइडिंग पर हुई कार्रवाई

जंगल-जंगल लूट मची है

जमीन ही नहीं जंगल में भी किया भ्रष्टाचार, वन विभाग के करोड़ों लूट गई भूपेश सरकार

अधिकारियों को मिली खुली छूट, वन विभाग में हो गई ₹ 4000 करोड़ की लूट। कांग्रेस सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विधानसभा में यह विषय उठने पर बताया कि अधिकारियों ने 37 टेंडर निकाले, जिनमें 33 में अनियमितता पाई गई। जिन्होंने अपना वोट देकर भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार बनाई, वह आदिवासी वर्ग भी कांग्रेस की लूट से बच नहीं पाए। वन अधिकार ग्राम पंचायतों से छीन कर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया और तो और पुनः विवेचना करवाने का अधिकार भी ग्राम पंचायतों से छीन कर उन्हें बिल्कुल लाचार बना दिया। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने जिन हसदेव अरण्य में संघर्ष कर रहे आदिवासियों से खुद मिलकर उनकी जमीन पर कोयला खनन रोकने का वादा किया था, कांग्रेस सरकार ने उन आदिवासियों को भी ठगा और बल प्रयोग करके उन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया है। सैकड़ों दिनों से धरने पर बैठे आदिवासियों को राहुल गाँधी अब चेहरा दिखाने भी नहीं जाते। एक ओर टी एस सिंह देव कहते थे कि आदिवासियों पर गोली चली, तो पहले वह सीने पर गोली खुद खाएंगे, लेकिन आज तो जंगल कट गए पर टी एस सिंह चुपके-चुपके उपमुख्यमंत्री बन गए।

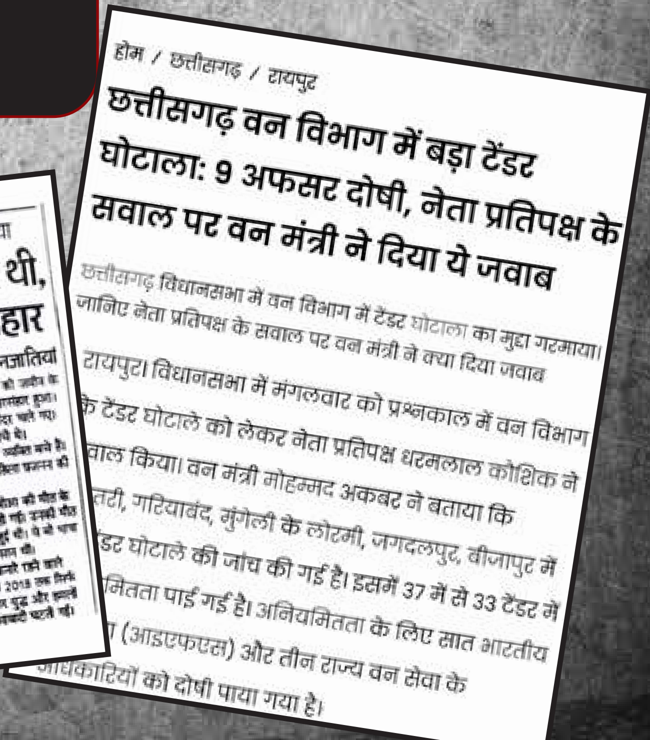

होम / छत्तीसगढ़ / रायपुर

छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा टेंडर घोटाला: 9 अफसर दोषी, नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर वन मंत्री ने दिया ये जवाब

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वन विभाग में टेंडर घोटाला का मुद्दा गरमाया। जानिए नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर वन मंत्री ने क्या दिया जवाब

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में वन विभाग के टेंडर घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने ...वाल किया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि ...टी, गरियाबंद, मुंगेली के लोरमी, जगदलपुर, बीजापुर में ...डर घोटाले की जांच की गई है। इसमें 37 में से 33 टेंडर में ...मितता पाई गई है। अनियमितता के लिए सात भारतीय ... (आइएफएस) और तीन राज्य वन सेवा के अधिकारियों को दोषी पाया गया है।

भास्कर खास • 'मैन ऑफ द होल' की मौत के साथ अमेजन के जंगलों की एक जनजाति का अंत हो गया

जनजाति के आखिरी इंसान ने 26 साल से किसी से बात नहीं की थी, जंगल की जमीन पर कब्जे के लिए किया गया था इनका नरसंहार

खतरे में कई और जनजातियां

गौठान घोटाला, सारा गुड़ गोबर कर दिया कांग्रेस ने

गौठान के नाम पर गायों का अपमान
जनता बंद करेगी भ्रष्टाचार की दुकान

गोबर की चोरी करने से भी बाज नहीं आई भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार। विधानसभा में ही इसके लूट का पर्दाफाश हो गया, जब ₹ 268 करोड़ के गोबर का हिसाब नहीं दे पाने के कारण रंगे हाथ पकड़े गए भूपेश बघेल। चारा घोटाले से भी बड़े करतूत को अंजाम देते हुए भूपेश सरकार ने प्रति गाय ₹ 39 लाख खर्च करने का दावा किया है। लबरा के डबरा के वादों में से एक वादा गौठान का भी था, जिसमें अभी तक के आंकड़े के अनुसार ही ₹ 1,300 करोड़ से अधिक की राशि का दुरूपयोग कर घोटाला किया है इस बेईमान सरकार ने। रोका-छेका के नाम पर विज्ञापनों तक में पैसा बहाया, लेकिन सड़कों पर हजारों गायों की वाहनों से मौत हुई है। गौशालाओं में सैकड़ों गायें भूख-प्यास से मरी हैं। इसमें गांव-गांव में बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर मिट्टी बेची गई और देख रेख के पैसे का गबन कर घोटाले किये गए हैं। ग्राम पंचायत की राशि, डीएमएफ, कैम्पा, 14वां वित्त, 15वां वित्त, मनरेगा जैसे मदों का जबरन दुरूपयोग कर यह घोटाला किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेशव्यापी निरीक्षण के क्रम में यह पाया कि कहीं भी गाय नहीं है या उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

डेढ़ माह से गोबर खरीदी बंद
तिल्दा जनपद पंचायत का मामला, पशुपालक परेशान

कांजी हाउस सह गौठान में भारी अव्यवस्था
पशुओं के लिए चारा का अभाव, कच्चा शेड फटकर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है

गोठान भूमि पर बेजा कब्जा, तीन वर्ष के बाद भी नहीं मिली अनुमति

रोका छेका अभियान जिले भर में असफल साबित हो रहा

सब गुड़ गोबर कर देने वाली कांग्रेस

आदिवासियों की गरीबी का उड़ा रही मज़ाक
भूपेश का शासन होकर रहेगा खाक

राज्य सरकार आदिवासी इलाकों में गुड़ और चना बाँट रही है। हालांकि, सरकार ने माना है कि सप्लायर ने खरीद ऑर्डर देने के बाद तय समय के भीतर गुड़ और चना उपलब्ध नहीं कराया है। इसी विषय पर कई बार आपूर्ति में भारी लापरवाही के साथ एक से दो महीने की देरी भी हुई है, फिर भी राज्य की कांग्रेस सरकार ने आपूर्तिकर्ताओं पर कोई कार्यवाही नहीं करते हुए किसी तरह का कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया। इसके अलावा राज्य में गुड़ और चने की गुणवत्ता को लेकर भी लगातार सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सीधे तौर पर राज्य सरकार ने इसमें भी खूब भ्रष्टाचार किया है।

गरीब परिवारों को अब बाजार से नमक और चना खरीदना होगा, अभी तक सप्लाई नहीं

20/08/19

गरीब परिवारों को अब बाजार से नमक और चना खरीदना होगा, अभी तक सप्लाई नहींगरीब परिवारों को एक सितंबर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नए तरीके से चावल शक्कर मिट्टी तेल के साथ ही चना...

गरीब परिवारों को एक सितंबर से सार्वज... के अंतर्गत नए तरीके से चावल, शक्कर मि... चना और नमक दिए जाने की बात कही जा... बस्तर जिले में आने वाले महीने में नमक और... फिर से नहीं मिल पाएगा। इन गरीब परिवारों को... खाद्य सामग्रियों के लिए बाजार से महंगे रेट पर ख... पड़ेगा।

पेनाल्टी कार्यवाही की गई: वेयर हाउस में अमानक मिला चना, ढाई साल पुराने केस में 2 लाख की पेनाल्टी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बांटे जाने वाले चना के अवमानक होने की शिकायत पर करीब ढाई साल बाद जांच रिपोर्ट पर 2 लाख रुपए की पेनाल्टी कार्यवाही की गई है। इसमें चना की पैकिंग तिथि के साथ चने की गुणवत्ता खराब पाए जाने की बात सामने आई है।

डीएमएफ घोटाला

काली कमाई से कांग्रेस का पंजा काला
भूपेश ने किया करोड़ों का डीएमएफ घोटाला

बड़े पैमाने पर इस फंड से रकम की बंदरबांट हो रही है। खुद सत्ताधारी कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी इस फंड से उनके विधानसभा क्षेत्र में ₹ 7 करोड़ के डीएमएफ घोटाला होने की शिकायत सदन में की है। स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष भी मान रहे हैं कि ऐसे घोटाले बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।

2019-20 में डीएमएफ फंड से कराया गया था भवन का निर्माण

ढाई करोड़ के भवन की टपक रही छत

150 बच्चे अध्ययनरत

एसओआर से अधिक दर पर हुआ निर्माण

जिम्मेदारों के खिलाफ हो कार्रवाई : सरपंच

विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार मुसीबत में, 250 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस प्रदेश समिति के प्रमुख मोहन मरकाम ने डीएमएफ फंड के दुरुपयोग को लेकर अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे. छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने पिछले साल डीएमएफ फंड में धांधली को लेकर इस्तीफा दे दिया था.

तबादला उद्योग

छत्तीसगढ़ में पैसों के बंदरबांट से हो रहा तबादला
भूपेश का एटीएम बन गया सरकारी अमला

प्रदेश में तबादला ने बाकायदा एक उद्योग का रूप लिया हुआ है। बाकायदा सभी पद के लिए रेट तय हैं। मलाईदार स्थानों के लिए करोड़ों में बोलियां लगाई जाती हैं, जिसमे मंथली रिचार्ज और टॉप-अप की भी सुविधाओं का जुगाड़ हो जाता है। सत्ता पक्ष से जुड़े विधायकों ने भी अनेक बार इस उद्योग की शिकायत की है।

बिलासपुर SP के तबादले पर पॉलिटिक्स: नेता प्रतिपक्ष का राज्य सरकार पर हमला, पूछा- कहीं ये विधायक और पुलिस के बीच विवाद का रिएक्शन तो नहीं?, कांग्रेस बोली-ये रूटीन ट्रांसफर

बिलासपुर 01/07/21

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर ह... कि कांग्रेस की सरकार में ट्रांसफर उद्योग बहुत अच्छ...

छत्तीसगढ़ में बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा औ... सेवा के 41 अफसरों के तबादले हुए हैं। इसमें बिल... प्रशांत अग्रवाल का नाम भी शामिल हैं। जिसको लेक... बीजेपी लीडर और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने ... सरकार पर जोरदार निशाना साधा है।

#BuildingUnsafe सालों से मकान खाली कराने के लिए घिस रहे चप्पलें

अधिकारी का फिर तबादला, मकान मालिक-किराएदार विवाद के 800 केस नहीं निपटे

बार-बार अधिकारियों के तबादले से लंबित मामलों का नहीं हो रहा निराकरण

ऐसे विवादों की सुनवाई

एक्सपर्ट व्यू

इस तरह की शिकायतें

शिक्षक भर्ती और तबादला घोटाला

वेतन वृद्धि की ताक में, शिक्षक हुए बेहाल करके शिक्षक भर्ती घोटाला, कांग्रेस ने लूटा माल

- छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को कांग्रेस सरकार ठीक तो नहीं कर सकी, लेकिन शिक्षक की भर्ती-ट्रांसफर-पोस्टिंग में भारी भ्रष्टाचार का माफ़िया राज जरूर चलाया है।
- विभाग के सचिव द्वारा ज्याइंट डायरेक्टर के खिलाफ जांच की बात कही गयी किन्तु स्थिति जस की तस है। भ्रष्टाचार के विश्वविद्यालय के कुलपति भूपेश बघेल के संरक्षण में केन्द्र के करोड़ों रुपयो का संगठित रूप से गबन करने कमीशनखोरी का खेल खेला गया। बिना काउंसलिंग 15,000 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति करने पोस्टिंग करी गई। जिन 12,000 मामलों में काउंसलिंग हुई, उन्हें दूर की पोस्टिंग दे कर उनसे संशोधित आदेश के लिए पैसे लिए गए। कांग्रेस नेताओं की सिफारिश पर हज़ारों ट्रांसफर आदेश संशोधित किये गए जिसमे हर आदेश पर करोड़ों की लेन-देन की गई। जिनकी क्रमोन्नति का वादा कर कांग्रेस ने उन्हें लुभाया था, उन्ही शिक्षकों को कांग्रेस ने लूट लिया।
- इससे अलग, सहायक शिक्षक भर्ती में एक ही कक्षा में बैठे 51 लोगों का चयन हो गया और व्यापम की शिक्षक भर्ती में टॉपर लिस्ट अलग और भर्ती लिस्ट में नाम अलग तथा परीक्षा में अभ्यार्थियों की संख्या अलग ऐसे भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। वहीं सरकारी विभागों में इन साढ़े चार वर्ष में कुल 33,348 पदों पर भर्ती की गयी किन्तु विज्ञापन सिर्फ 22,154 पदों का ही निकाला गया जिससे साफ पता चलता है की छत्तीसगढ़ में शासकीय पदों की भर्ती में गोलमाल का खेल खेला जा रहा है।

शिक्षकों की पदस्थापना में अनियमितताओं को लेकर ओपी द्वारा भूपेश सरकार पर सवालों की बौछार

राजधानी में हुई प्रेस वार्ता में ओपी भूपेश सरकार पर बरसे

नवभारत

तबादला, पदस्थापना पर चल रहा व्यापार-अलका

छीना नौनिहालों के मुंह का भी निवाला

भूपेश खा गया स्कूली बच्चों का सूखा राशन
बच्चों का बर्बाद हुआ भविष्य और जीवन

स्कूल शिक्षा विभाग में चावल वितरण के मामले में ₹ 500 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। कोंडागांव, जगदलपुर, सूरजपूर आदि जिलों में भंडार क्रय नियम एनसीसीएफ (NCCF), एनएसीओएफ (NACOF), एसएचजी (SHGs) केंद्रीय भंडार की अनदेखी कर बिना कॉन्ट्रैक्ट के सीधे चावल खरीद कर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया। संचालक ने आपदा का हवाला दे कर बीज निगम से सोयाबीन खरीदने के निर्देश जारी किए, लेकिन जिला कलेक्टरों ने सीधे निजी संस्थाओं से ख़राब क्वालिटी के सोयाबीन की खरीद की।

सूखा राशन वितरण में गड़बड़ी: नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की

28-Jun-2021

बिलासपुरः कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के स्कूल और
आंगनबाड़ी केंद्रों में सूखा राशन बांटा जा रहा है ...
बंद है और मिड डे मील योजना के तह...
खाना बांटा जा रहा था उसके एवज में ...
फैसला लिया गया था. अब इस वितरण ...
विपक्ष लगा रहा है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल क...
कि कोरोना काल के दौरान स्कूलों में सूखा रा...
दौरान घोटाला हुआ है. इस मुद्दे पर धरमलाल कौ...
की मांग की है. सरकार से मांग करते हुए नेता प्रति...
है कि इस पूरे मुद्दे पर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए...
तरह के भ्रष्टाचार की जांच करे.नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि...
बुलाकर सूखा राशन वितरण का कार्य किया जाना चाहिए...
लेकिन सरकार ने बिना टेंडर बुलाए नियमों को तोड़कर
ऑर्डर दिए है. पिछले विधानसभा सत्र के दौरान जब इस मुद्दे से
जुड़े सवाल किए गए थे. तब इस बात का खुलासा हुआ था.
धरमलाल कौशिक ने कहा कि इसलिए उन्होंने शिक्षा मंत्री को
पत्र लिखकर इस विषय में जांच की मांग की है. जांच कमेटी
बनाई जाए: धरमलाल कौशिक धरमलाल कौशिक ने कहा कि
यह पूरा मामला स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है.
इसलिए इसमें जांच की आवश्यकता है. एक निष्पक्ष जांच के
बाद ही पूरे मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और किस प्रकार का
घपला हुआ है इसका खुलासा हो पाएगा. उन्होंने जल्द से जल्द
इस गंभीर विषय में जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की

Chhattisgarh News: सूखा राशन वितरण में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप, नेता प्रतिपक्ष ने की सरकार से जांच की मांग

Raipur News: नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर डिटेल के साथ सूबे के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने विधानसभा में गलत जानकारी देने का आरोप विभागीय अधिकारियों पर लगाया है।

बच्चों का भविष्य अंधकारमय करने वाली कांग्रेस

शिक्षा सामग्री में भी किया भ्रष्टाचार
जनता बोल रही नहीं चाहिए ठगेश सरकार

- शिक्षा विभाग सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है क्योंकि यह विभाग ना सिर्फ प्रदेश के वर्तमान को प्रभावित करता है बल्कि प्रदेश के भविष्य के निर्धारण की नींव रखता है। दुःख की बात है की प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शिक्षा जैसे पवित्र काम को भी काला धन कमाने की फैक्ट्री बनाकर रख दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकारी स्कूलों की हालत ठीक करने का दावा करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिखती है। पूज्य संत स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर संचालित योजना में भी भ्रष्टाचार कर कांग्रेस सरकार की आंखों में शर्म नहीं आई। स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के नाम पर पूर्व से संचालित शासकीय स्कूलों में जीर्णोद्धार, गैर-जरूरी रंगाई पोताई व अन्य कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला कर दिया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा 726 नए स्कूल खोलने का दावा किया जाता है किन्तु एक भी स्वामी आत्मानंद स्कूल की नई बिल्डिंग (भवन) का निर्माण नहीं किया गया है।
- बच्चों के राशन से लेकर उनके पढ़ने-लिखने की वस्तुओं तक हर चीज में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। सरकार के खर्च पर ली गई एफ.एल.एन. किट, जिसे बच्चों को अंग्रेज़ी और गणित में दक्ष बनाना था, वो बच्चों और शिक्षकों तक पहुंची ही नहीं। कांग्रेस के नेता और कुछ अधिकारी मिलकर उसे हड़प गए। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रयास स्कूल संचालित किये जाते थे जिनमें अधिकांश स्कूलों को वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के मानक बना चुकी इस सरकार का ये सबसे शर्मसार करने वाला घोटाला है।

बच्चों का भविष्य अंधकारमय करने वाली कांग्रेस

शिक्षा सामग्री में भी किया भ्रष्टाचार
जनता बोल रही नहीं चाहिए ठगेश सरकार

- स्कूली शिक्षा से अलग, उच्च शिक्षा के हालात बद से बदतर होते जा रहे है। स्थिति यह है की प्रदेश में कुल 285 संचालित महाविद्यालय हैं जिसमें 73 महाविद्यालयों के पास स्वयं का भवन तक नहीं है। प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय की रैंकिंग देश में 100 के अन्दर भी नही है। राज्य सरकार द्वारा जी.ई.आर (ग्रॉस एनरोलमेंट रेसियो) 2022-23 को अभी तक जारी नहीं किया गया है। छात्रों के प्रवेश के अनुपात के विरुद्ध सीटों की संख्या बहुत ही कम है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों के 1369 पदों समेत हजारों अन्य पद रिक्त हैं। प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 अनुसार तकनीकी शिक्षा - 5,006, चिकित्सा शिक्षा - 17,854, कृषि शिक्षा - 4,938, स्कूल शिक्षा - 74,000 पद रिक्त हैं।

खेलगढ़िया मद में भ्रष्टाचार: लोक शिक्षण संचालनालय के अपर संचालक ने मांगी रिपोर्ट, खेल सामग्री के बदले 148 स्कूलों से खरीदवाया गया था टीवी

गरियाबंद 6 घंटे पहले

...बंद जिले में खेलगढ़िया मद में हुए भ्रष्टाचार का ... एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में लोक शिक्षण ...लय के अपर संचालक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर ...रे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि सरकार ...और मिडिल स्कूलों में खेल सामग्री के लिए पैसा दिया ...रियाबंद जिले के तत्कालीन DMC ने स्कूलों पर इससे टेलीविजन खरीदवा लिया था।

स्कूल शिक्षा विभाग में हावी है भ्रष्टाचार: व्यवस्था को सुधारने की जरूरत, बाबू से लेकर अफसर तक सब निकल रहे भ्रष्ट

स्कूल शिक्षा विभाग में जिस कदर भ्रष्टाचार हावी है, उससे अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिक्षा के मंदिरों का उद्धार आखिर कैसे हो पाएगा? खेलकूद सामग्री, लैब-लाइब्रेरी उपकरण और फर्नीचर खरीदी से लेकर अग्निशमन यंत्रों की खरीदी में भारी भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है।

संदीप तिवारी। रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में जिस कदर भ्रष्टाचार हावी है, उससे अब यह सवाल खड़े हो रहे है कि शिक्षा के मंदिरों का उद्धार आखिर कैसे हो पाएगा? खेलकूद सामग्री, लैब-लाइब्रेरी उपकरण और फर्नीचर खरीदी से लेकर अग्निशमन यंत्रों की खरीदी में भारी भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। इसके अलावा विभाग में नौकरी या अनुकंपा देने के मामले में भी भ्रष्टाचार जोरों पर है। यह हम नहीं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हाल के एक वर्ष के भीतर की गई कार्रवाई और विभागीय जांच में ये तथ्य उजागर हो चुके है। विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसमें भ्रष्टाचार हावी न हो रहा हो। विद्यार्थियों को मिड डे मील में सोया बड़ी देने में गड़बड़ी का मामला पिछले वर्ष उजागर हो चुका है।

किलोल मासिक पत्रिका में करोड़ों का घपला

जबरन बांटी किलोल मासिक पत्रिका
जनता ने देखा तो बस भ्रष्टाचार दिखा

छत्तीसगढ़ में स्कूल प्रबंधन के तहत स्कूलों में 'किलोल' मासिक पत्रिका की जबरन बिक्री शुरू हो गई है। इस पत्रिका का प्रकाशन एक निजी संस्था द्वारा किया जाता है। शिक्षकों को इसका आजीवन सदस्य बनने के लिए मजबूर किया गया। किलोल पत्रिका की खरीदी के लिये समस्त स्कूलों के शिक्षकों को खरीदने हेतु आदेश दिया गया और ₹ 10,000 की आजीवन सदस्यता एवं ₹ 720 की वार्षिक सदस्यता शुल्क देने को निर्देशित किया गया।

School Magazine Purchase Case : किलोल पत्रिका खरीदी मामले में जांच और पूछताछ होगी

August 8, 2023 Sukant Rajput

School Magazine Purchase Case :

0 मानसून सत्र में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया था मामला

0 विधानसभा कमेटी के पास है मामला, स्कूल शिक्षा मंत्री ने माना चूक

रायपुर/नवप्रदेश। School Magazine Purchase Case : विधानसभा के आखिरी सत्र में स्कूलों के लिए किलोल बाल पत्रिका खरीदी पर काफी बवाल मचा था। स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों में से एक किलोल और बाल पत्रिका की खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगे थे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया था कि निजी लोगों पर भी दबाव डालकर किलोल पत्रिका खरीदने के लिए मजबूर किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष speaker of the assembly ने विभाग से School Magazine Purchase Case : पत्रिका खरीदी की पूरी जानकारी हफ्ते भर में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। वहीं पूरे मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने माना है कि अकेले किलोल पत्रिका की खरीदी के

विधानसभा ब्रेकिंग – किलोल पत्रिका खरीदी पर सदन गरमाया, मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व मंत्री चंद्राकर के लिए कह दी बड़ी बात

CG Assembly Monsoon Session। किलोल पत्रिका की खरीदी को लेकर सदन में जमकर बहस हुई। अजय चंद्राकर के इस सवाल पर मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब दिया। चंद्राकर ने पूछा कि मिटिंग टीए पत्रिका खरीदने का निर्देश है क्या। मंत्री चौबे ने बताया अकस्मिक व्यय से खरीदी जाती है। उन्होंने कहा कि जांच जैसी कोई बात नहीं है। सारी पत्रिकाओं को खरीदने की अनुमति है। संकुल के लोग खरीदते हैं। कोई छिपाने की बात नहीं है। हमने किलोल के लिए आदेश दिया है।

साड़ी तक में घोटाला

साड़ी खरीद में चल रही कमीशनखोरी बताओ भूपेश कब रुकेगी ये चोरी

कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की इस तरह आदी हो चुकी है कि इन्होंने आंगनवाड़ी में कार्यरत माताओं और बहनों के लिए जो ₹ 1,000 (500 प्रति साड़ी) मोदी जी की सरकार ने भेजे थे, उसे भी डकार गयी। प्रदेश की माताओं-बहनों को अपने इस अधिकार के लिए भी विरोध प्रदर्शन करने पड़े, फिर भी भूपेश सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चेतावनी: रायपुर में बोलीं- दूसरी महिलाएं धनतेरस की खरीदारी कर रहीं, हम धरना दे रहे हैं, करेंगे बड़ा आंदोलन

रायपुर | 01/11/21

रायपुर के धरना स्थल पर आंगनबाड़ी से जुड़ी

लाल साड़ी पहने छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की महिलाएं रायपुर पहुंचीं। बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल पर इन महिलाओं ने आंदोलन कर दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संघ की प्रांतीय अध्यक्ष सरिता पाठक की अगुवाई में इन महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर वक्त रहते इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो नवंबर के दूसरे सप्ताह से इनके बड़े आंदोलन प्रदेश भर में शुरू हो जाएंगे।

छत्तीसगढ़

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में रोष, घटिया साड़ी मिलने से नाराज

सूरजपुर। सूरजपुर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इन दिनों अपने ही विभाग से खासी नाराज और आक्रोशित हैं। वजह है विभाग से घटिया साड़ी मिलना। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को महिला बाल विकास ने ड्रेस कोड के तहत साड़ी दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता- सहायिकाओं का कहना है कि साड़ी की क्वालिटी बेहद घटिया और निम्न स्तर की है।

कांग्रेस, करप्शन और कोरोना

कोरोना काल में सेस के नाम पर करोड़ों का खेल गरीबों के इलाज का पैसा डकार गया भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना सेस भी लगाया, लेकिन उसे भी खर्च नहीं किया। हाईकोर्ट ने भी इस सेस की रकम को डकार लेने के आरोप पर कांग्रेस सरकार को जवाबतलब किया है।

Chhattisgarh: हाईकोर्ट ने शराब पर कोरोना टैक्स लेने के मामले में सरकार से मांगा जवाब, दी 6 हफ्ते की मोहलत

Chhattisgarh News: कोरोनाकाल के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश में बेचे जा रहे शराब पर कोरोना टेक्स लगाया था. शराब पर लगे कोरोना टैक्स मामले में 10 माह बाद भी राज्य सरकार अपना जवाब पेश नही कर सकी. इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने अंतिम मौका दिया है. इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.

बिलासपुर. कोरोनाकाल के दौरान राज्य सरकार ने प्रदे में बेचे जा रहे शराब पर कोरोना टेक्स लगाया था. श पर लगे कोरोना टैक्स मामले में 10 माह बाद भी रा सरकार अपना जवाब पेश नही कर सकी. इस म बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिका करते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने दिया है. इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह ब याचिका को पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, बृज अन्य ने लगाया था, जिसमे कहा गया थ पैसा कोरोना अधोसंरचना में नहीं लग

Corona Cess: कोरोना सेस का पैसा किस आधार पर अन्य कार्यों में खर्च कर रही सरकार : विपक्ष

Corona Cess: नेता प्रतिपक्ष ने पूछा-शराबबंदी के लिए सामाजिक समिति की अब तक नहीं हुई बैठक।

रायपुर, राज्य ब्यूरो। Corona Cess: विधानसभा में प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने शराबबंदी के लिए बनाई गई सामाजिक कमेटी की बैठक को लेकर सवाल किया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि सामाजिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। राजनीतिक समिति की 19 अगस्त 2019 और प्रशासनिक समिति की नौ अक्टूबर 2019 को बैठक हुई है। कोरोना के कारण सामाजिक कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। कौशिक ने कहा कि अब तक सामाजिक समिति में सदस्यों के नाम तय नहीं हुए है। ढाई साल बीत गया, आज तक नाम तय नहीं हो पाया है। कब तक नाम आएंगे और समिति की बैठक कब होगी।

लॉकडाउन में शराब न मिलने से ये लोग सेनेटाइजर पी कर मर गए,इससे मुझे बहुत दुःख हुआ, बहुत पीड़ा हुई इसलिए शराबबन्दी नहीं कर रहे हैं।
शराब से मरे लोग
सेनेटाइजर से मरे लोग

बारदाना तक खा-चबा गए

कांग्रेस की कमीशनखोरी रही जारी जानबूझकर रोकी बोरे की खरीदारी

केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत न केवल बारदाना मामले में लगातार झूठ पर झूठ बोलते हुए किसानों को परेशान किया गया, बल्कि इसमें भी अनियमितता के अनेक मामले सामने आए हैं। सरकार को पता था कि जूट के बारदाने कम पड़ेंगे, फिर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाए, किसानों को बारदाने के लिए परेशान किया गया। शासन को जानकारी थी कि धान खरीदी 01 नवंबर से शुरू होगी, लेकिन बारदाना खरीदने के आदेश दिसंबर में जारी किए गए, इससे बारदाने धान खरीदी के सीजन समाप्त होने के बाद प्राप्त हुए। इन मामलों में ऐसी अकर्मण्यता तो यही दर्शाती है की कांग्रेस सरकार ने आपूर्तिकर्ता से सांठगांठ कर कमाई की है। अब तो प्रदेश में यह बात प्रचलित हो चुकी है कि “खाय बर होरा नइ ए... भूपेश करा बोरा नइ ए...”

बारदाना घोटाला: चौकीदार को डीएमओ ने हटाया, फूड विभाग ने सौंपी रिपोर्ट

23/01/19

बारदाना घोटाला: चौकीदार को डीएमओ ने हटा विभाग ने सौंपी रिपोर्टरायगढ़। औरदा गोदाम से 3 बारदाना लेकर खरसिया एक व्यापारी के यहां जा रह को फूड विभाग द्वारा पकड़ने के बाद...

रायगढ़। औरदा गोदाम से 3 हजार नए बारदाना लेकर ख एक व्यापारी के यहां जा रहे पिकअप को फूड विभाग द्वारा पकड़ने के बाद मार्कफेड ने गोदाम के चौकीदार रूपलाल मह को हटा दिया है। वहीं मामले की जांच कर रहे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। बीते मंगलवार को रायगढ़ एएफओ संतोष दुबे और खरसिया एएफओ कौशल किशोर साहू द्वारा खरसिया में पिकअप क्रमांक सीजी 13 यूई 3727 को संदिग्ध हालत में पकड़ा था। जांच के दौरान वाहन में 6 गठान याने 3 हजार नए बारदाना लोड मिला था। इसके बाद औरदा गोदाम में जांच की गई तो पता चला कि 2018-19 में 13328 नए गठान यानी 66 लाख 64 हजार 200 नए बारदाना शासन की ओर से मिला था। भौतिक सत्यापन में 35 सौ अधिक बारदाना 15 जनवरी की स्थिति में जावक में पाया गया, लेकिन औरदा गोदाम के चौकीदार कोई जवाब नहीं दे पाया। वहीं जिस वाहन को खरसिया के पास पकड़ा गया था। उसके पास मिले जावक गेट पास और मूल प्रति के गेट जावक पास में अंतर मिला।

कार्रवाई: सवा करोड़ का धान व बारदाने की हेराफेरी, 6 आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़ 2 वर्ष पहले

छह महीने पहले जैमुरा एवं बसनाझर धान खरीदी केन्द्रों में एक करोड़ 30 लाख रुपए के धान और बारदानों की हेराफेरी का मामला सामने आया था। इसमें समिति प्रबंधक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फड़ प्रभारी सहित 16 लोगों के खिलाफ खरसिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद फूड इंस्पेक्टर ने सोसाइटियों में जांच की और गड़बड़ी की रिपोर्ट दी। धारा 409, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पांच आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हो गई थी। अब फिर छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भानु प्रताप डनसेना सोंडका, डोल नारायण पटेल बायंग, खगपति पटेल जैमुरा, बंधुराम पटेल खरसिया, हलधर डनसेना आमापाली और बुद्धेश्वर डनसेना

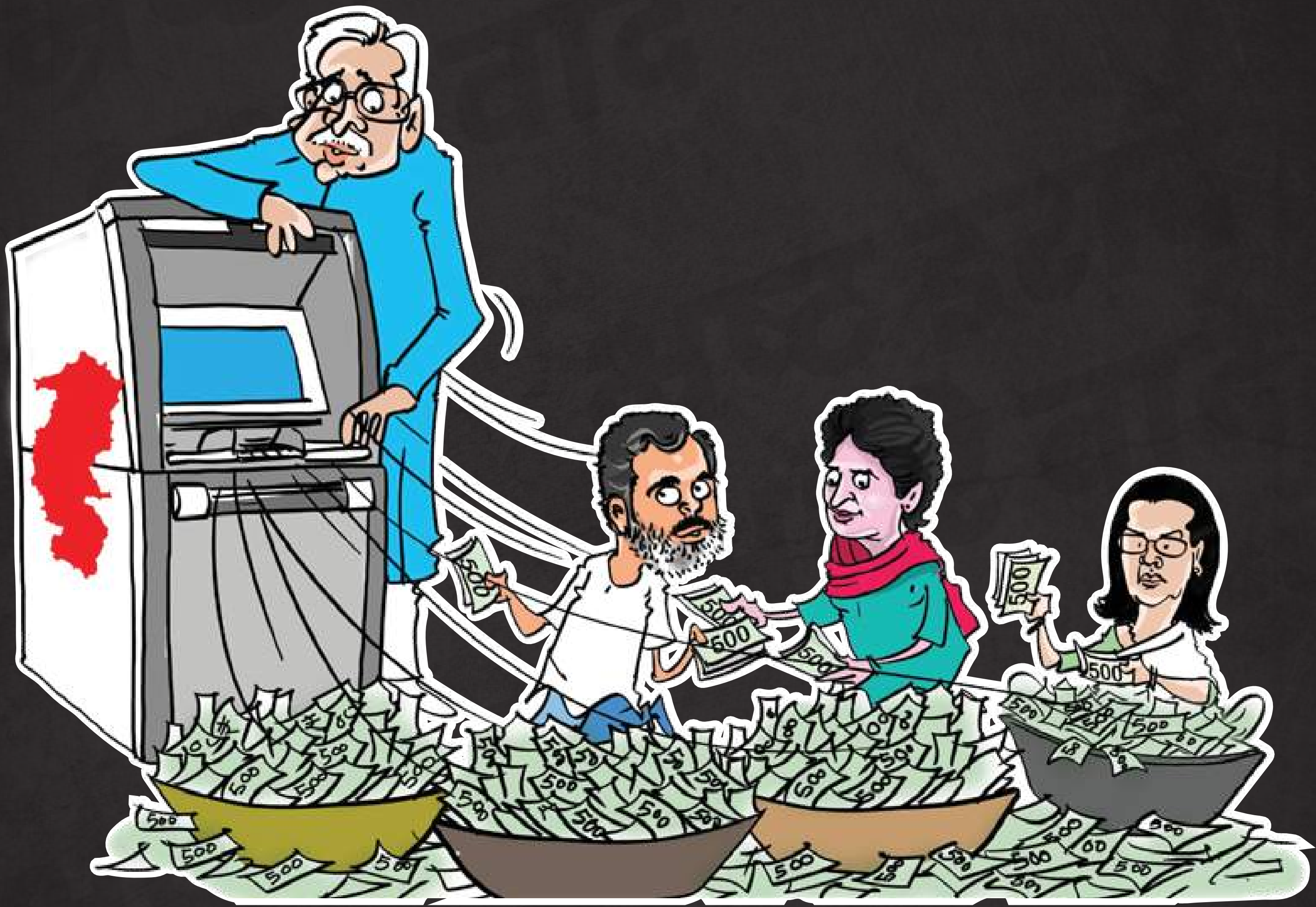

प्रदेश भर में जंगलराज, छत्तीसगढ़ बना अपराधगढ़

छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त अपराधियों के आगे भूपेश सरकार पस्त

- अभी तक दुष्कर्म के 5,909 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन औसतन 2 से 3 बलात्कार और हत्या के मामले दर्ज हो रहे हैं। इससे अलग अनेक ऐसे मामले हैं, जिसे दर्ज ही नहीं किया गया। प्रदेश में सरगुजा से लेकर बस्तर तक, मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग वृद्धाओं तक से नृशंस बलात्कार, उनके खिलाफ बर्बर हिंसा आदि के मामले से समूचा प्रदेश शर्मिंन्दा है। अनेक मामलों में तो सीधे तौर पर कांग्रेस के नेतागण संलिप्त रहे हैं। यहां तक कि एफआईआर दर्ज कराने में विफल रहने पर पीड़िता के पिता आत्महत्या की कोशिश करते हैं। अनेक स्थानों पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश में भी फिर से बलात्कार का शिकार हो जाती हैं महिलायें। समूचे प्रदेश में क़ानून व्यवस्था का बुरा हाल है। प्रदेश में लैंड माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया से लेकर ड्रग्स माफिया, कोल माफिया समेत हर तरह के लुटेरों की पौ बारह है। कांग्रेस संरक्षित तस्कर माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।
- छत्तीसगढ़ में अपराध प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण भी बढ़ा है। यह पहली सरकार है जिसमे पिछले 5 सालों में 2 कैबिनेट मीटिंग ही सचिवालय में की गई है। इनके अतिरिक्त, सारी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास में ही होती है। जिससे सचिवालय की महत्ता अपने आप समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सचिवालय नहीं जाते हैं, इसलिए वहां कोई वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं जाता है। सचिवालय अब कोई संस्था है ही नहीं।
- एस.डी.एम. लेवल के अधिकारी द्वारा चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरियों को निर्देशित करना तथा एडिशनल एस.पी. स्तर के अधिकारी के सामने डी.जी.पी. और आई.जी. सरीखे के लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं और उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। ये सरकार के प्रशासनिक कार्य करने का तरीका है, क्योंकि उन कनिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है।

एनएच के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर के लिए चक्काजाम

तत्कालीन बीइओ डॉ. नीलिमा गडकरी के निलंबन में साजिश की बू आ रही

एक्सप्रेस-वे में चाकू मारकर गार्ड की हत्या फोन लूटकर चार भागे

माफिया सरकार

आपराधिक कारनामों में संलिप्त भूपेश बघेल
कांग्रेस राज में चल रहा माफियाओं का खेल

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नकली अश्लील सीडी निर्माण एवं वितरण मामले में भी सीबीआई से चार्जशीटेड हैं। अश्लील सीडी मामले में सीबीआई ने केस को छत्तीसगढ़ के बाहर ले जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। फिलहाल यह लंबित है। इसके अलावा वे स्वयं अनेक EWS आवास को हड़प कर उस पर दुर्ग में अपना निजी बंगला नियम विरुद्ध बनाए जाने के आरोपी हैं। जिस तरह से कोयला घोटाले, शराब घोटाले आदि का बचाव कर रहे हैं, आरोपियों को बचाने पूरी ताकत झोंक रहे हैं भूपेश बघेल, उससे साफ जाहिर होता है कि तमाम घोटालों के 'पॉलिटिकल मास्टर' कोई और नहीं, स्वयं भूपेश बघेल ही हैं। इन्हीं घोटालों की काली कमाई से उनकी कुर्सी सलामत है और देश भर में वे कांग्रेस के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ का संसाधन झोंक रहे हैं।
- तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से लेकर के पटवारी, आर.आई तथा पुलिसकर्मी, सभी इस सरकार और सरकारी दल के कार्यकर्ताओं से नियमित प्रताड़ित एवं अपमानित होते रहे हैं। इन सबका निरंतर आर्थिक एवं मानसिक शोषण सरकार के मुखिया के संरक्षण में हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट तंत्र के संचालन में आम आदमी के दैनिक कार्य नियमित रूप से बाधित हो रहें हैं।
- पिछले 3 साल - 1 दिसंबर 2020 से 10 फरवरी 2023 - तक के कुछ आंकड़े बढ़ते अपराध की घटनाओं की पुष्टि करते हैं जैसे चोरी - 18,970, डकैती - 153, रेप - 6,703, हत्या - 2,320, हत्या का प्रयास - 1,606, सीलमंग - 3,867, गुमशुदगी - 25,535, अवैध शराब - 37,601 और ऑनलाईन ठगी लगभग 1,400 आदि।

अश्लील सीडी कांड: SC ने ट्रायल पर लगाई रोक, CM भूपेश बघेल को नोटिस

क्या है छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाला अश्लील सीडी कांड, सीबीआई ने किया खुलासा

अवैध खनन: रेत भंडारण की अनुमति में भी रॉयल्टी का बड़ा खेल
अनुमति एक की, कर रहे तीन से 4 जगह डंप, सरकारी जमीन पर भी रेत की मंडी

रेत खदान पर कार्रवाई करने गये अधिकारी लौटे उल्टे पांव

लोकपाल

लोकपाल बिल के नाम पर भूपेश ने लिया वोट लेकिन शुरू से इरादे में था खोट

लोकपाल लाने का वादा भी ये सरकार करके भूल गयी। वादा तो ये था कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाएंगे पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। होता भी कैसे? जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उनके रिश्तेदार एवं उप-सचिव तक की नाक भ्रष्टाचार में डूबी हो, वह किसी लोकपाल का गठन कर अपने गले खुद फंदा क्यों लगाना चाहेंगे ? अगर आज लोकपाल लाने का वादा पूरा कर लिया होता तो शायद इस बेदर्दी से प्रदेश का संसाधन लूट कर दस जनपथ का पेट नहीं भर पाती कांग्रेस।

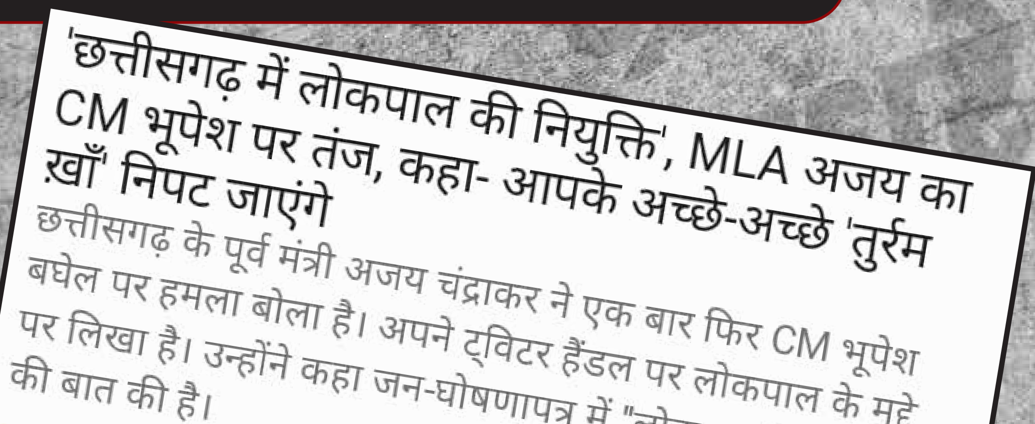
'छत्तीसगढ़ में लोकपाल की नियुक्ति', MLA अजय का CM भूपेश पर तंज, कहा- आपके अच्छे-अच्छे 'तुर्रम ख़ाँ' निपट जाएंगे

छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बार फिर CM भूपेश बघेल पर हमला बोला है। अपने ट्विटर हैंडल पर लोकपाल के मुद्दे पर लिखा है। उन्होंने कहा जन-घोषणापत्र में "लोकपाल" की नियुक्ति की बात की है।

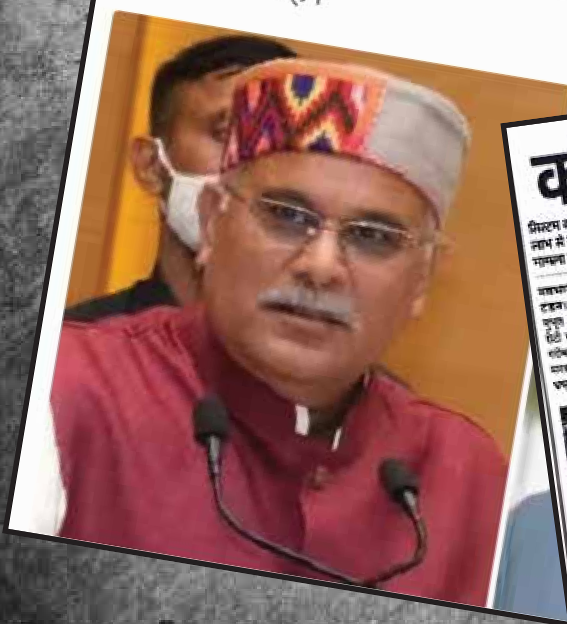

कौन करेगा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई

चोर मचाए शोर

आरोप लगाने में सबसे आगे कांग्रेस
काम गिनाने में मुंह छिपाकर भागे भूपेश

प्रदेश में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है, जहां तैमूर और नादिर शाह की तरह लूट नहीं मचाई हो कांग्रेस सरकार ने। मोटे आकलन के अनुसार कुल ₹ 1 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला कर कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। इसकी पुष्टि कांग्रेस सरकार में मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध चिट्ठी लिखने की घटना से होता है। जहां कांग्रेस विधायक श्री शैलेश पांडे ने छत्तीसगढ़ पुलिस को थाने के बाहर रेटलिस्ट टांगने को कहा, वहीं कांग्रेस विधायक श्री बृहस्पत सिंह ने अपनी ही सरकार की पुलिस के विरुद्ध धरना दिया। ऐसे में जब जांच एजेंसियां स्पष्ट साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करती है, तब ये भाजपा के खिलाफ अनेक काल्पनिक आरोप लगाने लगते हैं। जबकि तथ्य यह है कि कोई भी आरोप साबित करना तो दूर की बात, किसी भी मामले में सामान्य कार्यवाही तक नहीं कर पाई है कांग्रेस सरकार। इसी तरह विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस नेताओं ने सत्ता के लालच में ऊल-जलूल आरोप लगाए, जिनमें से हर मामले में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा हो चुका है कि उन पर अब कोई भरोसा नहीं करता।

प्रतिशोध की राजनीति के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में उसके अधिकारियों पर ईडी के छापे पर कांग्रेस ने कहा, 'प्रतिशोध'

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें कांग्रेस विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के आवास भी शामिल हैं, जिसे सबसे पुरानी पार्टी ने भाजपा की "प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति" का हिस्सा बताया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने कोयला लेवी मामले की जांच के तहत 10-12 स्थानों पर तलाशी ली। जांच आयकर विभाग की एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया था कि वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों द्वारा छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए कोयले से 25 रुपये प्रति टन की अवैध वसूली की गई थी। इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए दिसंबर 2022 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक वरिष्ठ सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था।

कांग्रेस बांटे रेवड़ी, कांग्रेसियों को देय

लबरा के लुटेरों ने खोली करप्शन की दुकान जिसका नाम रखा राजीव मितान

- सरकार द्वारा 13 हजार से अधिक राजीव मितान क्लब के लिए ₹ 132 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रति वर्ष ₹ 1 लाख इन क्लबों को दिया जाएगा। न सिर्फ इन क्लबों का गठन पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों को रौंद कर किया गया है, बल्कि इसके लगभग सारे पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ना तो पदाधिकारियों के चयन में कोई पारदर्शिता है और न किसी प्रकार के खर्च का ऑडिट हो रहा है। परिणाम ये है कि जो पैसे प्रदेश के विकास कार्यों में खर्च किये जा सकते थे, उन पैसों को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है।
- प्रदेश सरकार की खेलों के प्रति लापरवाही का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है की चार वर्षों से उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा नहीं की गयी एवं आज तक छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय स्तर पर एक भी खेल शामिल नहीं हो सका है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया व ओलंपिक खेल के तहत 25 अकादमी खोलने की घोषणा की थी उनमें से एक भी अकादमी राज्य सरकार प्रारंभ नहीं करा पायी। प्रदेश के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली भूपेश सरकार ने खेल को अवैध वसूली एवं कमीशनखोरी का माध्यम बना दिया है।

राजीव मितान क्लब के नाम पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं पर लुटाया जा रहा पैसा : भाजपा

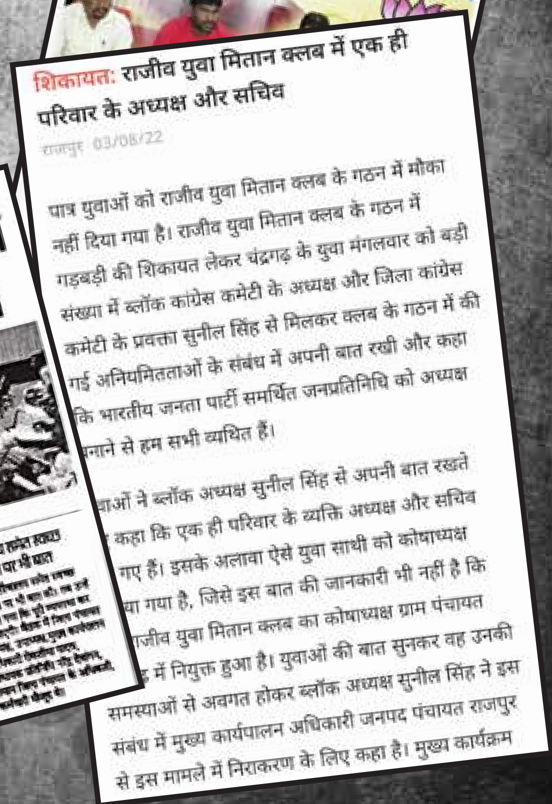
शिकायत: राजीव युवा मितान क्लब में एक ही परिवार के अध्यक्ष और सचिव

राजपुर 03/08/22

पात्र युवाओं को राजीव युवा मितान क्लब के गठन में मौका नहीं दिया गया है। राजीव युवा मितान क्लब के गठन में गड़बड़ी की शिकायत लेकर चंद्रगढ़ के युवा मंगलवार को बड़ी संख्या में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुनील सिंह से मिलकर क्लब के गठन में की गई अनियमितताओं के संबंध में अपनी बात रखी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित जनप्रतिनिधि को अध्यक्ष ...नाने से हम सभी व्यथित हैं।

...ओं ने ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सिंह से अपनी बात रखते ... कहा कि एक ही परिवार के व्यक्ति अध्यक्ष और सचिव ... गए हैं। इसके अलावा ऐसे युवा साथी को कोषाध्यक्ष ...या गया है, जिसे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि ...राजीव युवा मितान क्लब का कोषाध्यक्ष ग्राम पंचायत ... में नियुक्त हुआ है। युवाओं की बात सुनकर वह उनकी समस्याओं से अवगत होकर ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सिंह ने इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजपुर से इस मामले में निराकरण के लिए कहा है। मुख्य कार्यक्रम

बैठक · जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में सदस्य रोहित ने उठाए कई सवाल

मितान क्लब का कांग्रेसीकरण करने अफसरों पर लगा आरोप

वादा रोजगार का था, मिल रही है गोली

चार साल गुजार दिए गेंड़ी-भौंरा की सरकार ने, कलेक्शन बाबू करेक्शन भी ना सीख पाए पीआर में

घर-घर रोजगार का वादा कर भूपेश सरकार ने सिर्फ कुछ कांग्रेस के नेताओं और अफसरों के परिवारों को रोजगार देने का काम किया है। पीएससी और व्यापम के जरिए होने वाली सरकारी भर्तियों में चयन के लिए ₹ 75 लाख की बोली लगाई जा रही है। 10 लाख युवाओं को ₹ 2,500 हर माह देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर इतने कड़े नियम बनाए की अधिकांश बेरोज़गार युवा इसके लाभ से वंचित रह गए। इस तरह कांग्रेस सरकार ने युवाओं के हक़ के ₹ 15,000 करोड़ का गबन किया है। लगातार नौकरी देने का झूठ बोलती रही कांग्रेस सरकार में स्थिति यह है कि चतुर्थ श्रेणी के 95 पदों के विरुद्ध 2.25 लाख युवाओं के आवेदन आते हैं। नौकरियों में आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार में इस समय 75 हज़ार से अधिक नौकरियां आउटसोर्सिंग पर हैं। भाजपा सरकार में तेजी से बड़ी मात्रा में चल रहे युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को बंद कर इस सरकार ने जहाँ उन्हें भत्ताजीवी बनाया है, वहीं उनके हक़ की नौकरी आउटसोर्स कर दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन में 36,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की है, जिनमें 13 हजार से अधिक संख्या उन युवाओं की है जो बेरोजगारी के कारण परेशान थे। आत्महत्या के आंकड़ो में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान और नशे के आकड़ो में देश में दूसरे स्थान पर है जो प्रदेश में भूपेश सरकार की विफल युवा नीतियों को प्रमाणित करता है। बावजूद इसके कांग्रेस गाल बजाती रही और इसके मंत्री यह कह कर युवाओं के जख्म पर नमक छिड़कते रहे कि युवाओं को पंचर साटना चाहिए।

आरटीई की जिले में 2000 और राज्यभर में 25 हजार सीटें खाली, तीसरा राउंड नहीं होगा

चार माह से नहीं दिया मजदूरों का पैसा हाईवे बनाने वाली कंपनी की शिकायत

कलेक्टर -एसपी से भी मिलकर करेंगे शिकायत

युवाओं के लिए एक राजनीतिक आपदा साबित हुई है कांग्रेस

आउटसोर्सिंग और संविदा पर मिला धोखा
जनता बोली कांग्रेस को नहीं मिलेगा अब मौका

भूपेश बघेल ने सत्ता में आने से पहले आउटसोर्सिंग का खूब विरोध किया, परंतु आते ही पूरी सरकार को आउटसोर्सिंग व संविदा के भरोसे छोड़ दिया है। सरकार के खुद के मंत्री श्री उमेश पटेल ने विधानसभा के मंच से आउटसोर्सिंग को आवश्यक बताया था और शायद यही वजह है कि पिछले पौने पांच सालों में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है, जहाँ आउटसोर्सिंग नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों हेतु परिवीक्षा अवधि की सीमा 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर दी। साथ ही, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष क्रमशः नए कर्मचारियों को 70, 80 एवं 90 प्रतिशत वेतन देने का नियम लागू किया है, जिसके कारण अवधि बढ़ने से युवा न सिर्फ मानसिक रूप से परेशान हुए है बल्कि उनको आर्थिक हानि भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को हर सुविधा और सुरक्षा से वंचित रखना चाहती है कांग्रेस सरकार। प्रदेश के युवाओं के लिए एक राजनीतिक आपदा है कांग्रेस।

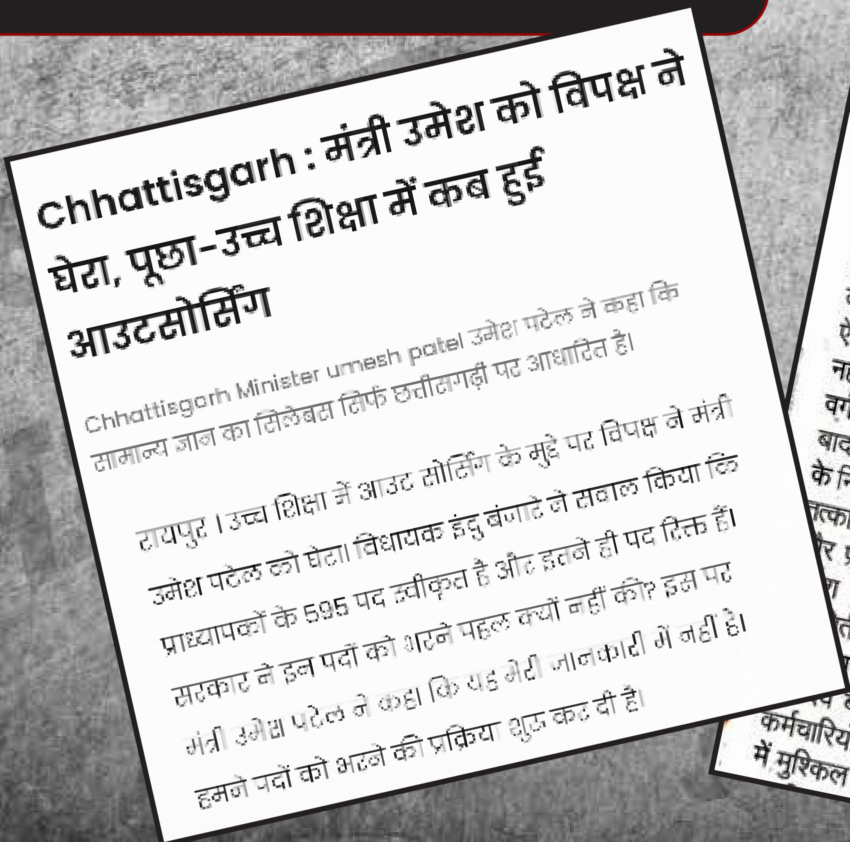

Chhattisgarh : मंत्री उमेश को विपक्ष ने घेरा, पूछा-उच्च शिक्षा में कब हुई आउटसोर्सिंग

Chhattisgarh Minister umesh patel उमेश पटेल ने कहा कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस सिर्फ छत्तीसगढ़ी पर आधारित है।

रायपुर । उच्च शिक्षा में आउट सोर्सिंग के मुद्दे पर विपक्ष ने मंत्री उमेश पटेल को घेरा। विधायक इंदु बंजारे ने सवाल किया कि प्राध्यापकों के 595 पद स्वीकृत है और इतने ही पद रिक्त हैं। सरकार ने इन पदों को भरने पहल क्यों नहीं की? इस पर मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि यह मेरी जानकारी में नहीं है। हमने पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वादाखिलाफी ने ली संविदा कर्मचारी की जान : भाजपा

रायपुर @ पत्रिका. भाजपा ने संविदा कर्मचारी की मृत्यु होने पर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी ने मोतीलाल की जान ली है। छत्तीसगढ़ की जनता और कर्मचारी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। चौधरी ने कहा, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे कांग्रेस ने नहीं ठगा। सत्ता में आने के लिए हर वर्ग से झूठ बोला। सत्ता में आने के बाद सभी को धोखा दिया। कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया था। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ...र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए ...ा बघेल ने 10 दिन में ...तीकरण का लिखित वादा किया ... चंद महीने के उप मुख्यमंत्री ...य बयान दे रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने में मुश्किल है।

भर्ती बंद : युवाओं के ज़ख़्मों पर नमक छिड़कने वाली सरकार

नई भर्तियों पर भूपेश ने लगाया प्रतिबंध युवाओं के भविष्य का शटर किया बंद

बेरोजगारी भत्ते के नाम पर इस सरकार ने पहले ही चार साल से इस प्रदेश के युवाओं को ठगा था, फिर बची-खुची कसर 10 जुलाई 2023 को वित्त विभाग से एक आदेश जारी कर पूरी कर दी। इस आदेश के माध्यम से राज्य में नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये कैसा कुशासन है, जिसमें महतारी के युवा संतानों के भविष्य को नीतिगत तरीके से अंधकार में धकेला जा रहा है। एक तरफ शत-प्रतिशत रोजगार देने का गाल बजा रहे हैं, दूसरी तरफ चपरासी के 95 पदों के विरुद्ध 2.25 लाख छत्तीसगढ़ी युवाओं के आवेदन आ रहे हैं। युवाओं को शराब बेचने या गोबर बिनने के काम में लगा दिया गया है।

सचिव भर्ती घोटाला: विधायक और कलेक्टर समेत 8 अधिकरियों से शिकायत, लेकिन परिणाम शून्य? अब जांच कराने की सुगबुगाहट

कलेक्टर और सीईओ ने अलग-अलग जांच गठि
एक सप्ताह के भीतर मांगी रिपोर्ट, विधाय
कहा- जांच प्रतिवेदन आने पर भर्ती
पायी जाती है, तो संबंधित जिम्म
अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय
खबर...

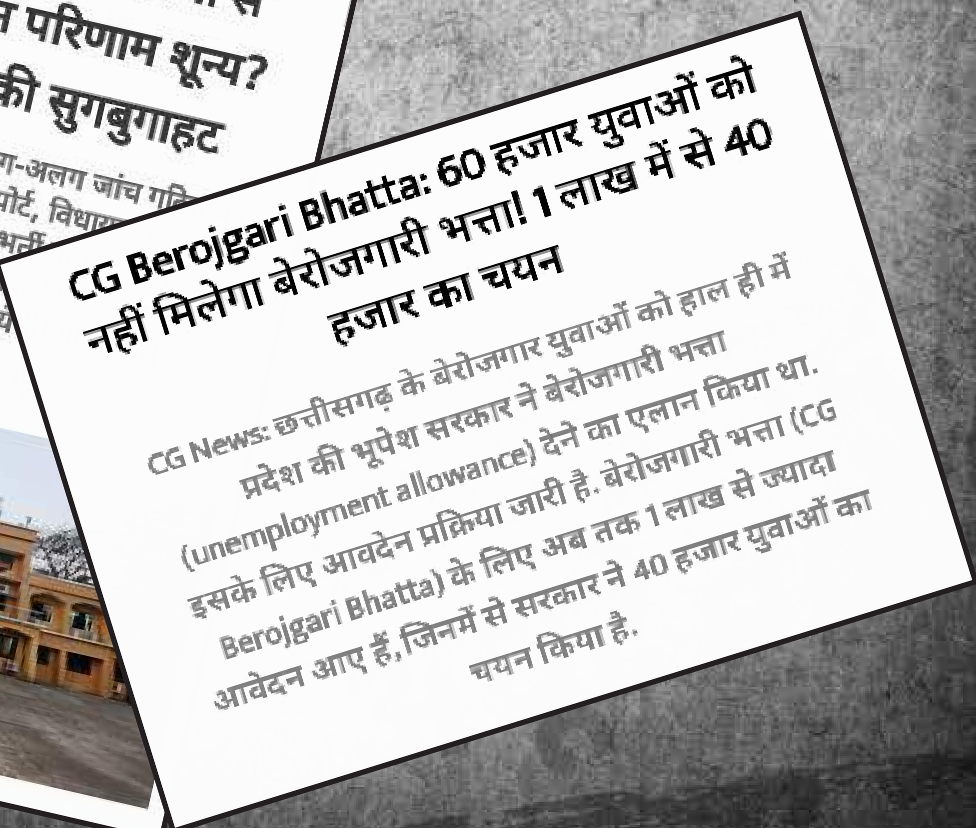

CG Berojgari Bhatta: 60 हजार युवाओं को नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता! 1 लाख में से 40 हजार का चयन

CG News: छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को हाल ही में प्रदेश की भूपेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता (unemployment allowance) देने का एलान किया था. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. बेरोजगारी भत्ता (CG Berojgari Bhatta) के लिए अब तक 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें से सरकार ने 40 हजार युवाओं का चयन किया है.

आरक्षण- चोर से कहो चोरी कर, गृहस्वामी को कहो जागते रहो

भूपेश ने उपेक्षित जातियों पर किया अत्याचार नहीं दिया आरक्षण निर्लज्ज हुई कांग्रेस सरकार

भूपेश बघेल आरक्षण मामले में भी अपना दोहरा आचरण का परिचय दे रहे हैं। वे जान-बूझ कर समाज को बांटने की साजिश इस मामले में भी रच रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा किये गए 58 प्रतिशत के आधार पर बहाली आदि करने की फिलहाल अनुमति दी है, अभी भी आरक्षण के मामले विभिन्न अदालतों में लंबित है। एक तरफ कांग्रेस झूठ पर झूठ गढ़कर अनुसूचित वर्गों को गुमराह कर रही है, उन्हें आरक्षण का आश्वासन देती है।काफी कमजोर कानून भी बना देती है, उधर अपने करीबियों से ही मुकदमा कराकर कोर्ट में मुकदमा हार भी जाती है। जब मंडल आयोग ने पहली बार पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था, तब भी कांग्रेस विपक्ष में थी और आरक्षण पर महत्वपूर्ण सुनवाई के दिन बकायदा महाधिवक्ता को अनुपस्थित करा दिया, ताकि सरकार वह मुकदमा हार जाए। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का भी कांग्रेस ने संसद में विरोध किया। अभी 12 आदिवासी समुदाय को भी एसटी का दर्जा देने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर छ. ग के सांसद सदन में अनुपस्थित करा दिए गए थे।

कांग्रेस ने षड्यंत्र करके आदिवासी आरक्षण में कराई कटौती-भाजपा

'कांग्रेस आरक्षण विरोधी': विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा- जो कोर्ट गए, सरकार ने उन्हें ही पद बांटकर किया सम्मानित

सार

धरमलाल कौशिक ने कहा कि, 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 58 फ़ीसदी आरक्षण को लागू किया था। लोगों को इसका लाभ मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद उनके करीबियों ने आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।

धरमलाल कौशिक, भाजपा विधायक। - फोटो : संवाद

नग्न प्रदर्शन करने को विवश अनुसूचित जाति व जनजाति के युवा

साढ़े चार साल युवाओं को नहीं दिया रोजगार
अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बांट रही सरकार

कांग्रेस सरकार में सबसे अधिक प्रताड़ित पिछड़े और कमजोर वर्ग के युवा हुए हैं। हालात इतनी बदतर है कि समूचे देश में पहली बार ऐसा हुआ, जब अपने अधिकार के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति के युवाओं को नंगे होकर विधानसभा जाने वाली सड़कों पर दौड़ना पड़ा। बड़ी संख्या में अपने अधिकार से वंचित कर दिए गए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इनका अधिकार हड़प लिए कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के बजाय सरकार ने इन युवाओं को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, इन पर मुक़दमे लाद दिए गए। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी पाए 267 लोगों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश पर जान-बूझ कर अमल नहीं किया सरकार ने। इस कृत्य से देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का मान-सम्मान धूमिल किया गया है।

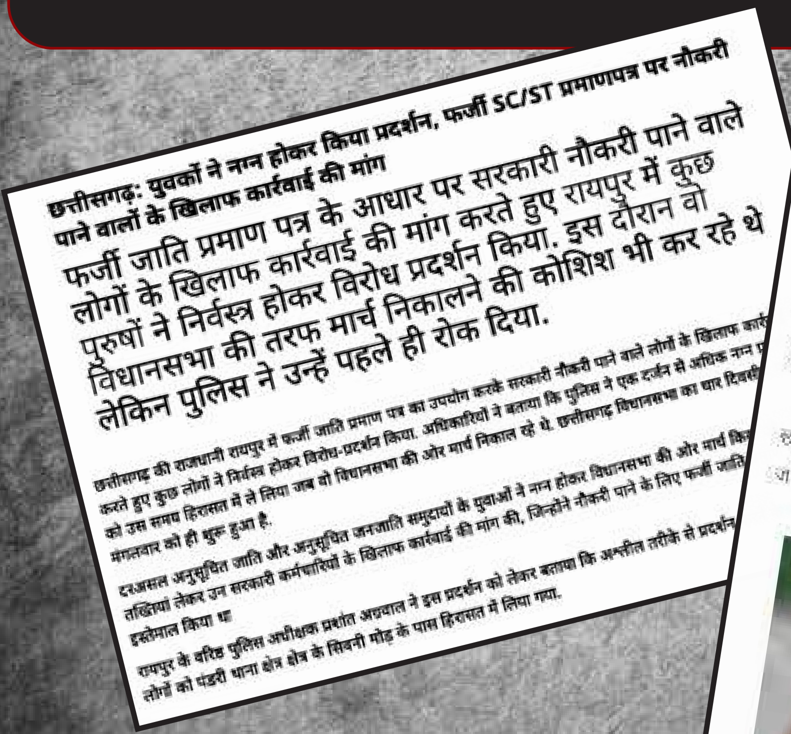

छत्तीसगढ़: युवकों ने नग्न होकर किया प्रदर्शन, फर्जी SC/ST प्रमाणपत्र पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए रायपुर में कुछ पुरुषों ने निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान वो विधानसभा की तरफ मार्च निकालने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के खिलाफ कार्... करते हुए कुछ लोगों ने निर्वस्त्र होकर विरोध-प्रदर्शन किया. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने एक दर्जन से अधिक नग्न प्... को उस समय हिरासत में ले लिया जब वो विधानसभा की ओर मार्च निकाल रहे थे. छत्तीसगढ़ विधानसभा का चार दिवसी... मंगलवार को ही शुरू हुआ है.

दरअसल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के युवाओं ने नग्न होकर विधानसभा की ओर मार्च किय... तख्तियां लेकर उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति... इस्तेमाल किया था

रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने इस प्रदर्शन को लेकर बताया कि अश्लील तरीके से प्रदर्शन... लोगों को पंडरी थाना क्षेत्र क्षेत्र के सिवनी मोड़ के पास हिरासत में लिया गया.

छत्तीसगढ़ में SC-ST वर्ग के युवाओं का भड़का गुस्सा, 'निर्वस्त्र' होकर किया प्रदर्शन, जानिए वजह

छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी मामले में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं ने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया।

उड़ता छत्तीसगढ़

ड्रग तस्करी रोकने में हो चुकी फेल
नशे में डूबा प्रदेश, भूपेश बघेल हुए फेल

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को गांजा समेत तमाम अवैध नशों का भी गढ़ बना दिया है। बढ़ते नशे की चपेट में आ, प्रदेश के युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। नशे की हालत में चाकूबाजी की घटनाएं आम हो गई हैं। स्थिति यह हो गयी है कि युवाओं द्वारा किये जा रहे अपराधों में राज्य देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। लोग अब इसे "उड़ता पंजाब" की तर्ज पर "उड़ता छत्तीसगढ़" कहते हैं। हाल ही में नशीली दवाओं की बरामदगी के अनेक मामले सामने आए हैं । इसमें बालोद जिले में 1.27 क्विंटल गांजा, महासमुंद कोमाखान में 7 क्विंटल, बलरामपुर में 16 क्विंटल, कोंडागांव पुलिस द्वारा 1 क्विंटल, जगदलपुर जिले में 144 किलोग्राम गांजा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चरस, हेरोइन, गांजा और नशीली गोलियाँ जैसी कई अन्य दवाएं भी जब्त की गई है।

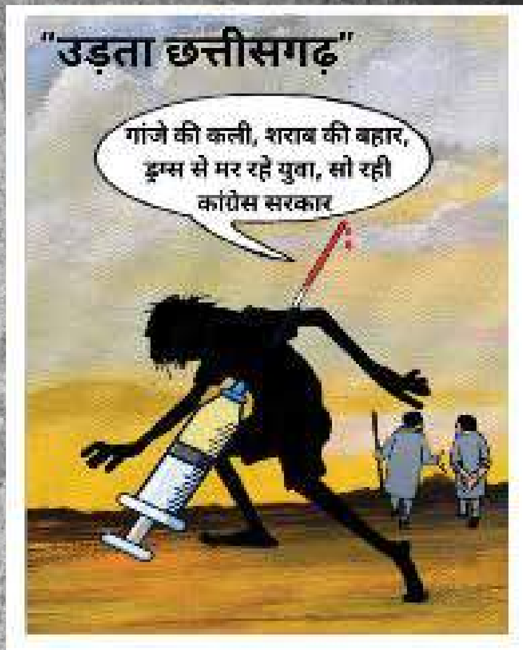

रेलवे स्टेशन में तस्कर: यूपी के बाद अब सतना का युवक पकड़ाया

दूसरे दिन 2 लाख का गांजा जब्त

रायपुर @ पत्रिका. ट्रेनें गांजा तस्करी का बड़ा जरिया बन गई है। रेलवे सुरक्षा बल ने बुधवार को प्लेटफार्म नंबर 7 के तरफ सतना के एक युवक के बैग से 2 लाख 1 हजार 800 रुपए का गांजा जब्त किया। आरोपियों को पकड़कर जीआरपी के सुपुर्द नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए सौंपा। एक दिन पहले मंगलवार को प्लेटफार्म-1 पर यूपी के एक युवक से 1 लाख 35 हजार का गांजा जब्त किया था। सुरक्षा अफसरों ने आपरेशन नारकोस चलाया है। मुखबिर की सूचना ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 07 दुर्ग छोर की तरफ रात 10..25 बजे घेराबंदी कर एक युवक पकड़ा। उसके एयर बैग की तलाशी लेने पर 2 पैकेट गांजा निकला, जिसका वजन 20 किलो 180 ग्राम था। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रविशंकर गुप्ता पिता-रामरूप गुप्ता, उम्र 25 साल सतना जिले का रहने वाला बताया। जीआरपी ने प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

Chhattisgarh: अवैध ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, सवा करोड़ रुपये का नशीला पदार्थ बरामद; दो लोग गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। उन्होंने 1.25 करोड़ रुपये मूल्य का 500 किलोग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किया है। आरोपी इसे ...र ले जा रहे थे। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। (फाइल फोटो)

09 Jun 2023 09:55 AM (IST)
08 Jun 2023 09:55 AM (IST)

वन अधिकार पट्टों का खराब वितरण

आदिवासियों को दिया धोखा, पट्टे का अधिकार रोका

कांग्रेस सरकार ने आदिवासी संस्कृति के साथ-साथ आदिवासियों के अधिकार पर भी आघात किया है। भाजपा सरकार में वर्ष 2008-18 तक प्रतिवर्ष औसतन 40,158 की दर से कुल 4,01,586 वन अधिकार पट्टे वितरित हुए थे। वहीं, कांग्रेस सरकार के पहले 4 साल में प्रतिवर्ष वन अधिकार पट्टा वितरण की औसत कम हो कर मात्र 13,692 रह गई। भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार की तुलना में प्रतिवर्ष तिगुना वन अधिकार पट्टा वितरण का काम करती थी। इसी का नतीजा है की, छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों की तुलना में दूसरे स्थान से गिरकर सातवे स्थान पर आ गया है। कांग्रेस सरकार ने धर्मान्तिरण को बढ़ावा दे कर आदिवासी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है, इलाज की व्यवस्था खराब कर नवजात आदिवासी बच्चों की जान ली है और वन अधिकार पट्टा वितरण में कमी कर आदिवासी अधिकारों का हनन किया है।

Pankhajur news: 70 साल से वन अधिकार पट्टे की मांग कर रहा OBC वर्ग, रैली निकालने पर SDM ने दिए ये निर्देश

70 साल से वन अधिकार पट्टे की मांग कर रहा OBC वर्ग, रैली निकालने पर SDM ने दिए ये निर्देश OBC class is demanding forest rights lease

Edited By: Bhavna Sahu , April 4, 2023 / 06:23 PM IST

पंखाजूर। ब्लॉक कोयलीबेड़ा क्षेत्र के OBC वर्ग द्वारा पीछले 70 साल से वन अधिकार पट्टे की मांग की जा रही है। 15 साल भाजपा की सरकार रही और 5 साल कांग्रेस की, परन्तु आज तक वन अधिकार पट्टा नहीं मिल सका। इससे नाराज कोयलीबेड़ा क्षेत्र के समस्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं ने एकजुट होकर पखांजुर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर वन अधिकार पट्टे की मांग की और पखांजूर नगर में रैली निकाली गई।

वन अधिकार पट्टा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन

धमतरी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। वन अधिकार पट्टे सहित छह सूत्रीय मांग को लेकर 21 अक्टूबर को सीटू के बैनर तले लोगों ने गांधी मैदान के पास धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल से लोगों ने राज्य सरकार को लेकर जमकर नारे ...गाए। लोगों का कहना था कि सालों बाद भी उन्हें वन अधिकार पट्टा नहीं ...ल पाया है। इससे उन्हें शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं मिल ...हा है। जल्द से जल्द वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जाए। प्रदर्शन के ... अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।

... प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार से वन अधिकार पट्टा ...वासीय पट्टा की मांग जिला के धमतरी, नगरी, मगरलोड एवं कुरुद ... भूमिहीन नागरिक कई वर्षों से मांग कर रहे है, लेकिन 15 वर्ष की ...रकार और ढाई साल वर्ष पुरानी भूपेश सरकार पट्टे की मांग को ...न कर रही है एवं पट्टा देने के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही

चिटफंड कंपनी के नाम पर जमीनों के बंदरबांट

वाह रे भूपेश तेरा गड़बड़झाला
चिटफंड के नाम पर किया करोड़ों का घोटाला

इस मामले में केवल कांग्रेसियों को माटी के मोल जमीन दिलाने का काम कर रही है प्रदेश सरकार। प्रदेश की जमीनों को नाम मात्र की कीमत पर कांग्रेसियों को सौंप रही है।

निगम की हर जमीन पर विवाद • भैंसथान को एजेंडे से निकालने के बाद भास्कर की पड़ताल

डूमरतराई, भैंसथान और मालवीय रोड की जमीन बेचकर 161 करोड़ रु. कमाना चाहता था निगम

भास्कर खास

भैंसथान विवाद

गंज मंडी विवाद

पुराना निगम मुख्यालय

पंडरी बस स्टैंड

5.70 एकड़ शासकीय और 5.50 एकड़ निजी भूमि का फर्जीवाड़ा

करोड़ों की जमीन का फर्जीवाड़ा तत्कालीन पटवारी गिरफ्तार

पुलिस को जांच में मिले थे कई सबूत, पूर्व में 4 आरोपी जा चुके जेल

बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा में शामिल पटवारी को मोटी रकम मिली थी। यहां तक जमीन की हर रजिस्ट्री में उसे कमीशन भी मिलता था। सरकंडा पुलिस द्वारा पटवारी से पूछताछ की जा रही है। कुछ ...रियों के नाम सामने आ सकते हैं।

...का शामिल होना था तय

...न को फर्जी तरीके से भोंदूदास के नाम करने ...है। कंपनी की मिलीभगत के बिना दस्तावेजों ...सकती. पुलिस द्वारा जांच करने पर सबसे ...सामने आया। इस पर पुलिस ने उसे

...छेड़छाड़ करके हेमूनगर निवासी रिक्शा चालक भोंदूदास पिता छेदीदास मानिकपुरी (70) के नाम दर्ज कर दी गई।

मालवीय रोड की जमीन बेचेगा निगम

आर्थिक संकट

- 20 हजार वर्गफीट से मिलेगा 22 करोड़ रुपये
- डुमरतराई से 70 करोड़ कमाई के लिए विज्ञापन हुआ जारी

■ नवभारत रिपोर्टर | रायपुर
www.navabharat.news

नगर निगम की आर्थिक स्थिति एक बार फिर गड़बड़ाने लगी है. यही कारण है कि जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एजेंसी रामकी कम्पनी को लगभग 40 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया. वहीं वार्डों में सफाई कराने वाली एजेंसियों को भी 3 महीने का भुगतान नहीं हो पाया. इतना ही नहीं इन्हीं आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम अब मालवीय रोड स्थित पुराना निगम मुख्यालय भवन की जमीन को बेचकर 22 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रहा है. इस मामले में महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि पहले के मुकाबले निगम की राजस्व वसूली इस बार अच्छी रही. लेकिन हम शतप्रतिशत यूजर चार्ज की वसूली नहीं कर पाये. यह हमें केवल 22 करोड़ ही मिल पाया, जबकि इसकी वसूली 38 करोड़ तक होनी थी. उन्होंने बताया कि इसी यूजर चार्ज का पैसा रामकी कंपनी को कचरा परिवहन और प्रोसेसिंग के लिए देना है. केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन नियम में भी इसका

डुमरतराई से मिलेगा 70 करोड़

नगर निगम को डुमरतराई में स्थित 8 एकड़ जमीन से ही लगभग 70 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. यहां निगम की तीन अलग-अलग जमीनें हैं. मार्केट वेल्यू के हिसाब से एक 11 हजार 431 वर्गमीटर की और दूसरी 10 हजार वर्गमीटर एवं तीसरी जमीन लगभग 13 हजार वर्गमीटर की है. इन जमीनों का सौदा बोली के हिसाब से किया जाएगा.

उल्लेख किया गया है. निगम की इस जमीन पर राजस्व अधिकारियों ने बताया कि इसमें अभी नामांतरण के कारण आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है. एक बार नामांतरण होने के बाद इसे बेचने के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा.

जवाहरबाजार भी फ्री होल्ड- राज्य शासन द्वारा निगम की जमीन को फ्री होल्ड के तहत बेचने का आदेश जारी करने के बाद जवाहरबाजार में बनाई गई 150 दुकानों को भी फ्री होल्ड कर दिया जाएगा. बताया गया कि यह दुकानें अभी लीज पर दी गई है, इसीलिए फ्री होल्ड में दिक्कत नहीं आएगी. यहां कारोबारियों को दुकानों की कीमत का 2 प्रतिशत किराया देना होता है. फ्री होल्ड की दरें इसी आधार पर तय होंगी.

लैंड जेहाद: पुरखों की जमीन माटी के मोल बेची

पुरखों की जमीन बेच रही कंगाल सरकार कर्ज में डूबे हैं कांग्रेस के कर्जदार

सैकड़ों एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड को देने की साजिश रची जा रही है। यहां तक कि 'दावत ए इस्लामी' जैसे पाकिस्तान-स्थित आतंकी संगठनों को भी छत्तीसगढ़ में 25 एकड़ से अधिक जमीन देने का षड्यंत्र भाजपा द्वारा आवाज उठाने पर नाकाम कर दिया गया। राज्य की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव नीलाम की जा रही है। चिटफंड आदि के नाम पर भी जमीनों की बंदरबांट हो रही है। मंत्री जय सिंह अग्रवाल को 25 एकड़ की आदिवासियों से हड़पी हुई जमीन वापस करनी पड़ी। समूचे प्रदेश को देश भर के कांग्रेसियों का चारागाह बना दिया गया है। सुकमा में आदिवासियों की जमीन पर बना कांग्रेस कार्यालय भी रंगे हाथ भाजपा द्वारा पकड़ा गया।

5.70 एकड़ शासकीय और 5.50 एकड़ निजी भूमि का फर्जीवाड़ा

करोड़ों की जमीन का फर्जीवाड़ा तत्कालीन पटवारी गिरफ्तार

पुलिस को जांच में मिले थे कई सबूत, पूर्व में 4 आरोपी जा चुके जेल

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर। रिक्शा चालक भोंदूदास के नाम करोड़ों की शासकीय व अन्य भूमि के फर्जीवाड़ा मामले में सरकंडा पुलिस ने तत्कालीन पटवारी अशोक जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जीवाड़े में पटवारी की अहम भूमिका रही। इसके पूर्व भोंदूराम समेत 4 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। जिला प्रशासन व पुलिस को एक शिकायत मिली थी। इसमें यह बताया गया था कि खिलाटी,

पटवारी को मिली थी मोटी रकम

विभागीय लोगों का शा...

निगम की हर जमीन पर विवाद • भैंसथान को एजेंडे से निकालने के बाद भास्कर की पड़ताल

डूमरतराई, भैंसथान और मालवीय रोड की जमीन बेचकर 161 करोड़ रु. कमाना चाहता था निगम

भास्कर खास

भैंसथान विवाद

गंज मंडी विवाद

पुराना निगम मुख्यालय

पंडरी बस स्टैंड

राजस्व के लिए जमीन बेच सकते हैं...

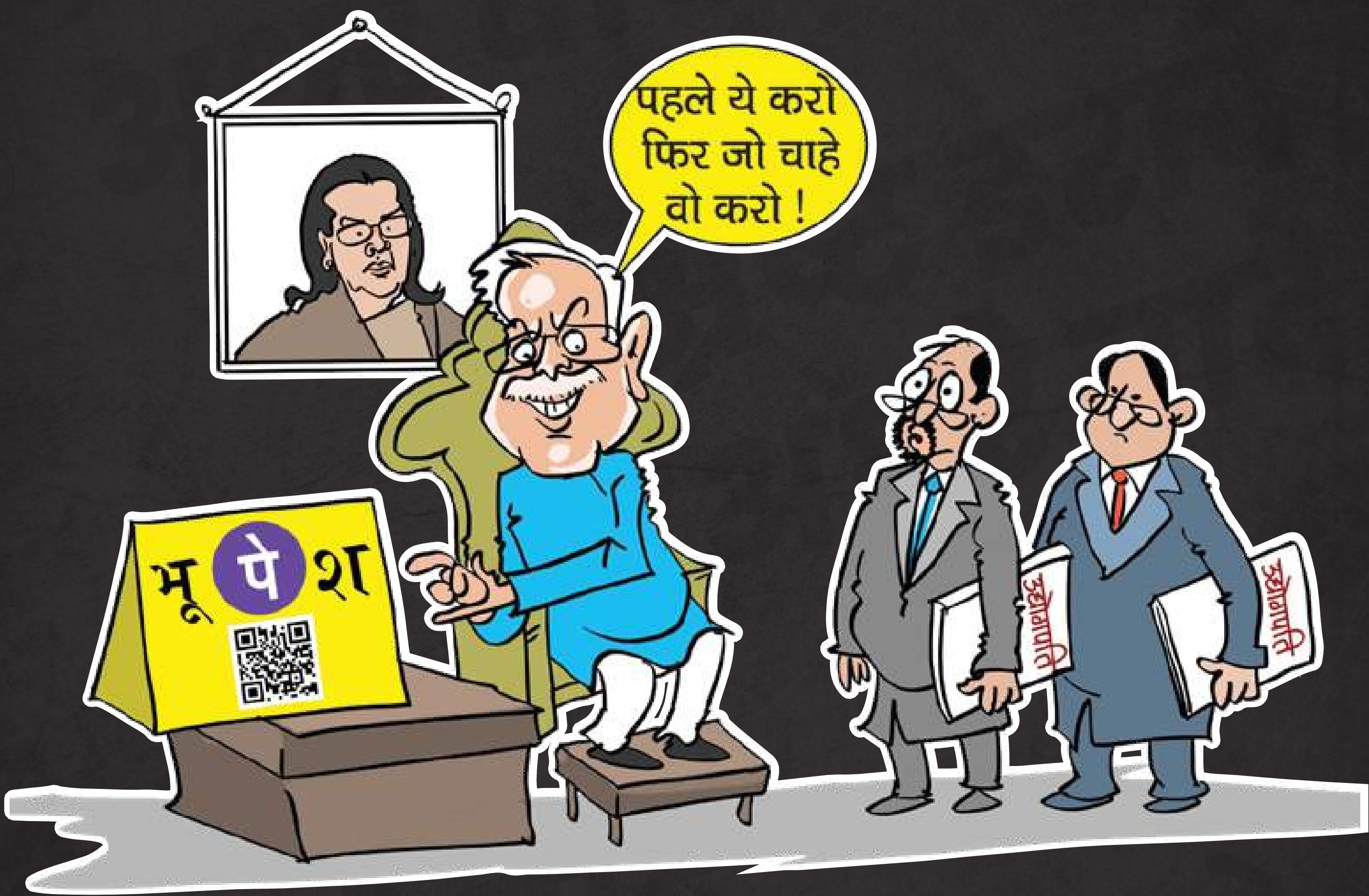
पहले ये करो
फिर जो चाहे
वो करो !
भू पे श
उद्योगपति
उद्योगपति

छीना शिक्षा का अधिकार भी

ढह रही है छतें और रिस रही बारिश के पानी से स्कूलों की दीवार, ये कौन सा शिक्षा का अधिकार

कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में लड़कियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त करने का वादा किया था, लेकिन और सब वादों की तरह इस वादे को भी नहीं निभाया। ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई उन योजनाओं को भी रोक दिया, जिसके अंतर्गत कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट मिलना था। बच्चों को आधुनिक सुविधायें मुहैया कराना तो फिर भी दूर की बात है, आज प्रदेश के बच्चे स्कूल एवं विश्वविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश में 34 वें स्थान पर है। प्रदेश में लगभग 8,164 लेक्चरर पद, 17,227 सहायक शिक्षक पद और 25,237 शिक्षक पद रिक्त पड़े हैं। यही स्थिति प्राचार्य, विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक, खेल शिक्षक, योग शिक्षक, लाइब्रेरियन एवं अन्य कर्मचारियों की है। ये कौन सा है शिक्षा का अधिकार?

भरीपारा आंगनबाड़ी केन्द्र भवन हुआ जर्जर

■ नवभारत रिपोर्टर। कोरबा
www.navbharat.news

बिहाबापारा पंचायत अंतर्गत आश्रित ग्राम भरीपारा में आंगनबाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है. इस भवन में छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ ही पौष्टिक आहार भी खिलाया जा रहा है. बिहाबापारा पंचायत के सरपंच एवं जिला पंचायत सदस्य तारा ठाकुर के साथ भरीपारा के पंचों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किए. निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी भवन जर्जर स्थिति में पाया गया. बरसात के दिनों में इस भवन से पानी का बहुत ज्यादा रिसाव होता है और कमरों के अंदर पानी का जमाव होता है जिससे बच्चों को बैठने की समस्या होती है तथा बरसात के मौसम में बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है. ऐसी स्थिति में पालक लोग बहुत चिंतित रहते है क्योंकि कभी भी खतरनाक हादसा हो सकता है ऊपर की प्लास्टर गिर सकता है. फोटो से स्पष्ट दिख रहा है कि यह भवन बहुत पुराना है. जनप्रतिनिधि के सामने लोगों ने अपनी समस्या को अवगत की. जिला पंचायत सदस्य तारा ठाकुर ने समस्या को ... कार्यवाही करने आश्वासन ... संबंधित विभाग को सूचना ... नए भवन बनाने के लिए मां... के प्रतिनिधियों ने नए ... शासन प्रशासन एवं ... भवनों की जांच पड़ता... चाहिए ताकि बच्चे ... संस्था को संचाल... अपना उत्तरदा...

स्कूल में बारिश का पानी, कई बच्चे पकड़ने लगे मछलियां

कोपरा प्राथमिक विद्यालय परिसर में पानी जाम होने से पालकों में नाराजगी

भोजन व्यवस्था का भी बुरा हाल

प्रदेश को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश

राज्य शिक्षा विभाग कर गया केन्द्रीय अनुदान हजम
अब भी भूपेश को नहीं आ रही शर्म

राज्य में शिक्षकों की इतनी कमी है कि प्रदेश के मासूम बच्चों को अपनी बात पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना पड़ रहा है। प्रदेश में लगभग एक लाख से अधिक लेक्चरर, सहायक शिक्षक, शिक्षक प्राचार्य, विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक, खेल शिक्षक, योग शिक्षक, लाइब्रेरियन एवं अन्य कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। देश स्तर पर शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है छत्तीसगढ़।

एक कमरे में लग रही पहली से पांचवीं कक्षा

अध्ययन करने बच्चे मजबूर, शासन-प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

बड़ा भर्ती विवाद

सितंबर 2021 में मंगाए आवेदन, उसके बाद अब तक ये तय नहीं कर पाए किस उम्र तक दें उम्मीदवारों को नौकरी

21 साल बाद 595 पदों पर हो रही प्रोफेसरों की भर्ती नियमों में अटकी

7 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने भरे थे फार्म, सबको अभी भी इंतजार

प्रमोशन से ही बन रहे प्रोफेसर कॉलेजों में

कई राज्यों में 58 और कुछ में 55 साल उम्र

विद्यार्थियों को असुविधाएं

विद्यार्थियों को नहीं उपलब्ध कराया परिवहन
भूपेश छात्रों के भविष्य का कर रहा दहन

जहां प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध ही नहीं है, वहाँ ठगेश सरकार कॉलेज व स्कूल के छात्र-छात्राओं को मुफ़्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने का खोखला वादा करके छलती रही है। आज भी ठगेश अपने कार्यक्रमों में इन झूठे वादों पर सवाल उठाए जाने पर पता नहीं किस मुँह से अपने अगले शासनकाल में इन्हे पूरा करने की सांत्वना देते फिर रहे हैं। ठगेश को अब तक यह आभास हो जाना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके झूठे वादों से त्रस्त हो चुकी है और इसी कारण वो अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच खो चुके हैं।

विद्यार्थियों और पालकों में आक्रोश व्याप्त

मजबूरी

जर्जर भवन में विद्यार्थी बैठने मजबूर

कभी भी हो सकती है बड़ी अनहोनी, अधिकारी ध्यान नहीं देते

आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में मिली अव्यवस्था
डीईओ, बीईओ को फटकार के साथ नोटिस

ये समस्याएं प्रमुखता से उठीं

सहायक शिक्षकों का दमन

सहायक शिक्षकों पर बढ़ा अत्याचार भूपेश राज में दमन के हुए शिकार

राज्य के सहायक शिक्षकों के साथ तो इस सरकार ने एक क्रूर और भद्दा मजाक किया है। अपने घोषणा पत्र में शिक्षकों से क्रमोन्नति का वादा तो कर लिया, पर आज पांच साल बाद भी राज्य के सहायक शिक्षक अपनी मांग पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अनेकों धरने और प्रदर्शन के बाद इन्हें कुछ मिला है, तो सिर्फ इनकी मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति और कुछ नहीं। उस समिति की कोई बैठक तक नहीं हुई है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के प्रमोशन होंगे रद्द: नए सिरे से होगी पोस्टिंग, मंत्री रविन्द्र चौबे ने दिए जॉइंट डायरेक्टर पर FIR के निर्देश

रायपुर 27

मंत्रालय में मंत्री रविन्द्र चौबे ने अधिकारियों की बैठक... में जल्द ही निर्देश जारी करेंगी।

शिक्षामंत्री रविंद्र चौबे ने सहायक शिक्षक पदोन्नति... हुए लेनदेन की पुष्टि के बाद सभी पोस्टिंग रद्द कर न... लिस्ट जारी करने को कहा है। साथ ही दोषियों पर एफ... दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक प्रमोशन के बाद संशो... पोस्टिंग लिस्ट को निरस्त किया जाएगा। वहीं निलंबित हुए स... जेडी के खिलाफ एफआईआर के भी निर्देश हैं।

GPM: वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सड़क पर शिक्षक, बोले- हर बार आश्वासन के बाद धोखा मिला

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन पिछले चार साल से एक सूत्रीय मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर करने को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए से शिक्षा विभाग के अफसरों तक संघर्ष जारी है। इसी मांग को लेकर एक बार फिर शिक्षक फेडरेशन ने मंगलवार को एक दिवसीय प्रदर्शन किया। इस दौरान काम-काज बंद कर दिए गए। इसके बाद शिक्षक सड़क पर बैठ गए और हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया।

सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ धोखा

खिलाड़ियों के भविष्य से खेल गए खेल
भ्रष्ट है कांग्रेस, ठग है भूपेश बघेल

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को नौकरियां दी जाती थी। परन्तु कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया। आज प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने 20 नए खेल जिसमें मलखंभ और रस्साकशी जैसे खेल शामिल हैं को ऐसी सूची में शामिल किया है, जिससे खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। इससे इन खिलाड़ियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। राज्य में भी खिलाड़ी इन खेलों को पात्रता की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, पर भूपेश सरकार ने इसपे कोई ध्यान नहीं दिया है।

उत्कृष्ट खिलाड़ी शासकीय सेवा के लिए भटक रहे, शासन की रुचि नहीं

बिलासपुर(नईदुनिया न्यूज)। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 22 वर्ष बाद भी राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। यह खिलाड़ियों के साथ अन्याय है। खिलाड़ियों को दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ ताइक्वांडो यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मुकेशपुरी गोस्वामी ने कहा...

महिला खिलाड़ी के लिए शासकीय नौकरी व प्रोत्साहन राशि की मांग

रायपुर@ पत्रिका. पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुकुरबेड़ा झुग्गी बस्ती में रहने वाली ऑटो चालक पूर्णो सोना की 19 वर्षीय बेटी गंगा सोना का चयन सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एशियन गेम्स के लिए किया है। सामाजिक संस्था डॉ. आंबेडकर अधिकार मंच के अध्यक्ष अधिवक्ता भगवानू नायक ने छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक, ...ली क्षण और सुनहरा अवसर ... उन्होंने कहा, झुग्गी बस्ती में ...ली सॉफ्टबॉल की महिला ... गीता सोना का चयन

छत्तीसगढ़ में पहली बार खिलाड़ियों का प्रदर्शन: खेल विभाग का किया घेराव और मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

हक और अधिकार के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी उतरे सड़क पर

प्रदर्शन : खिलाड़ियों ने खेल विभाग का फिर किया घेराव, राज्य खेल अलंकरण समारोह के आयोजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा जल्द करने के लिए सौंपा ज्ञापन

खिलाड़ी फिर उतरे सड़क पर, मुख्यमंत्री से सम्मान करने की लगाई गुहार

मरता नौनिहाल-सिसकता बचपन

अस्पताल खस्ताहाल, मरीज लाचार
राज्य को बीमार कर रही भूपेश सरकार

- भूपेश सरकार की लापरवाही और कुप्रशासन के कारण आज प्रदेश में 40 हजार से अधिक माताओं की गोद सूनी हो गई। प्रदेश में 39,267 बच्चों की इलाज आदि के अभाव में मौत की बात कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में स्वीकार की है। प्रदेश में शिशु व मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होना सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। आज छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 2016-17 में 38 बच्चे प्रति हजार मृत्यु से बढ़कर 2020-21 में 41 बच्चे प्रति हजार हो गयी हैं। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 2015-16 में 141 प्रति लाख से बढ़कर 159 प्रति लाख हो गयी जो दर्शाता है की कांग्रेस सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी गंभीर है। इससे पहले राज्य के आंकड़े के आधार पर ही राज्यसभा में खुलासा हुआ था कि मात्र तीन वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों के 25 हजार से अधिक बच्चों की इलाज के अभाव में मौत हो गयी। साथ ही 955 महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हुई।

- स्वास्थ्य विभाग में उपकरण और दवा खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपयो का भ्रष्टाचार किया गया है। कोरोनाकाल से लेकर अभी तक करोड़ों रुपयों में खरीदी गयी गुणवत्ताहीन पेट स्कैन, गामा मशीन, वेन्टीलेटर आदि उपकरण अस्पतालों में धूल खा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के ढाई-ढाई साल बंटवारे से स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच छिड़ी गैंगवार के कारण अस्पतालों की दुर्व्यवस्था हुई। छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुई आयुष्मान योजना को ढंग से लागू नहीं कर पाने की विफलता तथा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। कांग्रेस के कुप्रशासन ने छत्तीसगढ़ के कितने घर सूने कर दिए।

सरकारी दावों की पोल खोल रहा पंडरिया का अस्पताल

छत्तीसगढ़ में 3 वर्ष में 25000 आदिवासी बच्चों ने तोड़ा दम

डायरिया से तीन मौत हुई तो चंदा जमा किया, बैगा बुला कर गांव बंधवाया

सौ बिस्तर हास्पिटल भवन का अता-पता नहीं

आंगनवाड़ी कर्मियों के रिक्त पदों को नहीं भरने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़

कहत संगवारी छत्तीसगढ़ महतारी, कांग्रेस सरकार हे हत्यारी

पिछली सरकार में नई आंगनवाड़ियों की मंजूरी के साथ-साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद भी स्वीकृत किए गए थे। जिसके विपरीत, कांग्रेस सरकार ने नई आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद भरने की मंजूरी नहीं दी है। सहायिकाओं के 7 हजार पद रिक्त हैं, जिससे राज्य के बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में है। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग सभी योजनाएं ठप होती जा रही है। यही कारण है कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है।

ज्ञापन सौंपा: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कहा महंगाई बढ़ी, 6 साल से मानदेय जस का तस

बालोद 15/11/22

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन सीटू के आह्वान पर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को नया बस स्टेंड में धरना प्रदर्शन किया। तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया।

Korba News : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की हड़ताल 18 वें दिन भी जारी

छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के संघ के तत्वावधान में महिलाएं 23 जनवरी से प्रदर्शन कर रही हैं।

YOGESHWAR SHARMA
Updated Date: | Wed, 22 Feb 2023 12:19 AM (IST)
Published Date: | Wed, 22 Feb 2023 12:19 AM (IST)

मातृशक्ति: ना दी कोई सुरक्षा और छीन लिया महिलाओं का रोज़गार

महिलाओं की सेहत से खिलवाड़, छीना उनसे रोजगार - कब तक मौन रहेगी भूपेश सरकार

भूपेश सरकार ने भारी कमिशनखोरी के लिए 22,000 स्व-सहायता समूह की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की थोथी बात करने वाली भूपेश सरकार ने महिला स्व-सहायता समूह के आंगनवाड़ी बच्चों और माताओं के लिए रेडी टू ईट भोजन बनाने के काम को बड़े उद्योगपति को भारी कमीशनखोरी के चलते दे दिया। कांग्रेस सरकार ने न केवल स्व-सहायता समूहों की 22,000 से अधिक महिलाओं की रोजी रोटी छीनी, बल्कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ख़राब खाना देकर उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया और छत्तीसगढ़ के भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिया। निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने छीन ली मां-बहनों की रोजी-रोटी।

भारत

छत्तीसगढ़: बीजेपी ने एसएचजी का पक्ष लिया, रेडी-टू-ईट मील कदम पर सरकार पर हमला किया

पीटीआई

रायपुर, 11 मार्च (भाषा) विपक्षी भाजपा ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर महिला स्वयं सहायता समूहों से रेडी-टू-ईट पोषण आहार तैयार करने का काम राज्य संचालित बीज निगम को स्थानांतरित कर उनके रोजगार के अवसर छीनने का आरोप लगाया। एक निजी फर्म.

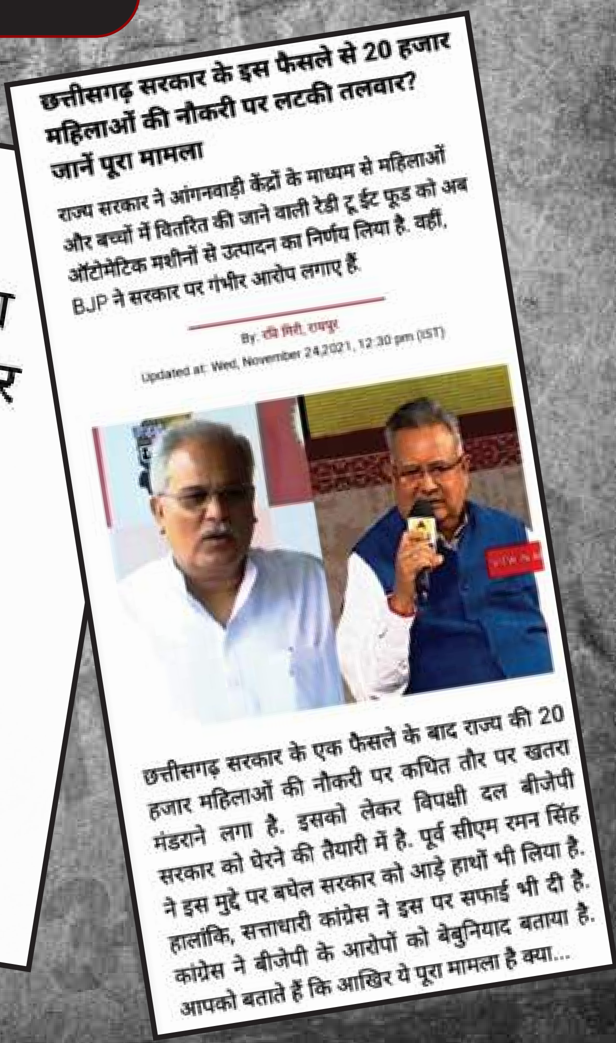

छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से 20 हजार महिलाओं की नौकरी पर लटकी तलवार? जानें पूरा मामला

राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में वितरित की जाने वाली रेडी टू ईट फूड को अब ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादन का निर्णय लिया है. वहीं, BJP ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By: रवि गिरी, रायपुर

Updated at: Wed, November 24,2021, 12:30 pm (IST)

छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले के बाद राज्य की 20 हजार महिलाओं की नौकरी पर कथित तौर पर खतरा मंडराने लगा है. इसको लेकर विपक्षी दल बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है. पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस मुद्दे पर बघेल सरकार को आड़े हाथों भी लिया है. हालांकि, सत्ताधारी कांग्रेस ने इस पर सफाई भी दी है. कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या...

1 लाख से अधिक बेटियां गायब

नारी सुरक्षा में भूपेश नाकाम
मानव तस्करी पर नहीं लगा लगाम

पिछले 56 माह में 1 लाख से अधिक छत्तीसगढ़िया बच्चियों के गायब होने की पुष्टि हुई है। केवल पिछले 3 वर्ष में ही प्रदेश की 59 हजार से अधिक महिलायें/बच्चियां गायब हुई हैं। कांग्रेस सरकार ने सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ को मानव तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया गया है। ये बेटियां कहां ले जाई गईं, इसकी कोई जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

छत्तीसगढ़ से 3 साल में 59 हजार महिलाएं और लड़कियां लापता

एनसीआरबी के 2019 से 2021 तक के आंकड़ों में मप्र पहले, प. बंगाल दूसरे स्थान पर

देश में 3 साल में 13 लाख किशोरियां और महिलाएं लापता

युवक और महिला मित्र पर मानव तस्करी का केस

शपथ-पत्र में युवती को पत्नी बता गुजरात ले जाने की थी तैयारी, कोर्ट में पकड़ा गया था आरोपी युवक

हमारी बेटियों को नौकरी-काम के लिए ले गए थे, फिर बेच दिया... अब कोई नहीं बताता- बेटियां कहां हैं?

मध्यप्रदेश में सबसे अधिक, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल

तीन साल में 13 लाख लड़कियां-महिलाएं गायब

सरकार बोली कानून को और कठोर बनाया

केंद्रशासित प्रदेश में शीर्ष पर दिल्ली

विधवाओं के प्रति संवेदनहीन सरकार

दिवंगत शिक्षकों की विधवाएँ अब तक बेरोजगार
वोट बैंक की राजनीति कर रही भूपेश सरकार

कांग्रेस नेताओं ने पंचायत स्तर के स्कूलों में पढ़ाने वाले दिवंगत शिक्षाकर्मियों की विधवा पत्नियों से पिछले चुनाव से पहले मिलकर झूठा वादा किया था कि वो नियमों को सरल कर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दिलवा देंगे। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार तो बना ली पर सामान्य से नियम भी नहीं बदले, जिससे इन परिवारों का भला हो पाता। इस असंवेदनशील कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी का दंश झेल रही शिक्षाकर्मियों की विधवाएं, आज इस सरकार के नेताओं को उनका वादा याद दिलाने कहीं जल समाधि ले रही हैं, कहीं अपनी ही शव यात्रा निकाल रही हैं और कहीं सरेआम सिर मुंडवा रही हैं। परन्तु, झूठे वादे कर सत्ता आनंद ले रहे कांग्रेस नेताओं के कान में जूं तक नहीं रेंग रही।

शिक्षकों की विधवाओं ने किए जूते पॉलिश: अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने से परेशान महिलाएं आंदोलन पर, पूछ रहीं- छोटे-छोटे बच्चे कैसे पालें

रायपुर 20/12/21

सरकार, अब तो दया कीजिए...

महिलाओं ने जूते पॉलिश कर विरोध जताया।

शिक्षकों की मौत के बाद अब उनकी विधवाएं सड़क पर जूते पॉलिश करने को मजबूर हैं। सोमवार को रायपुर के बूढ़ातालाब की सड़क के किनारे महिलाओं ने राहगीरों के जूते पॉलिश किए। बदले में लोगों ने जो 10-20 रुपए दिए उससे ही अब अपने आंदोलन का खर्च ये महिलाएं चलाएंगी। 6 दिसंबर से ये सभी महिलाएं रायपुर में धरना दे रही हैं। कोई जांजगीर से पहुंचा है तो कोई राजनांदगांव से। बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग से भी महिलाएं यहां पहुंची हैं।

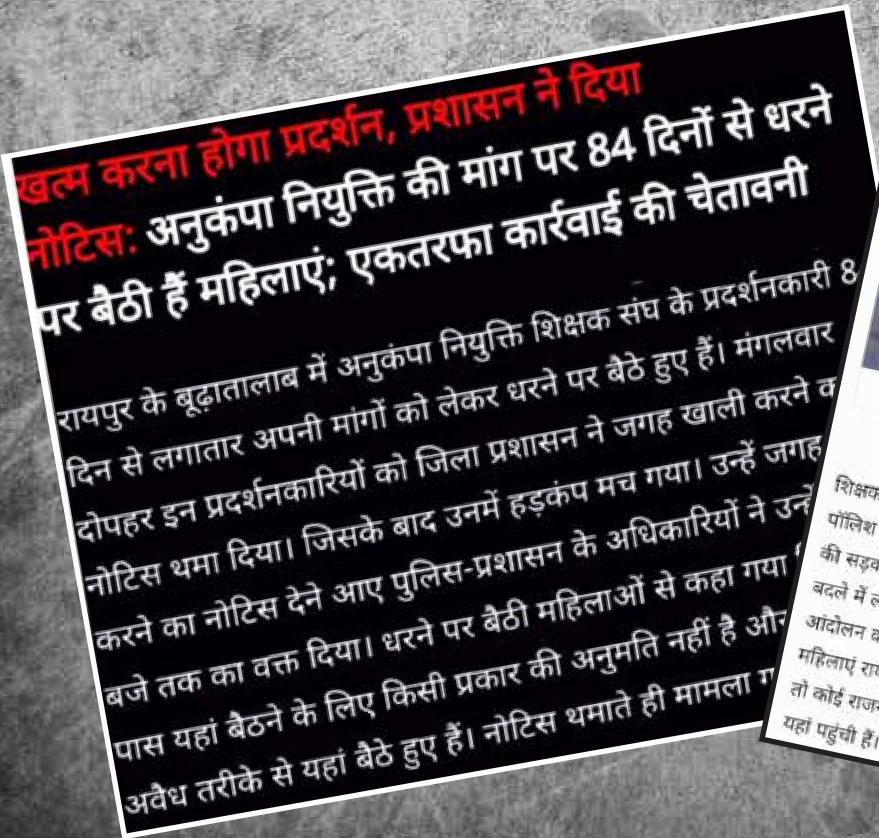

खत्म करना होगा प्रदर्शन, प्रशासन ने दिया नोटिस: अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर 84 दिनों से धरने पर बैठी हैं महिलाएं; एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी

रायपुर के बूढ़ातालाब में अनुकंपा नियुक्ति शिक्षक संघ के प्रदर्शनकारी 8
दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मंगलवार
दोपहर इन प्रदर्शनकारियों को जिला प्रशासन ने जगह खाली करने क
नोटिस थमा दिया। जिसके बाद उनमें हड़कंप मच गया। उन्हें जगह
करने का नोटिस देने आए पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने उन
बजे तक का वक्त दिया। धरने पर बैठी महिलाओं से कहा गया
पास यहां बैठने के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं है औ
अवैध तरीके से यहां बैठे हुए हैं। नोटिस थमाते ही मामला

वृद्धों का पेंशन भी हड़पा

पेंशन की उम्मीद में तरसी प्रदेश की बूढ़ी आँखें

प्रदेश के बच्चे हो या बूढ़े, इस संवेदनहीन सरकार ने हर छत्तीसगढ़िया को ठगा है। वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को वैसे तो बढ़ा कर ₹ 1,500 पेंशन देने का वादा इस सरकार ने किया था, पर सरकार बनते ही इस वादे को भी भूल गयी। आज हमारे बड़े-बूढ़े अपने हक़ के लिए सरकार की तरफ ताक रहे हैं, पर भूपेश सरकार ने इनकी तरफ एक बार पलट कर भी नहीं देखा है। केंद्र से आए पेंशन आदि की राशि का भी बंदरबांट करने में नहीं हिचकती यह सरकार।

दिव्यांगों का अपमान

दिव्यांगों का बनाया भूपेश ने मजाक छीना उनका अधिकार, सपने किए राख

कांग्रेस ने शुरू से ही प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है और इसी क्रम में इन्होंने प्रदेश के दिव्यांगों को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने पंचायतों व नगरीय निकायों में दिव्यांगों के जन-प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का वादा किया था, परंतु जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने दिव्यांगों के साथ ऐसा भद्दा मजाक करके उनका अपमान किया है। जहाँ भाजपा "सबका साथ सबका विकास" को अपनी प्रेरणा मान के कार्य करती है, वहीं कांग्रेस कमज़ोर वर्गों की जगह अपने कार्यकर्ताओं के पालन-पोषण पर ध्यान देती है।

उज्ज्वल दिव्यांग संघ ने की 2 हजार पेंशन देने की मांग

भास्कर न्यूज | राजिम

उज्ज्वल दिव्यांग कल्याण संघ ने दिव्यांग जनों की समस्याओं को लेकर जिलाधीश प्रभात मलिक से भेंट कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग संघ के जिला अध्यक्ष जागेश्वर साहू ने बताया कि वर्ष 2002 के सर्वे सूची में नाम नहीं होने से बहुत से दिव्यांग पेंशन से वंचित हैं। वर्ष 2002 के बाद पैदा हुए दिव्यांगजन व दिव्यांगताग्रस्त हुए लोगों को पेंशन राशि नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 2 मई 2003 को लागू करते हुए समस्त दिव्यांग जनों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाना चाहिए व 2002 के सर्वे की अनिवार्यता खत्म करना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों महिला समूहों व अन्य लोगों का जिस प्रकार ऋण माफ किया है उसी प्रकार निशक्त व्यक्तियों को जो स्वरोजगार हेतु ऋण लिया गया था उस ऋण को सरकार द्वारा माफ किया जाए।

अन्य राज्यों की तुलना में यहां सबसे कम है पेंशन

अन्य दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में दि... जनों को सबसे ... मिलती है। हम ले... अन्य राज्यों की त... 2000 हजार रुपए ... जाए। ग्राम पंचायत, ज... पंचायत, जिला पंचायत ... ही दिव्यांगजनों को प्रतिनि... दिया जाये। प्रत्येक दिव्यांग ... आवास योजना एवं शौचालय ... निर्माण में प्राथमिकता दी जाए। ज्ञापन सौंपने वालो में दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष जागेश्वर साहू के साथ, उपाध्यक्ष अमरसिंह ध्रुव, दिव्यांग संघ के प्रमुख सलाहकार दानसिंग निषाद, सचिव संतोष साहू, कोषाध्यक्ष पन्ना लाल सिन्हा, संयुक्त सचिव सुनिता साहू, महामंत्री कामता प्रसाद आदि रामप्रसाद शामिल थे।

1 2 3 4

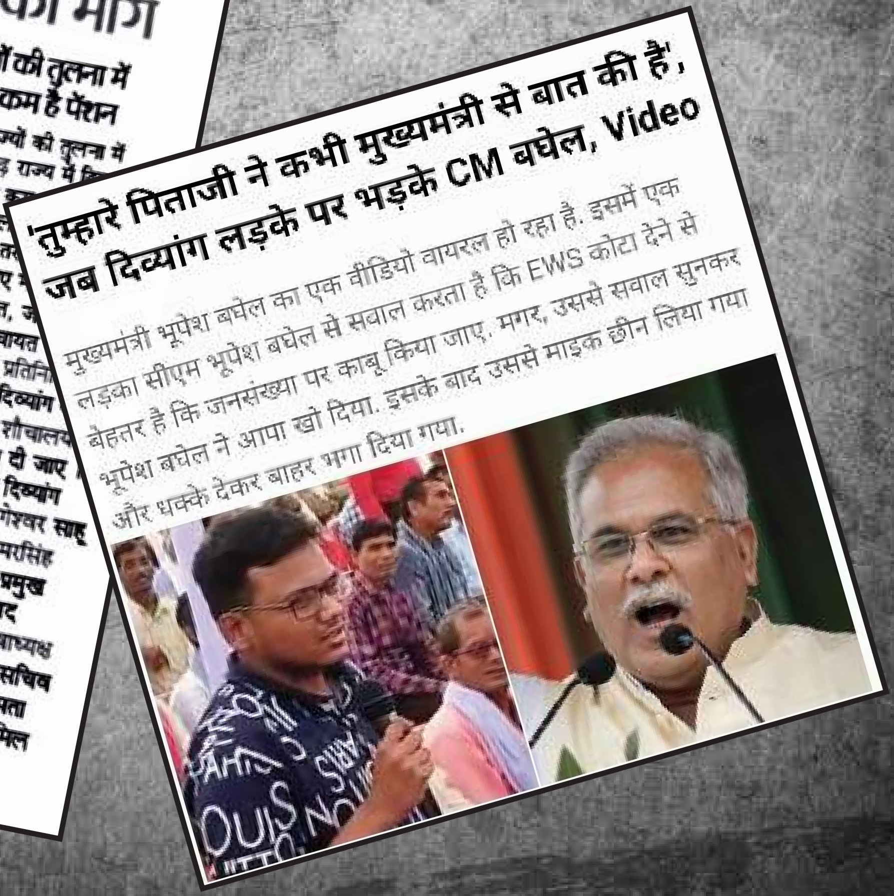

'तुम्हारे पिताजी ने कभी मुख्यमंत्री से बात की है', जब दिव्यांग लड़के पर भड़के CM बघेल, Video

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़का सीएम भूपेश बघेल से सवाल करता है कि EWS कोटा देने से बेहतर है कि जनसंख्या पर काबू किया जाए. मगर, उससे सवाल सुनकर भूपेश बघेल ने आपा खो दिया. इसके बाद उससे माइक छीन लिया गया और धक्के देकर बाहर भगा दिया गया.

पुलिस के साथ अत्याचार

कांग्रेस राज में प्रशासन को नहीं मिल रहा अनुदान
पुलिस ने भूपेश के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान

कांग्रेस सरकार ने पुलिस कल्याण कोष को अनुदान प्रदान करने के नाम पर सिर्फ खोखले वादे किए हैं। आज पुलिस परिजनों के द्वारा जब अपनी मांगों व सरकार के द्वारा जो वादा किए गए थे उसको पूर्ण करने के लिए आंदोलन किए गए तो उज्जवल दीवान व संजीव मिश्रा जैसे पुलिस वालों के ऊपर पुलिस द्रोह का केस लगा कर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। नौबत यहां तक आ गई है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मचारियों ने सरकार की नाकामी से तंग आकर अपनी एक राजनैतिक पार्टी बना चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुलिस कल्याण के लिए बड़े-बड़े वादे तो किए, परंतु चुनाव जीतने के बाद उन्हें ठंडे बस्ते में डाल कर छोड़ दिया।

पुलिस कर्मी पर हमला करने वालों को छोड़ दिया गया

नवभारत रिपोर्टर ।खरोरा।

पुलिस पर बेकसूर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप

फर्जी मुठभेड़ का लगाया आरोप

नक्सलियों की जगरगुण्डा व कोन्टा एरिया कमेटी ने जारी किया प्रेसनोट

नवभारत रिपोर्टर। दोरनापाल।

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों का कब्रगाह बना दिया प्रदेश को

पंडो जनजाति का किया तिरस्कार
प्रदेश में हारेगी भूपेश सरकार

भारत के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के पंडो, कोरवा और पहाड़ी कोरवा आदिवासियों में मृत्यु का दर बढ़ा है। मात्र चार महीने के दौरान 29 कोरवा आदिवासियों की असमय मृत्यु हुई। सिर्फ बलरामपुर जिले में ही सैकड़ों की संख्या में पंडो जनजाति के लोग टीबी व अन्य बीमारियों से प्रभावित हुए हैं और समय पर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण असामयिक मृत्यु हुई है। छत्तीसगढ़ के समाज का एक अभिन्न अंग-कोरवा समाज की दयनीय हालत बना देने के लिए जिम्मेदार केवल कांग्रेस की सरकार है।

Surajpur: पंडो बाहुल्य बस्ती के बच्चे बारिश में जान जोखिम में डालकर जाते हैं स्कूल, टापू बन जाता है गांव

Chhattisgarh: ग्राम पंचायत दुर्गापुर और कांदाबाड़ी के बीच स्थित नदी पर पुल नहीं होने के कारण बरसा... में नदी पानी से पूरी तरह भर जाती है. अ... होने के कारण वाहनों के पहिए थम जाते...

अमितेष पांडे, अम्बिकापुर

Sat, July 22,2023, 1:38 pm (IS...

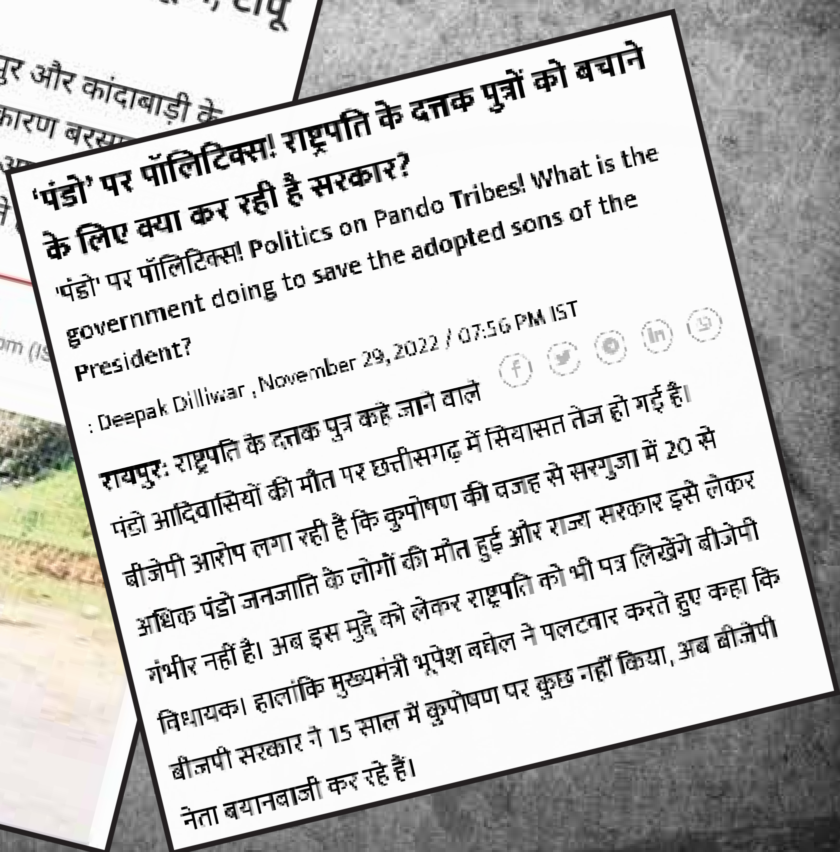

'पंडो' पर पॉलिटिक्स! राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को बचाने के लिए क्या कर रही है सरकार?

'पंडो' पर पॉलिटिक्स! Politics on Pando Tribes! What is the government doing to save the adopted sons of the President?

: Deepak Dilliwar , November 29, 2022 / 07:56 PM IST

रायपुर: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले
पंडो आदिवासियों की मौत पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है।
बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुपोषण की वजह से सरगुजा में 20 से
अधिक पंडो जनजाति के लोगों की मौत हुई और राज्य सरकार इसे लेकर
गंभीर नहीं है। अब इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति को भी पत्र लिखेंगे बीजेपी
विधायक। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि
बीजेपी सरकार ने 15 साल में कुपोषण पर कुछ नहीं किया, अब बीजेपी
नेता बयानबाजी कर रहे हैं।

जंगल में वन्य प्राणी तस्करों का साम्राज्य

पशु तस्करों का बढ़ रहा व्यापार
लगाम लगाने में नाकाम भूपेश सरकार

प्रदेश में हर रोज़ कहीं बाघ की खाल मिल रहा है, तो कहीं तेंदुआ की खाल और कहीं पैंगोलिन के शव बरामद हो रहे हैं। हाथी का भी शिकार हो रहा है। राज्य में 27 से अधिक बाघ गायब हैं, चार साल में बीस से अधिक बाघों के खाल बरामद हुए हैं। इसमें सिर्फ कांकेर, गरियाबंद, कवर्धा और राजनांदगांव जिले में 11 से अधिक बाघ के खाल जब्त हुए हैं। विलुप्त हो रहे पैंगोलिन तक की जब्ती शिकारियों से हो रही है। सत्ता के संरक्षण में समूचे प्रदेश में माफियाओं ने कहर बरपा दिया है। घोषणा पत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने की डींगें हांकने वाली कांग्रेस के राज में बाघों को पकाकर खा लेने जैसी वारदातें भी सामने आ रही हैं।

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बेखौफ गौ तस्कर, गो वंश से भरी पिकअप वाहन पकड़े गये

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी लंपी वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने जिले के पशु बाजारों ... अगले आदेश तक मवेशियों के खरीदी- बिक्री ... दिया है

गो वंश से भरी पिकअप वाहन

आरोप • साढ़े सात लाख में किया था सौदा, रुपए दे भी दिए थे

बाघ की खाल के सौदे के मामले में सीआरपीएफ अफसर भी आरोपी

वन विभाग ने अफसर को दिल्ली से बीजापुर बुलाने कहा

बाघ के अवशेष बरामद

आंध्र के गांव में फंसा था बाघ

दो तस्कर गिरफ्तार: खेतों में घूम रहे गाय-बैलों को बना रहे थे बंधक; कुछ दिन पहले हमले में हुई एक गाय की मौत

...मुंडा क्षेत्र में ही हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं। एक घटना ...सी ने गाय की जान लेने का प्रयास किया था। हालांकि ...के दौरान गाय को बचाया नहीं जा सका और उसकी ...ई। आरोपी की तलाश जारी है। वहीं दूसरी घटना ...र नुकीले और धारदार हथियार से वार किया ...उपचार के दौरान गोसेवकों ने बचा लिया है।

मानव-हाथी संघर्ष में भी भ्रष्टाचार!

गजराज योजना हकीकत से हुई दूर
जनता पलायन को हुई मजबूर

आज भी छत्तीसगढ़ में मानव-हाथी संघर्ष के कारण सैंकड़ों लोगों की मौतें हो रही हैं और प्रदेश की जनता अपना घर-बार छोड़ कर पलायन करने को विवश है। अगर आंकड़ों पे ध्यान दें, तो सिर्फ 2018-22 के बीच 1 लाख से अधिक मामले सामने आएं हैं, जहाँ किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 11,659 घर क्षतिग्रस्त हुए और 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। इन सब के बावजूद इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार के ठोस कदम तो नहीं ही उठाये हैं, बल्कि हाथियों को धान खिलाने के नाम पर अधिक मूल्य पर धान खरीदी दिखाकर करोड़ो रुपये का भ्रष्टाचार कर दिया।

नेंदुटिकरा के ग्रामीण तीन दिनों से घर बार छोड़कर लिए हुए हैं शरण

हाथियों से जान बचाने खुले आसमान के नीचे छत पर गुजार रहे हैं रात

हाथियों ने सांकरा बीट में डारा डेरा, अलर्ट जारी

अंगारा में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात

आधा दर्जन से अधिक मकानों को किया गया क्षतिग्रस्त, ग्रामीण दहशत में

तीन दलों में 58 हाथी बने खतरा, लगेगा कॉलर आईडी

पहले सिकासर दल को लगेगा कालर आईडी, क्योंकि खतरा सबसे ज्यादा इसी से

प्रदूषण की बढ़ती दर

प्रदेश में प्रदूषण ने पसारे अपने पांव
अधर में अटकी कांग्रेस की नाव

राज्य के कई ज़िले प्रदूषण का कहर झेल रहे हैं, जिससे लोगों को अस्थमा और एलर्जी जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। वायु प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार, जाँजगीर-चांपा, बिलासपुर, कबीरधाम, कोरबा, रायगढ़ और दुर्ग जैसे ज़िलों में अति उच्च प्रदूषण का स्तर दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, राज्य के दो शहर रायगढ़ और कोरबा नासा की 2019 की रिपोर्ट में दुनिया के 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थानों की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की रिपोर्ट के अनुसार सिलतरा, रायपुर, कोरबा, भिलाई और दुर्ग जैसे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र देश के शीर्ष 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों में से एक हैं। हाल ही में, छत्तीसगढ़ राज्य संसाधन केंद्र ने एक प्रदूषण सर्वेक्षण किया, जिसमें रायपुर और कोरबा में प्रदूषण के खतरनाक स्तर का पता चला है। प्रदूषण का स्तर राष्ट्रीय मानक से क्रमश: 11 और 28 गुना तक अधिक पाया गया है।

प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण विभाग गंभीर

प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण विभाग गंभीर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पर्यावरण विभाग बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब गंभीर हो गया है. इसी क्रम में प्रदेश के तमाम पावर प्लांट को नोटिस जारी कर उससे निकलने वाले राखड़ के निष्पादन के लिए सख्त आदेश जारी किया है.

इसके साथ ही कलेक्टर ओपी चौधरी ने प्रदेश के सभी पर्यावरण विभाग को इस आदेश के परिपालन में पत्र जारी किया है. साथ ही कहा है कि आदेश की अवहेलना करने वाले उद्योगों पर जल और वायु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ज्यादा जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी आर. के. शर्मा ने कहा कि राज्य में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) समेत 20 से ज्यादा कोल माइंस संचालित है. उन्होंने कहा कि राज्य में सरप्लस बिजली के लिए कोयला पावर प्लांट में जाता है.

स्व-संज्ञान : कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई

प्लांटों में प्रदूषण से बीमार पड़ रहे श्रमिक, न्यायमित्रों को 28 अगस्त तक रिपोर्ट देने के निर्देश

बिलासपुर @ पत्रिका. प्रदेशभर के विभिन्न प्लांटों में धुएं और धूल की वजह से बीमार पड रहे श्रमिकों के मामले में एक साथ कई जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इसके लिए नियुक्त न्यायमित्रों को अदालत ने राज्यभर के उद्योगों की संबंधित डाटा रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

प्रदेशभर में संचालित तमाम प्लांटों में काम करने वाले मजदूरों को सीमेंट और लोहे की डस्ट से बहुत परेशानी होती है। इसके कारण मजदूरों के फेफड़े बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट में उत्कल सेवा समिति, लक्ष्मी चौहान, गोविन्द अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल और एक स्व-संज्ञान मामले में जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के कई राज्यों को भी ऐसी ही स्थिति को लेकर निर्देशित किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में एडवोकेट प्रतीक शर्मा और पीआर पाटनकर को न्यायमित्र नियुक्त किया था। इन्हें अदालत ने प्रदेश की इन औद्योगिक इकाईयों में प्रदूषण के कारण हो रही परेशानी के बारे में जानकारी मंगाई थी। शासन के वकील ने बताया था कि,राज्य में करीब ऐसे 60 स्पंज आयरन या सीमेंट प्लांट हैं, जहां इस प्रकार की शिकायत आ रही है। बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने न्यायमित्रों को 28 अगस्त तक डाटा रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसमें यह बताया जाना है कि, कितने लोग प्रभावित हैं और इनके लिए क्या किया जा रहा है।

तोर रद्दा ला बनवा दे ओ दाई माता बंजारी ओ

भूपेश राज में सड़कें हुई लहूलुहान
सड़क दुर्घटना में जा रही लोगों की जान

हालात यह है कि प्रदेश के कलाकार को सड़क पर लोट कर बंजारी माता से प्रार्थना करना पड़ रहा है कि सरकार को सद्बुद्धि दें। कांग्रेस ने एक किलोमीटर की भी कोई नई सड़क का निर्माण तो नहीं ही किया, वह किसी भी सड़क की मरम्मत तक नहीं करा पायी। इस संबंध में एक मंत्री का गैर जिम्मेदार बयान था कि "सड़कें खराब होने से दुर्घटना कम होती है इसलिए ऐसा किया गया है"। केंद्र से गांव की सड़क बनवाने के लिए जो पैसे मिलते रहे हैं, उसे धरातल से नदारद कर अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से सीधे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कॉन्ट्रैक्टरों की जेब में डाला जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि हाल ही में आई कैग रिपोर्ट, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संवैधानिक बाध्यता के कारण सार्वजनिक करना पड़ा, में छत्तीसगढ़ में बनी 93% सड़कें गुणवत्ता के तय मापदंड से बत्तर पाई गई। गुणवत्ताहीन सड़कों पे हादसे बढ़े हैं, पर कांग्रेस सरकार को क्या, इन सड़कों पर तो अब जनता को गिरना-मरना है।

नागरिक अव्यवस्था के गुलाम... 25 किमी की सड़क पर बसा लिया गड्ढों ने घर

शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर सड़कों से लोग हलाकान

तिल्दा सोमनाथ जाने वाली खाली सड़क खराब, करोड़ों की सीसी रोड खोद डाली गई

तिल्दा जनपद की सड़कों पर फीटभर के कई गड्ढे, बारिश से उखड़ा डामर

सीसी रोड खोदने वाले ठेकेदारों पर जनपद पंचायत नहीं कर रही कार्रवाई

सुरेगांव से बीजाभाठा 7.56 किमी लंबी सड़क पर गिट्टी बिछाकर छोड़ दिया, लोग परेशान

निर्माण कार्य ठप

न बनी सड़क, ना ही बना अस्पताल
कांग्रेस लाई फिर से आपातकाल

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच भाजपा सरकार के अंतर्गत सडकों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अनुमान में 54.93% की वृद्धि हुई थी। जोकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच कांग्रेस सरकार के अंतर्गत मात्र 6.76% रही है। सडकों और पुलों के निर्माण में की गई वित्तीय कटौती और कुप्रबंधन का ही परिणाम है कि, हालही में विधानसभा में साझा की गई सीएजी (कैग) की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बनी 93% सड़के अमानक पाई गई, वो तय मापदंड को प्राप्त करने में असफल रही। नए अस्पताल भी नहीं बन पाए और इलाज के अभाव में हज़ारों गरीब दलित और आदिवासियों की जान चली गई। कांग्रेस सरकार ने राज्य में एक भी नए उच्च शिक्षण संस्था का निर्माण नहीं किया। तेजी से आगे बढ़ रहे छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य अपने भ्रष्टाचार के चलते ठप कर कांग्रेस ने प्रदेश को अंधकार की गर्त में ढकेला है। इसका दुष्परिणाम अब प्रदेश की जनता भुगत रही है, जबकि कांग्रेस नेता मौज में हैं।

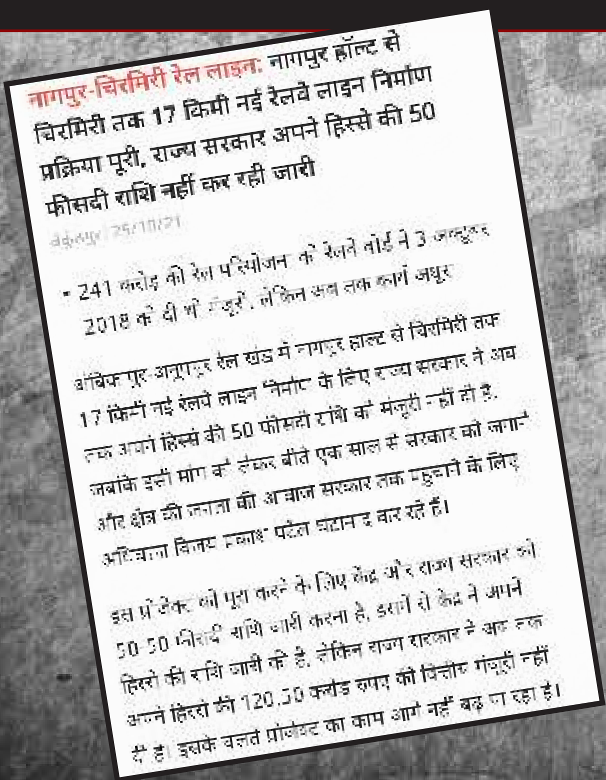

नागपुर-चिरमिरी रेल लाइन: नागपुर हॉल्ट से चिरमिरी तक 17 किमी नई रेलवे लाइन निर्माण प्रक्रिया पूरी, राज्य सरकार अपने हिस्से की 50 फीसदी राशि नहीं कर रही जारी

[illegible] 25/10/21

- 241 करोड़ की रेल परियोजना को रेलवे बोर्ड ने 3 [illegible] 2018 को दी थी मंजूरी, लेकिन अब तक कार्य अधूरा

[illegible] रेल खंड में नागपुर हाल्ट से चिरमिरी तक 17 किमी नई रेलवे लाइन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने अब तक अपने हिस्से की 50 फीसदी राशि की मंजूरी नहीं दी है. जबकि इसी मांग को लेकर बीते एक साल से सरकार को जगाने और क्षेत्र की जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए [illegible] प्रकाश पटेल [illegible] कर रहे हैं।

इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को 50-50 फीसदी राशि जारी करना है. इसमें से केंद्र ने अपने हिस्से की राशि जारी की है. लेकिन राज्य सरकार ने अब तक अपने हिस्से की 120.50 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी नहीं दी है। इसके चलते प्रोजेक्ट का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

Chhattisgarh lags in implementing devpt projects despite central loan: Nirmala Sitharaman

TNN / UPDATED: OCT 6, 2021, 09:46 IST

We gave Rs 286 crore, interest-free to Chhattisgarh, for 50 years (but) schemes for the poor are not being worked upon, said Sitharaman at a press conference.

RAIPUR: Union finance minister Nirmala Sitharaman on Tuesday denied that the Centre was discriminating against Chhattisgarh in funds allocation, saying that the state is lagging in implementing centrally sponsored schemes as it is unable to raise matching grants.

अभिव्यक्ति का गला घोंटने वाली कांग्रेस

भूपेश राज में अभिव्यक्ति की आजादी बदहाल
छत्तीसगढ़ में लगा है अघोषित आपातकाल

कांग्रेस हमेशा से ही अभिव्यक्ति का गला घोंटती रही है। छत्तीसगढ़ में भी सत्ता में आते ही असहमति के आवाजों का दमन, बाकायदा कांग्रेस के नेताओं द्वारा पत्रकारों की बर्बर पिटाई, बिजली कटौती तक के बारे में सोशल मीडिया पर लिखने के कारण देशद्रोह का मुकदमा कर उत्पीड़न, शासकीय शक्ति का दुरूपयोग कर राष्ट्रीय पत्रकारों पर एक साथ सैकड़ों मुकदमें लाद देने जैसे कुकृत्य और लगातार ऐसे मामलों में कोर्ट से फटकार लगाए जाने के बावजूद भी कांग्रेस के काले कारनामे जारी हैं। अजीब-अजीब तरह के क़ानून छत्तीसगढ़ पर लादते हुए कांग्रेस फिर से लोकतंत्र की हत्या करने पर आमदा है। विशेष सुरक्षा कानून बनाकर डॉक्टर, वकील, पत्रकारों को संरक्षण देने का पाखंड करने वाली कांग्रेस ने प्रताड़नाओं का इतिहास रचा है।

भास्कर Research • भास्कर ने चाकूबाजी की 130 एफआईआर का अध्ययन किया, इसके नतीजे

छोटी बातों पर उग्र होकर चाकू मारने वाले 90% लड़के कम उम्र के, 60 फीसदी वारदातें नशे में

फैक्ट फाइल

823

313

38%

FIR पढ़ने से नए ट्रेंड का खुलासा

पुलिस के दावे

एक्सपर्ट व्यू

युवाओं में बर्दाश्त खत्म

केस 1

अब सिर्फ तस्वीरें, यादें और ज़ख्म रह गए

अब राखी किसे बांधूंगी

आखिर कुसूर क्या

सालभर में पुलिस के पास जमा करवाए 700 से ज्यादा चाकू

राजधानी में तेजी से बढ़ी चाकूबाजी की घटनाएं बनीं पुलिस के लिए चुनौती

चाकू मारकर बदमाशों ने कर दी ड्राइवर की हत्या, वजह साफ नहीं

9 दिन में रायपुर में चौथी हत्या

माल उतारकर घर जा रहा था

रक्षाबंधन के दिन घर पर पसरा मातम

नक्सल हमले के बहाने टारगेट किलिंग

नक्सलियों को मिला कांग्रेस का साथ
टारगेट किलिंग के लिए मिला चुके हाथ

प्रदेश शासन में बैठे लोगों के नक्सलियों से संबंध की बातें तो जगजाहिर होती रही है। कांग्रेस शासनकाल में नक्सलवाद फिर पनपने लगा है जिसमे 1,302 हमले हुए हैं और 139 जवान शहीद हुए हैं। कांग्रेस नक्सलवाद के नाम पर भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग को भी प्रश्रय-प्रोत्साहन दे रही है, इसके भी अनेक साक्ष्य सामने आये हैं। अभी तक भाजपा के विधायक शहीद श्री भीमा मांडवी समेत कई कार्यकर्ता टारगेट करके मार दिए गए हैं। लगातार कार्यकर्ताओं को मार देने, काट देने की धमकियां मिल रही हैं। कांग्रेस विधायकों के सामने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी दी जा रही है। भूपेश बघेल वैसे तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए पुरे देश में घूम-घूम कर मुआवज़ा देते है पर नक्सल और पुलिस की लड़ाई में मर रहे लोगों की सुध लेने की उन्हें कोई फुर्सत नहीं, उनके लिए कांग्रेस सरकार के पास न सहानुभूति है, न ही कोई योजना। खुद भूपेश बघेल झीरम मामले में साक्ष्य अपनी जेब में ही रखे रहने के कारण संदिग्ध हैं। कांग्रेस के मुखिया रहे राहुल गांधी द्वारा झीरम मामले में नक्सलियों को क्लीन चिट देना भी यह संदेह पैदा करता है कि हर नक्सल मामलों में कांग्रेस संलिप्त है।

नक्सलियों ने मार्ग अवरुद्ध कर फेंके पर्चे, यू-ट्यूबर की हत्या स्वीकारी

डीएवी के हालात को देखते हुए अभिभावक भर्ती करवाने से पीछे हट रहे
नक्सल पीड़ित परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित

नक्सलियों ने लगाया बदले की कार्यवाही का आरोप
झारखंड में पुलिस ने स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार की गिरफ्तारी की
नक्सलवाद

मुंह में राम बगल में छुरी

छत्तीसगढ़ियों के साथ खेल रहा खेल
इस बार जाएगा भूपेश बघेल

कांग्रेस वास्तव में प्रादेशिक अस्मिता की भी हत्यारी है। वह बात भले प्रदेश के हित की करे, इस विषय पर तनाव भी पैदा कराये समाज में, लेकिन जब भी राज्यसभा में सदस्य बनाना हो, तो वह पता नहीं किस कारण किसी भी छत्तीसगढ़िया को मौक़ा नहीं देना चाहती है। जिन्होंने कभी देखा भी नहीं छत्तीसगढ़ को, उन्हें यहां से राज्यसभा में भेजना, छत्तीसगढ़ के कोटा से राज्यसभा पहुंचे सांसद का प्रमाण पत्र लेने भी छत्तीसगढ़ नहीं आना, कैबिनेट मंत्री द्वारा उनका प्रमाण पत्र दिल्ली जा कर पहुंचाना आदि छत्तीसगढ़ को शर्मसार करता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ी में मातृभाषा में शिक्षा देने वाली 'नयी शिक्षा नीति' का विरोध कर भी छत्तीसगढ़ी को नुकसान पहुंचाया है।

कांग्रेस ने राज्यसभा सीटों को लेकर चल रही चर्चा पर विराम लगाया, 2 बाहरी लोगों के नाम बताए

टीएनएन/ 30 मई, 2022, 03:18 IST

रायपुर: कांग्रेस ने रविवार रा
राजीव शुक्ला और रंजीत
के लिए अपने उम्मीदवार
दिया। हैरानी की बात यह
हैं।

"Outsiders": BJP On Rajya Sabha Nominations By Chhattisgarh Congress

Congress has nominated its senior leader and journalist-turned-politician Rajiv Shukla and former Bihar MP Ranjeet Ranjan as its candidates from Chhattisgarh.

फेक मुलाकात – ढोंगी कांग्रेस

मुख्यमंत्री की बात पर नहीं प्रशासन को विश्वास
बस हारने का विकल्प बचा है कांग्रेस के पास

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भेंट-मुलाकात के नाम पर घोषणाओं की झड़ी लगा दी, जिसे पूरा करने के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। ज़ाहिर है ऐसी एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। इतने झूठे तरीके से मुख्यमंत्री लबारी मार रहे हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय तक को, न तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं की जानकारी है और न ही घोषणाओं पर कार्यवाही हुई है। भरोसे के हत्यारे साबित हुए हैं सीएम।

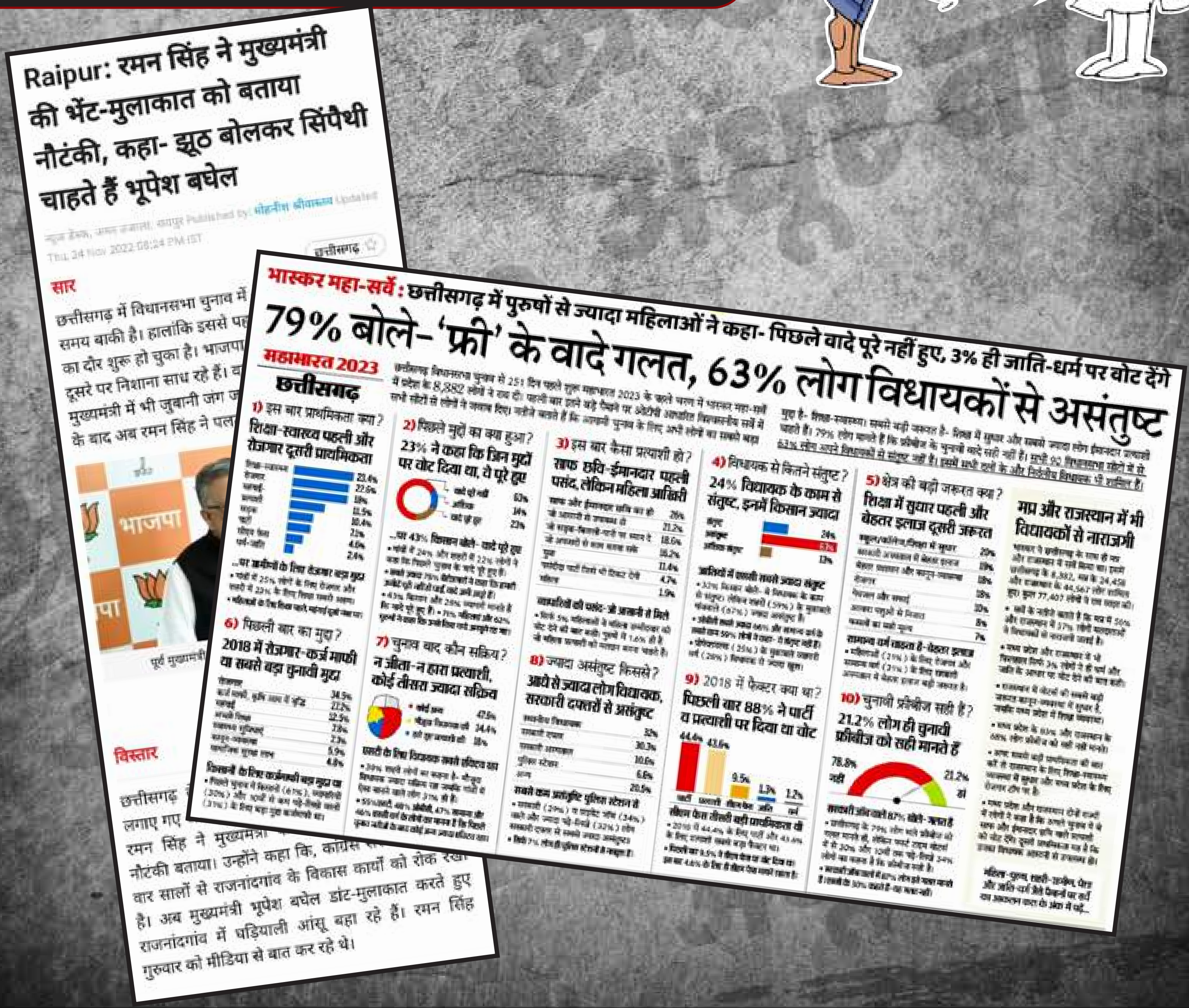

Raipur: रमन सिंह ने मुख्यमंत्री की भेंट-मुलाकात को बताया नौटंकी, कहा- झूठ बोलकर सिंपैथी चाहते हैं भूपेश बघेल

Thu, 24 Nov 2022 08:24 PM IST

छत्तीसगढ़

सार

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में ... समय बाकी है। हालांकि इससे प... का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा... दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ... मुख्यमंत्री में भी जुबानी जंग ... के बाद अब रमन सिंह ने पल...

भाजपा

पूर्व मुख्यमंत्री ...

विस्तार

छत्तीसगढ़ ... लगाए गए ... रमन सिंह ने मुख्यमंत्री ... नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस ... विकास कार्यों को रोक रखा ... वार सालों से राजनांदगांव के विकास कार्यों को रोक रखा ... है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डांट-मुलाकात करते हुए राजनांदगांव में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। रमन सिंह गुरुवार को मीडिया से बात कर रहे थे।

भास्कर महा-सर्वे : छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने कहा- पिछले वादे पूरे नहीं हुए, 3% ही जाति-धर्म पर वोट देंगे

79% बोले- 'फ्री' के वादे गलत, 63% लोग विधायकों से असंतुष्ट

महाभारत 2023

छत्तीसगढ़

1) इस बार प्राथमिकता क्या?
शिक्षा-स्वास्थ्य पहली और रोजगार दूसरी प्राथमिकता

2) पिछले मुद्दों का क्या हुआ?
23% ने कहा कि जिन मुद्दों पर वोट दिया था, वे पूरे हुए

3) इस बार कैसा प्रत्याशी हो?
साफ छवि-ईमानदार पहली पसंद, लेकिन महिला आखिरी

4) विधायक से कितने संतुष्ट?
24% विधायक के काम से संतुष्ट, इनमें किसान ज्यादा

5) क्षेत्र की बड़ी जरूरत क्या?
शिक्षा में सुधार पहली और बेहतर इलाज दूसरी जरूरत

मप्र और राजस्थान में भी विधायकों से नाराजगी

6) पिछली बार का मुद्दा?
2018 में रोजगार-कर्ज माफी था सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

7) चुनाव बाद कौन सक्रिय?
न जीता-न हारा प्रत्याशी, कोई तीसरा ज्यादा सक्रिय

8) ज्यादा असंतुष्ट किससे?
आधे से ज्यादा लोग विधायक, सरकारी दफ्तरों से असंतुष्ट

9) 2018 में फैक्टर क्या था?
पिछली बार 88% ने पार्टी व प्रत्याशी पर दिया था वोट

10) चुनावी फ्रीबीज सही हैं?
21.2% लोग ही चुनावी फ्रीबीज को सही मानते हैं

बिजली हाफ–बिल दुगना

बिजली की जगह मिला अंधकार, भ्रष्टाचार में डूबी भूपेश सरकार

- प्रदेश में गांव से लेकर शहर तक जनता बिजली कटौती से त्रस्त है। बिजली कंपनियों के कुप्रशासन के कारण सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ बिजली की कमी से जूझ रहा है। बिजली का उत्पादन भी 440 मेगावाट घट चूका है, जो निरंतर घट ही रहा है। किसान आज बिजली कटौती और बढ़े बिजली बिल से परेशान है। कांग्रेस सरकार ने औद्योगिक नीति में संशोधन कर बालको स्टील प्लांट, कोरबा और जिंदल पावर प्लांट के ₹ 10,000 करोड़ का बिजली शुल्क माफ कर दिया। किसानों को सरकार से एक ही पंप पर छूट मिल रहा है बाकि पम्पों का बिजली बिल तो किसान खुद भर रहा है। अब किसान तो किसी भी प्रकार से स्टील प्लांट के मालिकों से ज्यादा समृद्ध नहीं है तो फिर किसान के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों?
- भाजपा सरकार में सरप्लस बिजली वाले अपने प्रदेश में भूपेश सरकार ने अंधेरों का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। ऐसा लगता है मानो स्वार्थवश यह सरकार इनवर्टर आदि बनाने वाली कंपनियों के हाथ खेल रही है। बिजली बिल हाफ करने का वादा करने वाली कांग्रेस ने बिजली ही हाफ कर दी। हाल में आत्महत्या करने वाले किसान कन्हैयालाल पर कर्ज लगातार बढ़ता गया था, क्योंकि बिजली नहीं रहने के कारण इनकी खेती नहीं हो पा रही थी।

नहीं मिली संपत्ति कर में राहत

संपत्ति कर में नहीं मिली कोई राहत
भूपेश राज में जनता हो रही आहत

संपत्ति कर को आधा करने के नाम पर कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को केवल झूठे सपने दिखाए थे। कर कम करने के इन ढकोसले के बीच भूपेश सरकार के कुशासन मे हालात ये है कि पहली बार कच्चे मकानों से भी सम्पत्ति कर की उगाही की गई है। परिणाम ये है कि इस कदम से गरीबों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया गया है।

छग सरकार के ढाई साल, BJP के 16 सवाल: भाजपा ने मांगा हिसाब; शराबबंदी, संपत्तिकर आधा करने, बेरोजगारी भत्ता देने के अधूरे वादे CM बघेल को याद दिलाए

रायपुर 14/06/21

इस तरह के पोस्टर अब कांग्रेस के लिए जारी कर रही है भाजपा।

छत्तीसगढ़ भाजपा ने कांग्रेस सरकार से अब हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। दरअसल, 17 जून को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे हो जाएंगे। इन ढाई सालों के हिसाब-किताब के साथ सियासी मैदान में भाजपा सवालों की झड़ी लेकर आई है। सोमवार को भाजपा ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों से जुड़े सवालों के साथ अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा ने एक ब्रोशर जारी किया है। इस पर लिखा है- क्या हुआ तेरा वादा, ढाई साल का हिसाब दो, सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब तो देना होगा भूपेश सरकार।

कांग्रेस भवन के मुख्य गेट पर चस्पाया रिकवरी नोटिस, 13 लाख से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया

निगम अधिकारियों की मानें तो पहले भी निगम की ओर से कई बार कांग्रेस भवन के मुख्य गेट पर ऐसे नोटिस चस्पाए गए हैं। अब यह आखिरी मौका है। अगर टैक्स का भुगतान न हुआ तो इस भवन को स्थायी तौर पर सील कर दिया जाएगा। रिकवरी के बाद ही सील हटेगी।

कांग्रेस भवन के मुख्य गेट पर रिकवरी नोटिस चस्पा

फूड पार्क का झूठ, राहुल गांधी की लूट

फूड पार्क का वादा बना झूठ का आधार
भ्रष्ट कांग्रेस लूट ले गई युवाओं का रोजगार

200 फूड पार्क बनाने एवं उसमे छत्तीसगढ़ के लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने का झूठा वादा छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने किया था। फूड पार्क तो बने नहीं और प्रदेश का युवा आज भी रोज़गार की तलाश में भटक रहा है, लेकिन राहुल गांधी ये झूठा दावा कर रहें है की हर जिले में फूड पार्क बन गया है। किसान टमाटर समेत अपनी अन्य फसलों को सड़क पर फेंकने मजबूर हो रहे, जबकि राहुल गांधी देश भर में घूम-घूम कर 'टमाटर डालो पैसे निकालो योजना' की डींगें हांक रहे। एक तरफ किसानों को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिलता, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ियों को डेढ़ सौ रुपये किलो टमाटर खरीदना पड़ रहा है। बिचौलियों के हाथों खेलती हुई कांग्रेस ने अपनी सरकार को दलाल फ्रेंडली बना लिया है।

लघु उद्योग दिवस आज: फूड पार्क में 1 फैक्ट्री ही लगी, 85 प्लॉट खाली पड़े

धमतरी 30/08/20

- रोजगार देने के दावे पूरे नहीं, बगौद में 2018 में हुआ था फूड पार्क का लोकार्पण

जिले के कुरूद ब्लॉक के बगौद-बंजारी में मेगा फूड पार्क बनकर तैयार हो गया है। यह प्रदेश का पहला फूड पार्क है। इसका शिलान्यास 2018 में तत्कालीन सीएम रमन सिंह द्वारा किया गया था। इन दो सालों में यहां केवल एक ही फैक्ट्री लग पाई है। इसी के बगल में एक प्लाट पर भवन बनाने का काम चल रहा है। बाकी प्लाटों पर जानवर चर रहे हैं।

ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐसा हाल: 4 ब्लॉक में बनना है फूड पार्क, 2 साल में सिर्फ दो के लिए जगह ढूंढ पाए, उसमें भी निर्माण शुरू नहीं

कवर्धा 17/12/20

- जिले के किसानों को नहीं मिल रहा बाजार, फसलों को दूसरे राज्यों में बेचना मजबूरी

कबीरधाम जिले के कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर लोहारा और पंडरिया ब्लॉक में 1-1 फूड पार्क बनाया जाना है। छग सरकार ने दो साल पहले इसकी घोषणा की थी। फूड पार्क स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन दो साल में सिर्फ दो के लिए जगह ढूंढ पाए हैं। उसमें भी अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

बेघर, भूखा और प्यासा भी रखा प्रदेश को

पीने के पानी को तरस रहा है प्रदेश
नल-जल योजना के पैसों का क्या किए भूपेश ?

कांग्रेस सरकार ने न केवल छत्तीसगढ़ियों को बेघर किया, बल्कि उनके मुंह से निवाला भी छीना और उन्हें प्यासा भी रखा है। साफ पानी को तरस रहा है प्रदेश - जल जीवन का पैसा गटक गये भूपेश। घरों में पानी की आपूर्ति में छत्तीसगढ़ देश में सबसे पीछे है और जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में 26वें स्थान पर। चुनाव से पहले घोषणापत्र में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हर घर शुद्ध जल देने का वादा किया था। पर न सिर्फ इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चलाये जा रहे 'हर घर नल योजना' को भी ठीक से क्रियान्वित नहीं होने दिया। केंद्र सरकार की ₹ 3,300 करोड़ से अधिक के नल-जल योजना को लागू करने में फिसड्डी साबित हुई भूपेश सरकार। जिस भी योजना में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती, उसे ये भूपेश सरकार चलने ही नहीं देती है। प्रदेश की भोली-भाली जनता भूपेश बघेल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी हुई है। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि जल जीवन मिशन में जिन कंपनियों को कार्य दिया गया था वह कंपनिया समय पर कार्य नहीं कर रही हैं और उनके खिलाफ गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें हो रही है लेकिन उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

उद्योगों के साथ सिर्फ कागजों पर हो रहे एमओयू

रोजगार के नाम पर मिली भीख
छत्तीसगढ़ का भविष्य सड़कों पर रहा चीख

सरकार ने पिछले 3 वर्षों में उद्योगों के साथ 185 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ₹ 94,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का वादा किया गया है। जबकि राज्य में उतना निवेश भी नहीं आ पाया, जितने पैसे का इस निकम्मी सरकार ने विज्ञापन कर दिया है। वास्तविक निवेश राशि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए राशि के 1% से भी कम है। अधिकांश एमओयू में 2 साल की क्रियान्वयन अवधि थी, जो पहले ही बीत चुकी है। इन एमओयू को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी धरातल पर कोई कार्य होता नहीं दिखा है। सभी एमओयू केवल कागजों पर ही कायम है।

छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ का डामर घोटाला: शासन ने जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की बात कही; हाईकोर्ट ने कहा-लिखित दस्तावेज पेश करें

बिलासपुर 26/07/22

डामर घोटाले में अब दोषियों पर हो सकती है कार्रवाई।

छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपए के डामर घोटाले को लेकर [illegible] याचिका पर राज्य शासन ने एक बार फिर कहा कि जिम्[illegible] और दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। इस प[illegible] ने राज्य शासन को लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हु[illegible] प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराने कहा है। [illegible] सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी।

Investgarh Chhattisgarh investor Summit 2022: 132 MOU के जरिए 58,950 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्ताव, 1564 नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित, अभी अपार संभावनाएं

Hs91313 September 2, 2021

नवा रायपुर। Investgarh Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए नवा रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़' का आयोजन 27 जनवरी 2022 से 01 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ परियोजना' के उद्घाटन समारो[illegible] में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर इन्वेस्टगढ़-छत्तीसगढ़ का लोगो (प्रतीक चिन्ह) और वेबसाइट लांच की।

धोखेबाज सरकार

वादा किए बड़े-बड़े, धोखे से लिया वोट
कर्मचारी आज सड़क पर, कल करेंगे चोट

कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी को लेकर प्रदेश के 145 से अधिक कर्मचारी संगठन हड़ताल पर चले गए। कांग्रेस ने वादा किया था कि संविदा, दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, लेकिन इस समिति ने एक भी बैठक नहीं की। इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। रसोइया, संविदा कर्मी और सचिवों जैसे सभी समूहों ने अलग-अलग समय पर लम्बे समय से अपनी मांग सरकार के सामने रखी है और कांग्रेस नेताओं को उनका वादा याद दिलाया है। सचिव संघ को तो, 61 कांग्रेस विधायकों ने लिखित समर्थन दिया था और स्वयं मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था। पर कांग्रेस की इस सरकार में सब दिखावा है, किसी भी नेता, मंत्री या अधिकारी के शब्दों का कोई मोल नहीं बचा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में अघोषित कटौती की-फेडरेशन

साजा. छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं जिला अध्यक्ष बलदाऊसिंह पटेल, महामंत्री रामकुमार डडसेना, बेमेतरा ब्लाक अध्यक्ष प्यारेलाल कश्यप, बेरला ब्लाक अध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा, साजा ब्लाक अध्यक्ष पद मनसिंग इंदौरिया, नवागढ़ ब्लाक अध्यक्ष नरसिंह जायसवाल ने संयुक्त रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के 407862 कर्मचारी-अधिकारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महँगाई भत्ता डीए का क़िस्त स्वीकृत नहीं करने के कारण अघोषित रूप से प्रतिमाह वेतन में सिलसिलेवार कटौती हुई है. उन्होंने बताया कि केंद्र शासन ने 1 जनवरी 2019 के 12 प्रतिशत महँगाई भत्ता में 5प्रतिशत वृध्दि कर 1 जुलाई 2019 से 17प्रतिशत घोषित किया था, लेकिन राज्य शासन ने 1 जुलाई 2021 से महँगाई भत्ता में 5 प्रतिशत वृध्दि किया था, जिसके कारण 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक अर्थात 2 वर्ष प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के मासिक वेतन में 5 प्रतिशत का अघोषित कटौती हुआ था.

उन्होंने आगे बताया कि केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 20 का 4 प्रतिशत, 1 जुलाई 20 का 3 प्रतिशत तथा 1 जनवरी 21 का 3 प्रतिशत कुल 11 प्रतिशत डीए में वृद्धि अर्थात 17प्रतिशत से 28 प्रतिशत को 1 जुलाई 21 से प्रभावशील किया था, लेकिन राज्य सरकार ने 1 जुलाई 21 से 30 ...

अविवादित फौती नामांतरण सहित राजस्व संबंधी कार्यों के लिए भटक रहे लोग

पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 20 दिनों से कामकाज ठप

संविदा कर्मचारियों ने घुटनों के बल चलकर निकाली रैली

वादा कर्ज़माफी का था बना दिया पीढ़ियों तक को कर्ज़दार

भारी कर्ज़ ने प्रदेश को किया बदहाल
भ्रष्ट भूपेश बजा रहा अपनी गाल

घोषणा पत्र में कर्ज़माफी जैसे वादे करने वाली कांग्रेस ने वास्तव में छत्तीसगढ़ की पीढ़ियों तक को कर्ज़दार बना दिया है। यहां के किसान-श्रमिक के बच्चे शायद दशकों तक कर्ज़दार बने रहें, ऐसी लूट कांग्रेस ने मचायी है। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति कर्ज़ ₹ 12,551 था, जो अब दोगुने से भी अधिक बढ़ कर ₹ 27,284 हो गया है। ऐसा तब है जबकि कांग्रेस ने बुनियादी ढांचों के विकास या निर्माण आदि पर एक ढेला तक खर्च नहीं किया है। पूछने पर, कांग्रेस सरकार बार-बार कहती है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में अभी हमारा कर्ज़ कम है। सरकार यह भूल जाती है कि अन्य प्रदेश वर्ष 1956 में बने थे। उनकी आयु आज 67 वर्ष हो गयी और छत्तीसगढ़ आज 23 साल का है। अगर इसी अनुपात से कर्ज़ लेते रहे तो छत्तीसगढ़ राज्य ही दिवालिया नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले बच्चों पर लाखों रुपये का कर्ज़ हो जायेगा। एक हाथ से देकर दस हाथ से लूटने वाली साबित होती रही है कांग्रेस।

कर्ज लेने वाले किसान नहीं बेच रहे समिति में धान, रखे जाएंगे कालातीत सूची में

समिति की वार्षिक सभा

राज्य सरकार के संरक्षण मे लगातार बढ़ रहे हैं अपराध, विधायक अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार को लिया आडे हाथ

भूपेश सरकार जनता को कर्ज में डाल रही-अजय

हर घर तिरंगा अभियान का पूर्व मंत्री ने किया आगाज

बिगड़ती आर्थिक स्थिति

मुफ्त म पाइस, ता मरत ले खाइस

- वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। वर्ष 2018 तक विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के निर्माण, सडक पुल-पुलिया आदि का विकास करते हुए, आम लोगों की जरूरतों की पूर्ति हेतु सुंदर आर्थिक नियोजन करते हुए छत्तीसगढ़ ने 18 साल में मात्र 41 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया। 18 साल से 23 साल के छत्तीसगढ़ के ऊपर लगभग 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो गया, जिसमें कोई भी ऐसा नया काम नहीं हुआ, जिसे गिनाया और दिखाया जा सके। कोई नया संस्थान नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, फिर भी यह कर्ज़ नौजवान छत्तीसगढ़ के ऊपर डाला गया। छत्तीसगढ़ को कहां ले गये?
- जहां यहां के नौजवान को अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, आई. आई. टीयन बनना था, उसकी जगह आप उन्हे गोबर बेचने, महादेव सट्टा में खेलने, चरस बेचने, गांजा बेचने की दिशा में ले गए।
- मतलब 15 साल में जब हमने छत्तीसगढ़ को छोड़ा था तो नौजवान खाता-पीता हृष्ट-पुष्ट सब था उसे हमने सारी सुख-सुविधाएं दे दीं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, रोड दे दि, स्कूल दे दिया, कॉलेज में एडमिशन करा दिया, पढ़-लिखकर वह आगे बढ़ रहा था, आपने उसे पीछे खीचने का अपराध किया है।
- सकल घरेलू उत्पाद, जिसमें भाजपा सरकार मे 2011-12 से 2018-19 के दौरान 50.36% की वृद्धि देखी गई, 2018 के बाद धीरे-धीरे कम हो गई। अफसोस की बात है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद में 1.77% की दर से उल्लेखनीय गिरावट हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिकूल गिरावट का संकेत देती है। इतना हि नहीं, अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की जीडीपी संख्या स्पष्ट रूप से बहुत कम है।
- छत्तीसगढ़ की चिंताजनक वार्षिक वृद्धि दर पैटर्न में 2016-17 में एक उल्लेखनीय पुनरुत्थान दिखाई देता है, जब विकास दर प्रभावशाली 12% से अधिक हो गई। हालांकि, 2018 के बाद के वर्षों में विकास दर में काफी गिरावट देखी गई और 2020-21 में तो यह घाट कर -1.77% पर चली गई।
- छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 2018 तक लगातार वृद्धि हुई, जिसके बाद विकास में गिरावट आई और वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 4% की दर से गिरावट हुई, जिसे अर्थव्यवस्था की अपने उत्पादन या सकल घरेलू उत्पाद का विस्तार करने में असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह छत्तीसगढ़ मे जीवन स्तर को बढ़ाने और अपने निवासियों के लिए पर्याप्त आर्थिक अवसर पैदा करने की राज्य की क्षमता के बारे में भी चिंता पैदा करता है।

बिगड़ती आर्थिक स्थिति

मुफ्त म पाइस, ता मरत ले खाइस

- छत्तीसगढ़ के मामले में, बकाया देनदारियों में 82% की वृद्धि, 2018 के बाद से कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान सरकारी बोझ बढ़ने का संकेत देती है और यह राजकोषीय संतुलन के लिए हानिकारक साबित हुआ है।
- जनवरी 2019 से जनवरी 2023 के बीच कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल ₹54,491.68 करोड़ का कर्ज लिया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जनवरी 2023 तक राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का 66.35% है। गत चार वर्षों में ही, कुल राजकीय कर्ज का दो-तिहाई हिस्सा लिया जाना वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है।
- निवर्तमान कांग्रेस सरकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति व्यक्ति कर्ज में ₹14,733 की बढ़ोतरी हुई है। दिसम्बर 2018 में राज्य का प्रति व्यक्ति कर्ज ₹12,551 था। जोकि, मार्च 2023 में बढ़ कर ₹27,284 हो चूका था।
- काँग्रेस के सत्ता मे आने के एक साल के अंदर वर्ष 2020-21 छत्तीसगढ़ के राजकोषीय घाटे के लिए एक संकटपूर्ण मोड़ ले आया, जब छत्तीसगढ़ का सकल राजकोषीय घाटा भी 2018-19 से 2019-20 के बीच 116.6% बढ़ गया, जो वित्तीय कुप्रबंधन के अस्थिर पैटर्न को दर्शाता है।
- शर्म की बात है की वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य के बजट में ग्रामीण विकास पर व्यय का हिस्सा केवल 7.6% था जो अपने पड़ोसी राज्यों जैसे कि तेलंगाना (11.06%), झारखंड (9.74%), ओडिशा (9.32%) और मध्य प्रदेश (8.87%) की तुलना में बहुत कम है, जबकि राज्य की लगभग 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच भाजपा सरकार के अंतर्गत सडकों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अनुमान में 54.93% की वृद्धि हुई थी। जोकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच कांग्रेस सरकार में मात्र 6.76% रही है। सडकों और पुलों के निर्माण में की गई वित्तीय कटौती और कुप्रबंधन का ही परिणाम है कि, हालही में साझा की गई सीएजी (कैग) की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बनी 93% सड़के अमानक पाई गई, वो तय मापदंड को प्राप्त करने में असफल रही है।
- महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छत्तीसगढ़ की तुलना में शिक्षा पर खर्च का स्तर बहुत अधिक है। जहां 2017-18 से, भाजपा सरकार के तहत शिक्षा पर खर्च 42% बढ़ गया, वहीं कांग्रेस के सत्ता में आने के तुरंत बाद के वर्ष में इसमें केवल 4% की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण का 81% 2026-27 तक चुकाना होगा।

झूठे विज्ञापनों वाली सरकार

भूपेश ने काम नहीं बस चेहरा चमकाया है
विकास के नाम पर बस विज्ञापन छपवाया है

मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा चमकाने के लिए इन साढ़े चार सालों में लगभग ₹ 600.38 करोड़ विज्ञापन पर खर्च किए हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि सरकार की ओर से कोई काम नहीं किया गया, बल्कि अखबार, होर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में सब अच्छा चल रहा है। जबकि हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ता जा रहा है और जन-सुविधाएं बद से बदतर होती जा रही हैं। अगर सरकार चाहती तो इन ₹ 600 करोड़ से प्रदेश के 2 लाख से अधिक युवाओं को उनका बेरोजगारी भत्ता दे सकती थी।

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हर दिन विज्ञापन पर खर्च किए लगभग 30 लाख रुपए

सरकार ने दिसंबर 2018 से नवंबर 2021 तक सभी माध्यमों के जरिए विज्ञापन पर 300 करोड़ से ज्यादा

...-प्रसार पर

...018 से ...

बदरंग राजधानी • सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति नहीं लगाए जा सकते बैनर-पोस्टर

पहले करोड़ों खर्च कर राजधानी को सुंदर बनाया, अब उसी सुंदरता को पाट दिया अवैध पोस्टरों और बैनरों से

ग्लोबल चौक, जिसे ढाई करोड़ खर्च कर सुंदर बनाया

क्या है नियम

नेताओं को छूट, निजी संस्थानों पर कार्रवाई

पूरे शहर को इसी तरह पोस्टरों से पाट रखा है

छत्तीसगढ़ सरकार ने दो साल में विज्ञापनों पर खर्च किए 2 अरब 8 करोड़ से ज्यादा रुपये और कर्ज लिया 4 हजार 676 करोड़ रुपये

Chhattisgarh Govt: एक राज्य सरकार अपनी ब्रांडिंग और योजनाओं के विज्ञापनों पर किस हद तक खर्च कर सकती है इसकी बानगी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार बताती है. यहां विज्ञापन के नाम पर कांग्रेस की भूपेश सरकार ने दो अरब रुपये से भी ज्यादा खर्च कर दिए. वो भी महज दो सालों में.

भूपेश सरकार में पहली बार

- दो दो विधायकों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ने न्यायालय में दाखिल किया आरोप पत्र।
- दो आईएएस अधिकारी सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभावशाली अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं।
- मुख्यमंत्री के सलाहकार और मुख्यमंत्री कार्यालय के दो ओएसडी घर पर केंद्रीय एजेंसी ने छापा मारा।
- आईएएस और राज्य सेवा के अधिकारियों के घरों में आयकर का छापा पड़ा।
- कोयला के परिवहन में 25 रुपया प्रति टन की दर से दलाली खाने का आरोप लगा।
- शराब के कारोबार में सरकारी खजाने को मिलने वाले आबकारी शुल्क की राजनीतिक बंदरबांट हुई।
- गरीबों को मिलने वाले राशन को भी सरकारी अमले की मिलीभगत से डकार गए, केंद्रीय मंत्रालय ने जांच कर घोटाले की पुष्टि की।
- लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूची में कांग्रेस नेताओं, मंत्री, अधिकारियों के बच्चे टॉप पर रहे।
- करोड़ों की लागत से बने सर्वसुविधायुक्त मंत्रालय की उपेक्षा कर मुख्यमंत्री और मंत्री अपने बंगले से काम करते रहे, इससे प्रशासनिक कार्य चौपट होता गया।
- शांति के टापू छत्तीसगढ़ राज्य में सांप्रदायिक दंगा हुआ, हिंदू युवक की मॉब लींचिंग में मौत हुई, सामाजिक सौहार्द्र शहरों और गांवों में बिगड़ा।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासन के कुछ रोचक तथ्य

- देश की पहली ऐसी सरकार जहां शासन मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव या पुलिस महानिदेशक नहीं बल्कि एस डी एम स्तर के अफसर सरकार चलाते हैं।
- एकमात्र प्रदेश जहां कई आईएएस जेल में हैं।
- देश का पहला ऐसा राज्य जहां बिना राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिए, पिछले दरवाजे से कांग्रेस के पदाधिकारियों / अधिकारियों के करीबी शासकीय पदों पर नियुक्त हुए।
- जहां पांच साल में एक भी नया प्राइमरी स्कूल नहीं खुला।
- छत्तीसगढ़ियावाद का दिखावा करने वाली सरकार राज्यसभा में सभी बाहरी नेताओं को चुनकर भेजती है और निगम मंडलों में बाहरी लोगों की नियुक्ति की जा रही है।
- जहां धार्मिक आस्था के प्रतीकों के निर्माण में भी घोटाला होता है।
- जहां वन रक्षक परीक्षा में विश्व विजेता धावक उसेन बोल्ट के दौड़ने का रिकॉर्ड टूट जाता है।
- भेंट मुलाकात में प्रश्न और प्रश्नकर्ता को पहले से सेट किया जाता है। बाकायदा प्रशिक्षण के बाद ही मुख्यमंत्री से "सेट मुलाकात" हो पाती है।
- जहां मुख्यमंत्री "भेंट मुलाकात" कार्यक्रम करके जनता से सरेआम गाली-गलौज करते हैं।
- देश का पहला राज्य जहां परीक्षा व्यापम लेती है, परिणाम PHQ जारी करता है। व्यापम के शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिना परीक्षा दिए 99 अभ्यर्थियों का चयन होता है।
- मंत्रिमंडल में नक्सलियों के प्रतिनिधि और सलाहकार मंडल में अर्बन नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले शामिल है।
- संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री न्यायपालिका के निर्णय के खिलाफ काला कपड़ा पहनकर धरने पर बैठते हैं।
- विधायक थप्पड़ मारते हैं और गाली देते हैं तो कर्मचारी और पुलिस वाले माफी मांगते हैं।
- छत्तीसगढ़ में डॉडरा गांव (सुकमा जिला) में अंतरराज्यीय जुआ स्थल है।
- सर्वाधिक दुर्घटना वाले राज्य छत्तीसगढ़ में 40 हजार सड़क दुर्घटना में 21 हजार लोग मरे व अपंग की गिनती नहीं।

निवेदन

लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हर मामले में इस लाज को पूरी तरह तिलांजलि दे दी है। भूपेश बघेल की सरकार जितनी बेशर्मी के साथ घोटाले करती है, उतनी ही बेशर्मी के साथ अपने घोटालेबाजों को बचाने पूरी ताकत भी लगा देते हैं। जितनी बेशर्मी से अभिव्यक्ति की हत्या करती है उतनी ही बेशर्मी के साथ स्वयं अभिव्यक्ति की हर मर्यादा का उल्लंघन करते हुए राजनीति को अपशब्दों का शब्दकोश भी बना देती है। जिस बेशर्मी के साथ अपने सहयोगी मंत्री को दिखा देते हैं, उतनी ही ताकत से प्रदेश की जनता को भी अपमानित करते हैं। जिस तरह बिना किसी लोकलाज की परवाह किये अपने लगभग तमाम वादों से मुकर जाते हैं, उसी तरह लगातार झूठ पर झूठ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी दुष्प्रचार करने से बाज नहीं आते।

प्रदेश की ऐसी बेशर्म, बर्बर, बदजुबान, बेईमान, बंटाधार करने वाली कांग्रेस सरकार के कलुष कारनामों की काली करतूतों का यह संक्षिप्त आरोप पत्र प्रदेश की जनता की अदालत में इस आशा के साथ प्रस्तुत है कि जनता जनार्दन इस पर विचार करते हुए भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ निर्णय सुनाये। इस सरकार को उखाड़ फेक कर ही हम प्रदेश में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्बहाली का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जोहार।

जय छत्तीसगढ़ महतारी। जय छत्तीसगढ़। वन्दे मातरम्।

भाजपा छत्तीसगढ़ आरोप पत्र समिति

श्री अजय चंद्राकर

संयोजक

श्री प्रेम प्रकाश पांडेय

सदस्य

श्री ओ पी चौधरी

सदस्य

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।।

श्रोत

- एबीपी न्यूज़. बस्तर में किसान हो रहे परेशान, कर्मचारीयों के हड़ताल से कई सरकारी लाभ लेने में दिक्कत. 15 जून 2023.
- हिंदुस्तान. छत्तीसगढ़ के किसान की आत्माहत्या, कर्ज-फसल खराब होने से था परेशान. 28 जुलाई 2023.
- आज तक. छत्तीसगढ़: 127 किसानों की जमीनों पर अफसरों का कब्ज़ा, HC ने रद्द किया अधिग्रहण. 4 दिसंबर 2018.
- Zee मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़. टॉप-5 बिजली कटौती वाले राज्यों में छत्तीसगढ़. 11 फरवरी 2022.
- दैनिक भास्कर. लॉकडाउन: पिछले महीने से तीन गुना ज्यादा बिजली बिल भेज रहा विभाग, जनता परेशान. अगस्त 2020.
- जनता से रिश्ता. बिजली कटौती लेकिन भरी बिल: जीएच नागरिक परेशान. 31 जुलाई 2023.
- दैनिक भास्कर. रायपुर में बेरोजगारों का बड़ा प्रदर्शन. मई 2023.
- एबीपी न्यूज़. रायपुर में शिक्षित बेरोजगारों पर पुलिस की बरसी लाठियां. 9 अप्रैल 2023.
- Indian Express. Chhattisgarh govt has debt burden of Rs 82,125 crore, 66.35% of total loans availed since 2000 was after Congress came to power: CM. 3 मार्च 2023.
- एबीपी न्यूज़. Chhattisgarh: इस जिले में गरीबों के राशन में लग रही सेंध, हजारों क्विंटल सरकारी चावल की हो रही कालाबाजारी. 18 फरवरी 2023.
- दैनिक भास्कर. आदिवासी इलाके के 25 हज़ार बच्चों की जान गई. जून 2023.
- अमर उजाला. Chhattisgarh: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के SNCU में 2 घंटे बिजली गुल, 4 बच्चों की मौत, अफसर बोले- मशीनें चालू थीं. 5 दिसंबर 2022.
- पत्रिका. छत्तीसगढ़ : अस्पताल में 4 बच्चों की मौत, BJP ने भूपेश सरकार पर बोला हमला, कहा- ठीक नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था. 5 दिसंबर 2022.
- न्यूज़बाजी. छत्तीसगढ़ में हर दिन गायब हो रहीं 33 बेटियां, 18 साल से कम आयु की बच्चियों का आंकड़ा भी चौंकाने वाला. 3 अगस्त 2023.
- जागरण. छत्तीसगढ़ में 16 लाख गरीब परिवार को रखा जा रहा है पीएम आवास से वंचित. 25 फरवरी 2023.
- जनता से रिश्ता. वन विभाग में करोड़ों रुपय का घोटाला, बिना कार्य योजना सरकारी ख़ज़ाने की लूट. 17 नवंबर 2021.
- नई दुनिया. मरवाही वनमंडल में फर्जी वन समिति बनाकर करोड़ों का घोटाला, दो रेंजर निलंबित. 7 मार्च 2023.
- दैनिक भास्कर. रेडी-टू-ईट फूड अब महिलाएं नहीं, मशीन बनाएगी:स्व सहायता समूह से छीना काम, 3 लाख परिवारों के सामने संकट; कवर्धा में सड़क पर उतरीं महिलाएं. अगस्त 2021.

- आज तक : 'तुम्हारे पिताजी ने कभी मुख्यमंत्री से बात की है', जब दिव्यांग लड़के पर भड़के CM बघेल, 29 दिसम्बर 2022
- ग्लिबस : भूपेश कर रहे युवाओं से सेट मुलाकात, दही के भोरहा म कपसा ल लील डारे : संतोष पांडेय. 7 अगस्त 2023
- भास्कर : छग सरकार के ढाई साल, BJP के 16 सवाल:भाजपा ने मांगा हिसाब; शराबबंदी, संपत्तिकर आधा करने, बेरोजगारी भत्ता देने के अधूरे वादे CM बघेल को याद दिलाए. 9 अगस्त 2021
- नव प्रदेश : BJP State Incharge : भूपेश सरकार पर लगाए ये आरोप, बोली- कांग्रेस फेल. 8 दिसम्बर 2021
- जनता से रिश्ता : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में रोष, घटिया साड़ी मिलने से नाराज. 28 फरवरी 2022
- अमर उजाला : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल जारी, वेतन समेत सात सूत्रीय मांगों पर डटे. 15 फरवरी 2023
- Indian Express : Chhattisgarh govt has debt burden of Rs 82,125 crore, 66.35% of total loans availed since 2000 was after Congress came to power: CM. 3 मार्च 2023
- डेली छत्तीसगढ़ : क़र्ज़माफ़ी का वादा कर प्रदेश को बना दिया कर्ज़दार - रमन. 17 जून 2021
- नई दुनिया : युवा मितान क्लब, गलत तरीके से पैसा बांटने का षड़यंत्र: चौधरी. 1 अक्टूबर2021
- भास्कर : नाराजगी:राजीव युवा मितान क्लब के खाते खुले, पैसे नहीं आए. 9 अगस्त 2022
- न्यूज़ लांड्री : छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हर दिन विज्ञापन पर खर्च किए लगभग 30 लाख रुपए. 13 दिसम्बर 2021
- अमर उजाला : 'जनता का पैसा खा गए भूपेश': केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले- काका नहीं, खा-खा हैं, हमारी सरकार आएगी तो जाएंगे जेल. 8 जून 2023
- पत्रिका : एमओयू के बाद जमीन तक देखने नहीं आए उद्योगपति. 20 अक्टूबर 2022
- सीजी न्यूज : "कृषि उत्पादन का बढ़ना देश की ताकत ... समस्या नहीं": अर्थव्यवस्था बचाने जनता की जेब में पैसा डालना होगा : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल. 20 दिसम्बर 2021
- द सूत्र : प्रमोशन पाने वालों को झटका. 27 नवम्बर 2022
- etv भारत : बघेल सरकार के खिलाफ सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन आज, विधानसभा घेराव की तैयारी.
- नई दुनिया : Mungeli News: वादा खिलाफी पर शिक्षकों ने निकाली भड़ास. 8 फरवरी 2023
- द सूत्र : सरगुजा में बच्चे आते खेलने , 2 हफ्ते से शिक्षक नहीं आ रहे. 3 अगस्त 2023
- एबीपी न्यूज़ : भविष्य से खिलवाड़! 11 हजार शिक्षकों की कमी से जूझ रहा छत्तीसगढ़ का यह संभाग, इन जिलों में 'राम भरोसे' कई प्राथमिक शालाएं. 6 अप्रैल 2023
- नवभारत टाइम्स : क्या छत्तीसगढ़ में 18 लाख युवा हैं बेरोजगार? BJP प्रदेश अध्यक्ष ने बेरोजगारी भत्ते पर उठाया बड़ा सवाल. 18 अप्रैल 2023

- नई दुनिया : उद्योगों में 1.15 लाख को मिलना था रोजगार, सिर्फ 7000 को मिल पाया, देखिए यह रिपोर्ट. 24 जुलाई 2023
- एबीपी न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों ने अचानक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया स्थगित, बोले- 'CM बघेल पर भरोसा है'. 2 अगस्त 2023
- नवभारत टाइम्स : संविदाकर्मियों के खिलाफ सरकार का सख्त एक्शन, हड़ताल पर बैठे 211 कर्मचारियों को किया बर्खास्त. 1 अगस्त 2023
- न्यूज़ 18 : 'छत्तीसगढ़िया ओलंपिक' का मैदान बना मौत का अखाड़ा! एक और कबड्डी खिलाड़ी की मौत, अब तक कितने. 17 नवम्बर 2022
- नवभारत टाइम्स : प्रैक्टिस से लौटते वक्त टूट गया पैर, तब से बेड पर... देश के लिए मेडल लाने वाले तलवारबाज को मदद की आस. 14 सितम्बर 2022
- नई दुनिया : आइएएस कर रहा राजा रघुराज सिंह क्रिकेट स्टेडियम का कबाड़ा. 13 नवम्बर2022
- जनता से रिश्ता : प्रदूषण से छग में हालात चिंताजनक. 24 नवम्बर 2022
- भास्कर : रिपोर्ट जारी:बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, सांस के मरीज बढ़ रहे. 9 अगस्त 2021
- नईदुनिया : दो सालों से आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं है कार्यकर्ता और सहायिका, खेलने व खाने में बीत रहा नौनिहालों का बचपन. 23 जून 2022
- पत्रिका : जानिए...छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद है खाली. 4 अप्रैल 2022
- नईदुनिया : सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे पर विधानसभा में हंगामा, मंत्री बोले- भूमाफिया पर यूपी की तरह नहीं चलेगा बुलडोजर. 26 जुलाई 2022
- राष्ट्रबोध : रायपुर : कोरोनाकाल में 50 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जे, कमरे बनाकर चौकीदार रख लिया....!!. 21 जनवरी 2021
- बोल छत्तीसगढ़ : मस्जिद के नाम पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, कब्जा हटाने व जुर्माना देने के सरकारी आदेश का उलंघन. 30 जून 2023
- नवभारत टाइम्स : सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर बीजेपी का हमला, पूर्व मंत्री ने थाने में किया हंगामा. 19 अप्रैल 2023
- लाइव हिंदुस्तान : भेंट मुलाक़ात है या बत्तमीज़ी और दांत. 9 मई 2022
- नवभारत टाइम्स : सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर बीजेपी का हमला, पूर्व मंत्री ने थाने में किया हंगामा. 19 अप्रैल 2023.

- हिंदुस्तान टाइम्स : तेंदुए को मारने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ में वन्यजीवों की तस्करी के आरोप में 5 अन्य गिरफ्तार. 14 फरवरी 2022
- रायपुर टॉप न्यूज़ : वन्यजीव हिरण के सिंग एवं खाल की तस्करी करते 4 तस्कर गिरफ्तार...बाजार में हिरण के सिंग एवं खाल की कीमत है लाखों में. 28 जून 2023
- एबीपी न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में बाघ सहित अन्य वन्यजीवों तस्करी मामले बड़ी कार्रवाई, 39 आरोपी गिरफ्तार. 21 जुलाई 2023
- एबीपी न्यूज़ : एससी-एसटी युवाओं ने बिना कपड़ों के किया प्रदर्शन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'ये बीजेपी का प्लान'. 18 जुलाई 2023
- डीएनए हिंदी: छत्तीसगढ़ में बिना कपड़ों के क्यों प्रदर्शन करने लगे लोग? जानिए क्या है वजह. 18 जुलाई 2023
- न्यूज़ 18 : छत्तीसगढ़ विधानसभा के सामने SC-ST वर्ग के युवाओं का नग्न प्रदर्शन, फर्जी जाति मामले में कार्रवाई की मांग. 18 जुलाई 2023
- IBC 24 : छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी, CSEB के रिटायर्ड कर्मचारी को लगाया इतने का चूना. 29 नवम्बर 2022
- जागरण : 20 हजार से अधिक लोग हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार, 22 साल का शातिर KYC अपडेट का देता था झांसा. 21 जनवरी 2023
- नईदुनिया : छत्तीसगढ़ में डेटिंग एप की आड़ में ठगी और ब्लैकमेलिंग का फैला जाल. 31 अगस्त 2021
- etv भारत : मासिक बाल पत्रिका किलोल की खरीदी पर रविंद्र चौबे और अजय चंद्राकर में जमकर बहस. 21 जुलाई 2023
- लल्लूराम : सदन में गरमाया बाल पत्रिका 'किलोल' की खरीदी का मुद्दा, अजय चंद्राकर ने दी जांच की चुनौती, कहा- मेरे समय में गड़बड़ी हुई तो मैं भी जाऊंगा जेल... 21 जुलाई 2023
- भास्कर : वर्चुअल मीट कार्यक्रम:राज्य स्तरीय मासिक पत्रिका किलोल का हुआ वर्चुअल मीट कार्यक्रम. 11 अगस्त 2021
- नईदुनिया : गरीब आदिवासी परिवार को 10 माह से नहीं मिल रहा राशन. 20 मई 2021
- tcp 24 न्यूज़ : सरपंच-सचिव की लापरवाही से बैगा आदिवासी परिवारों को नहीं मिल पा रहा राशन.
- पत्रिका : न तो राशन कार्ड बन पाया न मिल रहा मुफ्त राशन. 25 जुलाई 2023
- जनता से रिश्ता : चोर मचाए शोर, सूर्यकांत तिवारी के लगाए आरोपों पर रमन सिंह ने दिया बयान. 11 जुलाई 2022
- दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच : शराब घोटाले पर रमन का भूपेश पर वार, कहा : चोर मचाए शोर... 16 मई 2023
- एबीपी न्यूज़ : छत्तीसगढ़: बारदाने की कमी से परेशान किसान, कांग्रेस के पदाधिकारी भी उठा रहे सवाल. 2 दिसम्बर 2021
- टीवी 9 : छत्तीसगढ़ में कैसे होगी धान खरीद, नहीं मिला पूरा बारदाना तो सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी. 23 नवम्बर 2021

- The Hindu : Malnutrition deaths of Pando people highlight systemic failure. 13 अक्टूबर 2021
- नवभारत टाइम्स : कोरवा जनजाति के लोग हैं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, गांव में बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे. 16 जून 2021
- एबीपी न्यूज़ : राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र 'पहाड़ी कोरवा' के दो परिवार जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर, देखें तस्वीरें. 17 अक्टूबर 2022

अउ नइ सहिबो
बदल के रहिबो

Chhattisgarh News: सुकमा में पहली क्लास की छात्रा से रेप, जांच के लिए आठ लोगों की टीम गठित

Edited by मुनेश्वर कुमार | भाषा | Updated: 25 Jul 2023 2:42 pm